राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

आइसीसी को रास नहीं आया दस्तानों पर 'धौनी का बलिदान'
>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 2 अंक 361

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 8 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

इकोनॉमिक फोरम में बोलेंगी बरखेड़ी की युवा सरपंच

भोपाल : गांव में योजनाओं का अमल कैसे होता है, बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव की युवा सरपंच भक्ति शर्मा यह बात दुनिया को बताएंगी। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से उन्हें बुलावा आया है। भक्ति देश की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शुमार हैं। (पेज-13)

जागरण विशेष

जोर-शोर से गूंजेगा मां क्षीर भवानी का जयकारा

जम्मू : कश्मीर में आतंक व अलगाववादियों पर बरती जा रही सख्ती और केंद्र में मोदी-शाह की जोड़ी के होने से विस्थापित कश्मीरी पंडितों में नई उम्मीद जग गई है। कश्मीर वापसी की आस लेकर वे लोग हर साल यहां मां क्षीर भवानी के दर्शन को आते हैं, इस बार उत्साह अलग है। (पेज-13)

विश्वास.News

फर्जी है एमपी के बैतूल में खजाना मिलने का दावा ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 5

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

सैनिकों को अफसर बनाने को चेन्नई में खुलेगा प्रशिक्षण केंद्र

नई दिल्ली : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों को प्रशिक्षण देकर अफसर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। सैनिकों को कमीशंड अफसर बनने का मौका देकर सेना में करीब 11 हजार अफसरों की कमी को भी पूरा किया जा सकता है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

दक्षिण भारतीय राज्य केरल के तट पर आज पहुंचेगा मानसून

नई दिल्ली : भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि 24 घंटे में मानसून केरल तट पर पहुंच जाएगा। वैसे केरल में मानसून पहली जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार इसमें एक हफ्ते की देरी हुई है। इसके (मानसून) धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व की ओर रुख करने की बहुत संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 11

दुबई में बस दुर्घटना में 12 भारतीयों की मौत

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में एक बस रास्ते में लगे साइनबोर्ड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बारह भारतीयों समेत 17 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर ओमान में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां ईद की छुट्टियां मनाकर लौटे थे। बस में 31 यात्री थे।

क्रिकेट महाकुंभ

इंग्लैंड vs बांग्लादेश — दोपहर 3:00 बजे से — स्थान : कार्डिफ

अफगानिस्तान vs न्यूजीलैंड — शाम 6:00 बजे से — स्थान : टांटन

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

जगन ने एक साथ बनाए पांच डिप्टी सीएम

- 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल को आज दिलाई जाएगी शपथ
- पांच उप मुख्यमंत्रियों वाला देश का पहला राज्य बनेगा आंध्र प्रदेश

टाडेपल्ली स्थित अपने कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी। प्रेट्र

अमरावती, प्रेट्र/एएनआइ : सियासत में सबको साधने की नीति कोई नई नहीं है। इसके लिए राजनीतिक दल तरह-तरह के उपाय करते हैं। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सभी समुदायों को खुश करने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने पांच डिप्टी सीएम बनाने का एलान किया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कपू समुदाय से होंगे। शनिवार को 25 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाएगी। जगन मोहन ने अकेले 30 मई को सीएम पद की शपथ ली थी।

मुख्यमंत्री जगन मोहन ने शुक्रवार सुबह अपने आवास पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में पांच उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। 25 मंत्रियों में से आधे मंत्री भी इन्हीं समुदायों से होंगे। पांच उप मुख्यमंत्री बनाने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। चंद्रबाबू नायडू ने अपने कैबिनेट में पिछड़ा और कपू समुदाय के दो डिप्टी सीएम बनाए थे। वाइएसआरसीपी के विधायकों मोहम्मद मुस्तफा शेख और रामकृष्ण रेड्डी ने पांच डिप्टी सीएम बनाने के फैसले की पुष्टि की। विधायक दल की बैठक में जगन मोहन ने यह भी कहा कि उनके मंत्रिमंडल में कमजोर तबकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि रेड्डी समुदाय के दबदबे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए गए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। विधानसभा की 175 में से 151 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। जबकि लोकसभा की 25 में से 22 सीटें पार्टी के हिस्से में आई थीं। बैठक में जगन मोहन ने यह भी कहा कि ढाई साल बाद सरकार के कामकाज की समीक्षा के बाद कैबिनेट में बदलाव किया जाएगा।

एनपीए वसूली के नए दिशानिर्देश जारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आरबीआइ ने कहा, 30 दिनों के भीतर करनी होगी डिफॉल्ट की पहचान

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे कर्ज की वसूली शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी किये। इनके तहत बैंकों को डिफॉल्ट की पहचान करने के लिये 30 दिन का समय दिया जाएगा। नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

आरबीआइ ने शुक्रवार को कहा कि फंसे कर्ज की शीघ्र पहचान, सूचना देने और समयबद्ध ढंग से उसे वसूलने का फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के मकसद से नए दिशानिर्देश 'प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रैस्ड असेट' जारी किए गए हैं। इनके प्रभाव में आने के बाद पहले से चले आ रहे उपाय अमान्य हो जाएंगे। इनमें कॉरपोरेट कर्ज पुनर्संरचना योजना, वर्तमान दीर्घकालिक परियोजना लोन की पुनर्संरचना, रणनीतिक कर्ज पुनर्संरचना योजना (एसडीआर), एसडीआर के बाहर स्वामित्व में बदलाव, स्कीम फॉर सस्टेनेबल ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स (एस4ए) और ज्वाइंट लेंडर्स फोरम शामिल हैं।

ऐसा है नया फ्रेमवर्क : नए फ्रेमवर्क से उन बैंकों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, जिनका पूंजी आधार छोटा है। नया फ्रेमवर्क व्यवसायिक बैंकों, नाबार्ड, एग्जिम बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों और जमा राशि स्वीकार न करने वाली महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होगा। अब कर्जदाताओं को दिए कर्ज के 35 फीसद की प्रोविजनिंग करनी ही होगी। इनमें 20 फीसद की प्रोविजनिंग डिफॉल्ट होने के शुरुआती 180 दिनों के भीतर करनी होगी। अगर कर्जदाता 365 दिनों के भीतर किसी समाधान पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो उन्हें शेष 15 फीसद की प्रोविजनिंग करनी होगी।

डिफॉल्ट से पहले ही समाधान योजना पर काम पेज>>10

घाटी में 16 घंटे चली मुठभेड़ जैश के चार आतंकी ढेर

कार्रवाई ▶ ढेर आतंकियों में हथियार लेकर भागे दो एसपीओ भी शामिल

आतंकी ठिकाना बना मकान भी तबाह, भारी मात्रा में हथियार बरामद

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

मुठभेड़ में ढेर जैश के आतंकी एसपीओ सुलेमान और शब्बीर खान (ऊपर), आतंकी इमरान अहमद बट और आशिक हुसैन गनई (फाइल फोटो)

दक्षिण कश्मीर के पंजारन में मुठभेड़ स्थल पर सेना के जवान। एएनआइ

दक्षिण कश्मीर के पंजारन (पुलवामा) में गुरुवार देर शाम शुरू हुई मुठभेड़ 16 घंटे बाद शुक्रवार को जैश-ए-मुहम्मद के चार आतंकियों की मौत के साथ समाप्त हुई। सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को गुरुवार रात ही मार गिराया था, तीन अन्य शुक्रवार तड़के मारे गए। ढेर किए गए आतंकियों में दो पुलिस के भगोड़े एसपीओ हैं, जो दो दिन पहले ही हथियारों के साथ फरार हो गए थे। इस बीच, शोपियां व पुलवामा के विभिन्न हिस्सों में आतंकी समर्थक तत्वों और सुरक्षाबलों में हिंसक झड़पें हुईं। प्रशासन ने एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया है।

सेना की 44 आरआर, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के विशेष दस्ते को सूचना मिली थी कि जिला पुलिस लाइन से हथियारों के साथ फरार हुए एसपीओ सुलेमान खान और शब्बीर अहमद डार पंजारन गांव में छिपे जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों इमरान अहमद बट और आशिक हुसैन गनई के साथ मिलकर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इस पर संयुक्त दस्ते ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया।

आत्मसमर्पण करने को कहा, फिर भी चलाते रहे गोली : सुरक्षाबलों ने गुरुवार शाम जब आतंकी ठिकाना बने मकान को घेर लिया और आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी इमरान अहमद को गुरुवार शाम को ही मार गिराया था, जबकि दो भगोड़े एसपीओ और आशिक नामक एक अन्य आतंकी शुक्रवार तड़के मारे गए। आतंकियों की तरफ से अंतिम गोली सुबह करीब साढ़े चार बजे चली। इसी दौरान आतंकी ठिकाना बना मकान भी आग लगने से तबाह हो गया। सुरक्षाबलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद भी मिला है।

आतंकी समर्थकों ने लहराए जैश के बैनर : पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने चारों आतंकियों के शव उनके परिजनों के हवाले कर दिए हैं। चारों को उनके परिजनों ने शाम को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया। आतंकियों के जनाजे में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। कई युवकों ने जनाजे में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के बैनर लहराते हुए जिहादी नारे भी लगाए।

कराची में आइएसआइ छाप रही है भारतीय नोट

नई दिल्ली : पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ कराची में एक उच्च सुरक्षा वाले प्रिंटिंग प्रेस में दो हजार रुपये के भारतीय नोट छपवा रही है। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे (डी कंपनी) इन नकली नोटों को भारत के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने में लगे हैं। इस काम में काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अफसरों भी जुटे हैं। (पेज-11)

सैन्य प्रतिष्ठानों की वीडियो बनाते चार पाकिस्तानी जासूस पकड़े

जम्मू : सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में हवाई हमले से हताश पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ जम्मू संभाग में किसी बड़े सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसका पर्दाफाश पुलिस की ओर से चार जासूसों से पूछताछ के आधार पर किया गया है। यह मॉड्यूल आइएसआइ के कर्नल इफ्तिखार अहमद व हिज्ब कमांडर आमीर खान से संपर्क में था। आइएसआइ बड़े हमले को अंजाम ही नहीं देना चाहती है बल्कि ऊधमपुर, डोडा व कठुआ में आतंकवाद फिर से जिंदा करने की कोशिश में भी है। (पेज-6)

सोपोर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला, दो जवान घायल पेज>>6

वार्ता की बेकरारी

एक ही दिन इमरान और कुरैशी ने मोदी और जयशंकर को लिखे पत्र

इस्लामाबाद, प्रेट्र : आतंकवाद को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव, खाली खजाने और भारत के कड़े रुख से परेशान पाकिस्तान अब बातचीत की राह तलाश रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कश्मीर समेत सभी मसलों पर बातचीत की इच्छा जताई है। इमरान ने कहा है कि पाकिस्तान बातचीत से सभी विवादों को हल करना चाहता है। इमरान ने यह पत्र मीडिया में आई उस खबर के बाद लिखा है जिसमें कहा गया था कि एससीओ सम्मेलन के दौरान बिश्केक में पाक के साथ द्विपक्षीय मुलाकात से भारत ने इन्कार कर दिया है। बिश्केक में मोदी और इमरान भाग लेने जाएंगे। शुक्रवार को ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर को पत्र लिखकर सभी मसलों पर बातचीत की इच्छा का इजहार किया और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के प्रयासों के लिए प्रतिबद्धता जताई।

लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी को टेलीफोन पर बधाई देते हुए इमरान ने बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई थी, लेकिन मोदी ने जवाब में पहले हिंसा व आतंकवाद को खत्म कर भरोसा कायम करने को जरूरी बताया था। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें क्षेत्रीय विकास के लिए दोनों देशों के साथ काम करने को जरूरी बताया गया है। इससे दोनों देशों के लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत एकमात्र रास्ता बताया गया है।

पुलवामा हमले से बिगड़ी बात : फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। 26 फरवरी को वायुसेना के विमानों ने पाक में घुसकर बालाकोट स्थित शिविर पर हमला कर सैकड़ों आतंकी मार गिराए थे। अगले दिन पाक ने भी जम्मू-कश्मीर में जवाबी हमला करने की कोशिश की लेकिन भारतीय वायुसेना की सतर्कता के कारण उसके विमानों को भागना पड़ा था। इस तनाव को खत्म करने और साथ काम करने की इच्छा पाक पीएम ने 26 मई की टेलीफोन वार्ता में भी जताई थी।

अलीगढ़ में बच्ची की हत्या की जांच करेगी एसआइटी

- आरोपितों पर लगेगा रासुका, पुलिस ने अब तक दो आरोपितों को किया गिरफ्तार
- सेलिब्रिटीज के बाद अब राजनेताओं ने उठाया सवाल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़

अलीगढ़ के टप्पल में ढाई साल की बच्ची की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर देश भर में गुस्से का इजहार किए जाने के बाद डीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार ने शुक्रवार को जांच के लिए अलीगढ़ के एएसपी (देहात) मणिलाल पाटीदार के नेतृत्व में छह सदस्यीय एसआइटी गठित कर दी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी लगाया गया है, जो तीन हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। आरोपितों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और पॉक्सो एक्ट में भी कार्रवाई की तैयारी है। केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। क्रिकेट और फिल्म जगत की हस्तियों के बाद शुक्रवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में ट्वीट किया। राहुल ने कहा, ऐसी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, उप्र में जंगल राज है। बच्ची की हत्या और पुलिस लापरवाही पर सोशल मीडिया पर नौ जून को टप्पल चलो के आह्वान के संदेश चल रहे हैं।

क्यों हुई हत्या : टप्पल में एक मिस्त्री की ढाई साल की मासूम 30 मई को गायब हो गई थी। दो जून को उसका क्षत-विक्षत शव घर से 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर पर मिला था। मामले में पुलिस ने दो आरोपितों जाहिद और असलम को गिरफ्तार किया था। एसएसपी आकाश कुलहरि ने बताया कि आरोपित जाहिद ने बच्ची के पिता से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। 45 हजार लौट दिए थे। पांच हजार के लिए बच्ची के पिता ने जाहिद को अपमानित किया था। उसी का बदला लेने के लिए जाहिद ने साथी असलम के साथ मिलकर कपड़े से गला घोंटकर बच्ची की हत्या कर दी। शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया। बदबू आने पर शव को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। डीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार ने कहा कि स्थानीय पुलिस पर लग रहे लापरवाही के आरोप की भी जांच कराई जा रही है।

दरिंदे ने बेटी संग भी किया था दुष्कर्म : मुख्य आरोपित असलम ने 2014 में अपनी बेटी से दुष्कर्म किया था, जिस पर पत्नी ने ही केस दर्ज कराया था। आरोपित जेल से जमानत पर छूटा तो कस्बे में ही महिला से छेड़छाड़ का केस दर्ज हुआ। फिर उसने दिल्ली के गोकुलपुरी से बच्चे को अगवा किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपित को पकड़कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया था।

असंवेदनशील और गैरजिम्मेदार पुलिस : बालिका के गायब होने के बाद परिजन थाने पहुंचे, लेकिन रिपोर्ट अगले दिन दर्ज हो सकी। घटना के तीन दिन बाद शव मिला तो ग्रामीणों ने थाने के सामने शव रख प्रदर्शन किया। इस लापरवाही पर इंस्पेक्टर चाहल को लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बाद केपी सिंह चाहल, दारोगा सत्यवीर सिंह, अरविंद कुमार व शमीम अहमद, सिपाही राहुल यादव को निलंबित कर दिया गया था।

ये कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट

- शव क्षत-विक्षत हालत में था, जिसे कुत्ते खींच रहे थे। डॉक्टर जिस अंग को पकड़ते वह अलग हो रहा था।
- हत्या तीन-चार दिन पहले होने की वजह से शव में कीड़े पड़ चुके थे।
- बालिका का एक पैर तोड़ दिया गया था और दायां हाथ गायब था।
- बालिका के बाल जलाए गए थे। लग रहा था कि शव पर एसिड डाला गया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्ची की हत्या मामले में अलीगढ़ पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने अलीगढ़ के एसएसपी से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली।

सवर्ण आरक्षण के विरोध के कारण बिहार में राजद को हुआ नुकसान

पटना : लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की शिकस्त की वजहें तलाशी जा रही हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में दमदार लड़ाई की जमीन तैयार हो सके। प्रारंभिक तौर पर तीन सदस्यों क टीम ने जो खोजा है, उसके मुताबिक सवर्ण आरक्षण का विरोध राजद के नए नेतृत्व को सबसे ज्यादा भारी पड़ा है। गठबंधन के घटक दलों के आधार वोटरों की उदासीनता के साथ-साथ यादवों से अति पिछड़ी जातियों का बढ़ता फासला भी हार की वजह बना है। पड़ताल का मौखिक ब्योरा शनिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे रांची रवाना हो गए हैं। (पेज-4)

नीति आयोग को निरर्थक बता ममता ने बैठक में आने से किया इन्कार

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 15 जून को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। साथ ही कहा है कि एक संस्था के तौर पर यह 'निष्फल' है। राज्य की योजनाओं में मदद के लिए इसके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। ज्ञात हो, देश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मोदी 15 जून को नीति आयोग के संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे में मोदी को पत्र लिखकर ममता ने बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। (पेज-5)

ब्रिटिश पीएम टेरीजा मे ने छोड़ा कंजरवेटिव पार्टी का अध्यक्ष पद

लंदन : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। टेरीजा अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। टेरीजा ने बेक्जिट समझौते पर संसद में कई बार विफलता हाथ लगने के बाद पिछले महीने प्रधानमंत्रा का पद छोड़ देने का एलान कर दिया था। अब उनके उत्तराधिकारी पर ब्रेक्जिट मामले को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। टेरीजा के कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी में नए नेता के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। (पेज-11)

सामने आया सच

विदेश यात्रा से लेकर प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर से घूमने-फिरने जैसे शौक किए पूरे, कर्ज की तेज मंजूरी और वसूली में देरी के लिए अधिकारियों ने ली रिश्वत, एसएफआइओ द्वारा की गई जांच में सामने आई अधिकारियों की करतूत

आइएलएफएस अधिकारियों ने कर्ज बांटकर काटी चांदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : घपलेबाजी में बर्बाद हुई इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिडेट (आइएलएंडएफएस) के शीर्ष अफसरों ने रिश्वत के रूप में विदेश यात्रा, निजी हवाई यात्रा और विदेश के अपने मकानों में इंटेरियर डेकोरेशन करवाने जैसे शौक पूरे किए। कर्ज लेने वालों ने तेज मंजूरी और वसूली में देरी के लिए समूह के अफसरों की इसी प्रकार से खातिरदारी की।

सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) की जांच में ऐसे अनेक मामले सामने आए, जिसमें आइएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आइएफआइएन) के कर्जधारकों ने शीर्ष अधिकारियों को रिश्वत दिए। आइएफआइएन आइएलएंडएफएस की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इकाई है। जांच अधिकारियों को ई-मेल रिकॉड्स की जांच में आइएलएंडएफएस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों और शिवा ग्रुप के चेयरमैन सी शिवशंकरन के बीच गहरी मिलीभगत का पता चला। इस मामले में रिश्वत दे-देकर कर्ज को जारी रखा गया और वसूली में देरी की गई।

जांच के मुताबिक, आइएफआइएन ने शिवा ग्रुप की कंपनियों के साथ कर्ज देने और डिबेंचर्स में निवेश करने के 15 ट्रांजेक्शन किए। जिन कर्जों का भुगतान सिर्फ चार ट्रांजेक्शन में हो जाना चाहिए था, उन्हें 15 ट्रांजेक्शन में पूरा किया गया। शिवशंकरन ने कम से कम तीन अधिकारियों (रवि पार्थसारथी, विभव कपूर और हरि शंकरन) की अनेक प्रकार से खातिरदारी की। इनमें विदेश भ्रमण, निजी जेट और हेलीकॉप्टर से घूमना-फिरना, रिजॉर्ट्स की बुकिंग और ब्रसेल्स (बेल्जियम) के कुछ फ्लैट्स में इंटेरियर डेकोरेशंस की व्यवस्था करना शामिल हैं। ऐसी खातिरदारियों के बदले तीनों अधिकारियों ने आइएफआइएन की लोन देने और उनकी वसूली से संबंधित निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित किया।

एसएफआइओ ने इस मामले में पिछले सप्ताह अपना पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। आरोप पत्र के मुताबिक, शिवा ग्रुप के हर मामले पर पकड़ रखने वाले शिवशंकरन के रवि पार्थसारथी और हरि शंकरन के साथ निजी ताल्लुकात थे। उनके समूह को पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन दिए गए, जबकि पुराने लोन का कायदे से एनपीए घोषित कर दिया जाना चाहिए था। जांच अधिकारियों ने कहा, आइएफआइएन और शिवा ग्रुप की कंपनियों के बीच धूर्ततापूर्ण ट्रांजेक्शन से कंपनी की बेहतर तस्वीर पेश की जाती रही और इस प्रक्रिया में आइएफआइएन के कर्जदाताओं का बंटाधार हो गया।

आइएलएफएस के डिफॉल्ट्स के बाद मामला हुआ था उजागर : आइएलएंडएफएस समूह के घोटाले का मामला पिछले साल तब उजागर हुआ, जब नकदी की किल्लत के कारण समूह की कंपनियों ने एक-के-बाद-एक कई डिफॉल्ट्स किए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को आइएलएंडएफएस समूह का नया बोर्ड नियुक्त करना पड़ा। मार्च 2018 को आइएलएंडएफएस समूह पर 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था।

पहले आरोप पत्र में 30 इकाइयों व व्यक्तियों पर गंभीर आरोप : एसएफआइओ ने इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। यह आरोप पत्र मुंबई की एक विशेष अदालत में दाखिल किया गया है। इसमें 30 इकाइयों और व्यक्तियों पर वित्तीय हेराफेरी सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र दाखिल करने से पहले एसएफआइओ ने करीब 400 इकाइयों के खातों की जांच की। जांच एजेंसी ने आइएलएंडएफएस के कार्यालयों से जब्त किए गए कंप्यूटरों और लैपटॉप्स के आंकड़ों और आइएलएंडएफएस के सर्वर्स से निकाले गए ई-मेल की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने आरबीआइ की निरीक्षण रिपोर्ट्स, बैठक के ब्योरे, सरकार द्वारा नियुक्त आइएलएंडएफएस बोर्ड की मूल्यांकन रिपोर्ट्स तथा अन्य डॉम्यूमेंट्स भी खंगाले।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

9 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2018
from various programs of VISION IAS

1 AIR KANISHAK KATARIA
2 AIR AKSHAT JAIN
3 AIR JUNAID AHMAD
4 AIR SHREYANS KUMAT
5 AIR SRUSHTI JAYANT DESHMUKH

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2020
DELHI 13 June | 1 PM

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- निबंध लेखन - शैली, PT 365, Mains 365, सीसैट कक्षाएं
- मुख्य परीक्षा, निबंध, PT, सीसैट टेस्ट सीरीज

ओपन सेशन
सिविल सेवा परीक्षा सामान्य अध्ययन 2020 की तैयारी कैसे करें
www.visionias.in पर साइन अप करें
9 JUNE 1 PM

VisionIAS Classroom, 2154, Second Floor, kingsway camp, outram Lane, near syndicate bank, Delhi

DELHI • 635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar
• 2nd Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066, 9650617807

JAIPUR 9001949244 | PUNE 8007500096 | HYDERABAD 9000104133 | AHMEDABAD 9909447040 | LUCKNOW 8468022022

339 नए मोहल्ला क्लीनिकों का निर्माण होगा राजधानी में मौजूदा वित्त वर्ष में। आउटकम बजट की रिपोर्ट में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 8 जून 2019

न्यूज गैलरी

मानहानि मामले में आतिशी व सुशील गुप्ता को जमानत

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मानहानि के मामले में आप नेता आतिशी, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार को अदालत में पेश होने के बाद जमानत दे दी। अदालत ने सभी को 10-10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। वहीं, शुक्रवार को पेश नहीं होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 जुलाई को पेश होने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य आप नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी। बब्बर ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल और उनके सहयोगी नेताओं ने गलत आरोप लगाए हैं कि भाजपा ने दिल्लीवासियों के वोट कटवा दिए हैं। उनका कहना था कि ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर भाजपा और इसके नेताओं की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। (जासं)

बच्चों से यौन अपराध करने वाले उदारता के योग्य नहीं

नई दिल्ली : चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को निचली अदालत से मिली 10 साल की सजा को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। साथ ही हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि बच्चों का यौन शोषण करने वाले लोग मानसिक विकृति का शिकार हैं। ऐसे लोग किसी भी तरह की उदारता के योग्य नहीं हैं। नवंबर 2013 में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि भाई दूज के दिन उनकी चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने महिला के मुंहबोले भाई को गिरफ्तार किया था। उसे मई 2015 में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने उसे गलत केस में फंसाया है। (जासं)

हाई कोर्ट का आदेश लागू कराने में हो रही दिक्कत

नई दिल्ली : एक दवा कंपनी को दिया गया 1.4 लाख पौधे लगाने का आदेश लागू कराने में पर्यावरण विभाग को दिक्कत हो रही है। हाई कोर्ट में दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय रिज की जमीन इतने पौधे लगाने के लिए सक्षम नहीं है। यहां की मिट्टी भी पौधरोपण के लिए उपयुक्त नहीं है। हाई कोर्ट में एक दवा कंपनी ने दूसरी के खिलाफ शिकायत की थी। इसमें कहा था कि दूसरी कंपनी उनके ब्रांड के नाम पर दवा बेच रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कंपनी पर 80 लाख रुपये जुर्माना लगाया था और कहा था कि यह पैसा हरियाली बढ़ाने पर खर्च होना चाहिए। अब पर्यावरण विभाग ने कहा कि केंद्रीय रिज पौधरोपण के लिए उपयुक्त नहीं है। विभाग ने हाई कोर्ट से मांग की है कि पौधरोपण के लिए जगह बदलने की मंजूरी दी जाए। (जासं)

'आयुष्मान भारत' योजना दिल्ली में नहीं लागू होगी

इन्कार ▶ सीएम बोले, हमारे पास केंद्र से दस गुना बड़ी स्वास्थ्य योजना

केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के पत्र का दिया जवाब

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आयुष्मान भारत योजना लागू करने से दिल्ली सरकार ने फिर इन्कार कर दिया है। इसे लागू करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के तीन जून को लिखे पत्र का शुक्रवार को दिए जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही।

केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से 10 गुना बड़ी और व्यापक दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना है। इसमें वे सारी बातें हैं जो आयुष्मान भारत योजना में हैं। उन्होंने लिखा है कि आयुष्मान योजना में दिल्ली की मात्र 10 फीसद से भी कम आबादी लाभार्थी है। जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, फ्रिज या फोन हैं, वे लाभार्थी नहीं हैं। 10 हजार महीना से अधिक आय वाले लाभार्थी नहीं हैं। केजरीवाल ने कहा है कि आयुष्मान योजना में केवल पांच लाख रुपये तक इलाज होगा, जबकि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना में राज्य का हर व्यक्ति लाभार्थी है। इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, चाहे वह 30 लाख रुपये ही क्यों न हो। इलाज के खर्च की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। पत्र में केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा है कि यदि आयुष्मान योजना में कोई ऐसी बात जो दिल्ली स्वास्थ्य योजना में नहीं है तो बताएं, उसे हम अपनी योजना में शामिल कर लेंगे।

ट्विटर पर भिड़े उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ट्विटर पर भिड़ गए। सिसोदिया ने कहा कि जो 10 हजार रुपये से अधिक कमाता है तो वह आयुष्मान योजना से बाहर है। उपमुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली के लोगों का हक छीन कर अब जले पर नमक मत छिड़को। आयुष्मान भारत योजना तो दिल्ली में लागू हो कर रहेगी।

दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पत्र लिखकर दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने को कहा है। इस पर सिसोदिया ने ट्वीट किया कि अगर आपके घर में कोई एक सदस्य 10 हजार रुपये प्रति माह से ज्यादा कमाता है तो आपका परिवार आयुष्मान योजना से बाहर है। दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार न्यूनतम मजदूरी ही 13 हजार से ज्यादा देती है। फिर इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, सिर्फ बीमा कंपनियों को? इस पर विजेंद्र गुप्ता ने लिखा कि दिल्ली सहित देश के 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोग इस योजना में कवर हैं। छह माह बाद लोग आपको सत्ता से बाहर करेंगे, फिर आयुष्मान भारत योजना हम दिल्ली में लागू करेंगे।

दिल्ली के संदर्भ में आयुष्मान का स्कोप बहुत कम : सिसोदिया : मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें आयुष्मान योजना से दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास फोन, फ्रिज, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तीन कमरे का घर है, उसे इसका फायदा नहीं मिलेगा। जबकि दिल्ली में जो योजना है वह सब पर लागू है। दिल्ली के संदर्भ में इस योजना का स्कोप बहुत कम है। गत तीन जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने पत्र लिख कर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि इस योजना को दिल्ली में भी लागू करें।

गवर्नेंस रिफॉर्म में बेस लाइन का काम करेगा आउटकम बजट

दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के आउटकम बजट की कॉपी जारी करते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (बीच में) और अन्य। जागरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

अगर आप पूछें कि पिछले साढ़े चार साल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि आउटकम बजट का सफलतापूर्वक संचालन हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सचिवालय में आउटकम बजट की रिपोर्ट 2019-20 रिलीज के मौके पर यह बात कही। इस रिपोर्ट में आउटकम बजट के नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यह आसान काम नहीं था कि किसी विभाग को पैसा देते वक्त ये पूछा जाए कि आप इस पैसे का क्या करोगे? पहले ये सवाल आता था कि हमें स्कूल में लाइब्रेरी बनानी है और किताबें खरीदनी हैं। आप हमें 10 करोड़ रुपये दे दीजिए। इस पर प्लानिंग डिपार्टमेंट का ये पूछना तो ठीक था कि कितनी लाइब्रेरी खोलोगे। लेकिन अब ये भी पूछा जाता है कि इन किताबों को कितने बच्चे पढ़ेंगे। कितने बच्चों को इसका लाभ होगा। लाइब्रेरी बन जाने के बाद भी पूछा जाता है कि इससे कितने बच्चों को लाभ मिला है।

सिसोदिया ने कहा कि देश में आज से 10-20 साल बाद जब भी गवर्नेंस रिफॉर्म की बात होगी तो ये आउटकम बजट बेस लाइन की तरह उपयोग होगा। हम इसे दिल्ली में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि साढ़े चार साल पहले जब दिल्ली के लोगों ने हमें चुनकर भेजा था तो इसलिए नहीं भेजा था कि आप बहुत अच्छे मैनेजर बन सकते हो। लोग लीडरशिप चाहते थे। ऐसी लीडरशिप जो दिल्ली को आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि आज मैं आउटकम बजट रिपोर्ट में सरकार की हर योजना, हर प्रोग्राम का जनता को कैसे और कितना लाभ हुआ, उसका सटीक आंकड़ा है। इस मौके पर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि 2018 में दिल्ली सरकार ने 1900 इंडीकेटर्स या सूचकों पर आधारित अपनी पहली आउटकम रिपोर्ट पेश की थी। आज हम 3000 सूचकों पर आधारित आउटकम रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं।

आरएमएल में बनेंगे 900 बेड के दो सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक

रणविजय सिंह, नई दिल्ली : केंद्र सरकार के आरएमएल अस्पताल का कायाकल्प होगा। जल्द अस्पताल में अलग-अलग दो सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसकी कुल बेड क्षमता 900 होगी। इस परियोजना को केंद्र सरकार के सौ दिन की कार्ययोजनाओं में शामिल किया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सौ दिन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में चार परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें इन दोनों सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का निर्माण शामिल है। इन दोनों ब्लॉकों का निर्माण पूरा होने पर अस्पताल में 2369 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही दोनों सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। यहां हृदय, न्यूरो, किडनी, यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों के इलाज के अलावा कैंसर सर्जरी की भी सुविधा होगी। इससे अस्पताल में सर्जरी की वेटिंग कम होगी। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को इलाज का बेहतर विकल्प मिल पाएगा। मौजूदा समय में अस्पताल में 1469 बेड हैं।

मरीजों की भीड़ के लिहाज से यह दिल्ली में एम्स व सफदरजंग अस्पताल के बाद तीसरा सबसे व्यस्त अस्पताल है। अस्पताल में मरीजों की तुलना में सुविधाएं कम पड़ रही हैं। लिहाजा लंबे समय से अस्पताल के विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके मद्देनजर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाने की योजना है, जो लंबे समय से अधर में फंसी थी। अब अस्पताल में 600 बेड के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। इसके निर्माण पर करीब 500 करोड़ खर्च आएगा।

एक ही नाम का फायदा उठाकर महिला ने निकाले लाखों रुपये

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आमने-सामने रहती हैं पीड़ित और आरोपित महिला
- डिलीवरी ब्वॉय की गलती से आरोपित महिला को मिल गई थी चेकबुक

एक महिला के बैंक खाते से लाखों रुपये निकल गए। पुलिस के पास मामला पहुंचा और उसने जांच शुरू की। इसमें पता चला कि आरोपित और पीड़ित महिला का नाम एक ही है। बैंक की ओर से चेकबुक जारी हुई थी, जो डिलीवरी ब्वॉय की गलती से आरोपित महिला को मिल गई थी। आरोपित ने खाते से कई बार रुपये निकाले। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एंटो अल्फांस ने बताया कि 23 मई को मोहन गार्डन थाने में विपिन गार्डन निवासी एक महिला ने शिकायत दी। इसमें बताया कि जब वह खाते को अपडेट कराने बैंक पहुंचीं तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से तीन लाख 62 हजार 254 रुपये निकाल लिए गए हैं। जांच में पुलिस ने बैंक से संपर्क किया और खाते को ब्लॉक कराया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़ित महिला के नाम से बैंक की ओर से चेकबुक जारी की गई थी। कोरियर ब्वॉय ने गलती से यह चेकबुक फरवरी में आरोपित महिला को सौंप दी। आरोपित व पीड़ित महिला दोनों एक-दूसरे को जानती थीं। दोनों का घर आमने-सामने है। आरोपित महिला ने किसी तरह से पीड़ित महिला के हस्ताक्षर के बारे में पता किया और इसकी नकल करनी शुरू कर दी। जब महिला को लगा कि अब वह खाताधारी महिला के हस्ताक्षर की नकल कर लेती है, तब उसने 50 हजार रुपये का चेक जारी किया। बैंक की ओर से जब यह रकम जारी कर दी गई तो महिला ने इसी तरह से चार बार और निकासी की। इस बीच आरोपित महिला ने खाताधारी महिला के नाम से जारी एटीएम कार्ड भी पा लिया। महिला ने चालाकी करते हुए बैंक में खाताधारी महिला का मोबाइल नंबर बदलकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया। इसके बाद एटीएम कार्ड से भी पैसे की निकासी की जाने लगी। पूछताछ में आरोपित महिला ने बताया कि जब उसे पता चला कि उसका भेद अब खुल चुका है तो खुद को बचाने के लिए वह ठगी की पूरी रकम बैंक खाते में जमा कराने पहुंची थी।

दुष्कर्म की शिकायत से पहले की 529 कॉल, आरोपित बरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित युवक को इस आधार पर बरी कर दिया कि शिकायत दर्ज कराने से पहले पीड़िता ने आरोपित को 529 बार कॉल किया था। न्यायमूर्ति मनमोहन व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने एक विश्वविद्यालय में महिला प्रोफेसर के बयानों में विरोधाभास के चलते उसे अविश्वनीय करार दिया। पीठ ने सवाल उठाया कि घटना के एक महीने के बाद महिला ने रिपोर्ट दर्ज क्यों कराई। उसने चिकित्सकीय जांच से इन्कार क्यों किया और घटना के बाद आरोपित को 529 बार फोन कॉल क्यों किया।

आरोपित और महिला प्रोफेसर की मुलाकात सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हुई थी। महिला का आरोप था कि नोएडा स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आइआइएम) से उसे दिसंबर 2016 में सेमिनार में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। आरोपित ने एक होटल में दवाइयां खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं, आरोपित ने आइआइएम से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी को अदालत को बताया कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है, उस दिन राजपत्रित अवकाश था और कोई सेमिनार नहीं था।

निचली अदालत ने आरोपित को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ महिला हाई कोर्ट गई थी। उसका कहना था कि निचली अदालत ने तथ्यों की अनदेखी की। महिला ने हाई कोर्ट में कहा कि मर्जी के बगैर संबंध बनाना दुष्कर्म है और आरोपित को इसे गलत साबित करना होगा। वहीं, पीठ ने महिला की दलील को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा तब होता है, जब शारीरिक संबंध बना हो और मेडिकल जांच हुई हो। महिला द्वारा चिकित्सा जांच से इन्कार करने से साफ है कि शारीरिक संबंध नहीं बने। पीठ ने कहा कि महिला ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने से पहले 16 दिसंबर 2016 से 29 जनवरी 2017 के बीच आरोपित को 529 बार कॉल किया था। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि महिला का होटल के एक कमरे में दुष्कर्म हुआ और उसने न तो इसका विरोध किया और न ही शोर मचाया, जबकि होटल में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था होती है। महिला आसानी से कमरे से बाहर आकर पुलिस को फोन कर सकती थी या फिर होटल स्टाफ से मदद मांग सकती थी। इतना ही नहीं गंभीर घटना के बाद महिला ने आरोपित को उसे शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर छोड़ने की अनुमति दी और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक महीने तक इंतजार किया। ऐसे में महिला के आरोपों में विरोधाभास है और आरोपित को इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती।

जस्टिस पटेल बने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति पटेल को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति पटेल झारखंड उच्च न्यायालय में नियुक्त थे। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के लिए 60 पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से 24 पद रिक्त हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य और दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद न्यायमूर्ति पटेल अपनी पत्नी और अन्य परिजनों के साथ। ध्रुव कुमार

किराये में बुजुर्गों-छात्रों को मिल सकती है छूट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- मेट्रो के सभी स्टेशनों पर बायोमीट्रिक आधारित फेयर कलेक्शन गेट लगाने की है योजना

मेट्रो में किराये को लेकर आने वाले दिनों में सियासत तेज हो सकती है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से संकेत मिल रहे हैं कि मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर की दिल्ली सरकार की योजना से पहले बुजुर्गों और छात्रों को किराये में छूट मिल सकती है। इस दिशा में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने उसी समय कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था, जब फरवरी में मेट्रो स्टेशनों पर बायोमीट्रिक आधारित एएफसी (ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन) गेट लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो में मुफ्त सफर या छूट का प्रावधान तकनीकी रूप से लागू करने में नौ माह तक का समय लग सकता है। यदि दिल्ली सरकार महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त सफर के लिए सब्सिडी योजना को मंजूरी देकर फाइल आगे बढ़ाती है, तब भी इस योजना को मेट्रो बोर्ड से स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेट्रो से संबंधित नीतिगत मामलों पर बोर्ड की मंजूरी जरूरी होती है। बोर्ड में दोनों सरकारों (केंद्र व दिल्ली सरकार) के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड से यह प्रस्ताव पास होना आसान नहीं है। अभी तक तो डीएमआरसी के अधिकारी यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा कैसे दी जाए। मेट्रो में दोगुना किराया वृद्धि पर विवाद बढ़ने पर पिछले साल केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने बुजुर्गों व छात्रों को किराये में कुछ छूट देने के लिए डीएमआरसी को नीति तैयार करने को कहा था।

फरवरी में डीएमआरसी 14.51 करोड़ की लागत से सभी मेट्रो स्टेशनों पर बायोमीट्रिक आधारित एएफसी गेट लगाने के लिए टेंडर जारी कर चुका है। इस गेट पर अंगुली पंच कर किराया भुगतान हो सकेगा। साथ ही इस तकनीक से यात्रियों की पहचान संभव हो पाएगी। इसलिए बायोमीट्रिक एएफसी गेट लगाने की प्रक्रिया शुरू होने पर ही डीएमआरसी ने कहा था कि यह तकनीक आने वाले दिनों में मेट्रो के किराये में छूट का प्रावधान लागू करने में मददगार बनेगी।

बताया जा रहा है कि डीएमआरसी ने यह पहल बुजुर्गों व छात्रों को रियायत देने के मकसद से की थी। केंद्र सरकार भी इस योजना को पहले लागू करना चाहेगी। चर्चा इस बात की भी है कि किराये पर सियासत बढ़ने पर किराया निर्धारण समिति का गठन भी हो सकता है। वैसे भी पूर्व किराया निर्धारण समिति मेट्रो में हर साल किराया भुगतान का सुझाव दे चुकी है। ऐसे में दोबारा समिति का गठन होता है तो चुनाव के बाद अगले साल बुजुर्गों व छात्रों को किराये में छूट का प्रस्ताव आ सकता है।

पिंक टोकन व स्मार्ट कार्ड लाने में भी लगेगा वक्त : बताया जा रहा है कि डीएमआरसी ने पिंक टोकन व स्मार्ट कार्ड के जरिए यह सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव सरकार को दिया है। लेकिन अधिकारी कहते हैं कि पिंक टोकन व स्मार्ट कार्ड का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यदि कोई महिला यात्री पिंक टोकन या स्मार्ट कार्ड लेकर अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल के लिए दे दे तो उसकी निगरानी आसान नहीं होगी। साथ ही नए टोकन उपलब्ध होने में समय लगेगा क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में ही तीन से चार माह का समय लग जाएगा। इसके बाद भी नया टोकन व स्मार्ट कार्ड उपलब्ध होने में वक्त लग सकता है।

पानी के लिए मारामारी

ये फोटो सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की है। पेयजल की किल्लत के चलते यहां एनडीएमसी के टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। शुक्रवार को ऐसे ही एक टैंकर से पानी भरते लोग। प्रेट्र

मिशन एडमिशन

ईडब्ल्यूएस कोटे के छात्रों को कट ऑफ में छूट मिलने या नहीं मिलने पर कोई फैसला नहीं हुआ, हालांकि फीस भुगतान में उन्हें छूट मिली है

इस बार कट ऑफ में 0.5 फीसद वृद्धि की संभावना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी कॉलेज में आयोजित ओपन डे में छात्रों ने अपनी समस्याएं शिक्षकों के सामने रखीं। यह आयोजन दैनिक जागरण की मीडिया पार्टनरशिप में हुआ था। इस मौके पर इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेल के डिप्टी डीन डॉ. बिपिन तिवारी ने बताया कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तहसीलदार रैंक से ऊपर के अधिकारियों की ओर से बनाए जाने पर स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार 12वीं के नतीजे पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन रहे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि 0.5 फीसद कट ऑफ बढ़े। अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के छात्रों को कट ऑफ में भी छूट मिलेगी या नहीं। हालांकि फीस भुगतान में उन्हें छूट मिली है।

इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश गिरि ने कॉलेज की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। राजधानी कॉलेज की एलुमिनी व अकादमिक परिषद की पूर्व सदस्य डॉ. गीता भट्ट ने बताया कि 12वीं के बाद कॉलेज में दाखिले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती विषय व कॉलेज के चुनाव को लेकर आती है। ऐसी परिस्थिति में छात्र सबसे पहले अपने विषय को प्राथमिकता दें और बाद में कॉलेज को, क्योंकि आज के समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 कॉलेजों में मौजूद सभी प्रोफेसर सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे में कॉलेज के चलते विषय से कोई समझौता नहीं करें। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्टूडेंट वेलफेयर की डिप्टी डीन डॉ. हेना सिंह ने बताया कि डीयू दाखिले से जुड़ी किसी भी सटीक जानकारी के लिए डीयू.एसी.इन की ही मदद लें। स्पोर्ट्स कोटे के ट्रायल व प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स की परीक्षा तिथि अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। ऐसे में नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहे। खास बात यह है कि इस बार दाखिले के दौरान चरित्र प्रमाणपत्र व माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। फीस जमा करने के बाद अपना दाखिला फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। ओपन डे के दौरान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट व ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर छात्रों में मन में काफी संशय था। उनका कहना था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा ये सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। 14 जून दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। सर्टिफिकेट नहीं मिला तो वे आरक्षित कोटे का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही ईडब्ल्यूएस वर्ग के मानदंड क्या है। इसके अलावा छात्रों ने यह भी जानना चाहा कि यदि 12वीं में उन्होंने जिन विषयों का अध्ययन किया है और यदि इसमें से ही किसी विषय में ऑनर्स करना चाहे तो क्या कट ऑफ में उन्हें कोई छूट मिलेगी।

जाकिर हुसैन कालेज में ओपन डे कार्यक्रम में दाखिला संबंधित सवाल पूछती छात्रा। जागरण

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू : दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के दौरान ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने को लेकर इन दिनों छात्रों को काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। कई छात्रों को तो निराश होकर वापस लौटना पड़ा है। पश्चिमी जिला उपायुक्त अजीमुल हक ने बताया कि दिल्ली सरकार की ओर से चार जून को ही दिशानिर्देश मिले हैं। पांच जून को ईद के कारण छुट्टी थी। छह जून से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी ऑनलाइन सुविधा शुरू नहीं हुई है। ऐसे में छात्रों के आवेदन हाथोंहाथ लिए जा रहे हैं। बाद में सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट तैयार होने में करीब दो हफ्ते का समय लगेगा।

छात्रवृत्ति के लिए मांगे जाएंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की तरफ से इस वर्ष एक विशेष फैसला किया गया है। इसके जरिए अकादमिक सत्र 2019-20 में ऐसे छात्रों को फीस के बराबर छात्रवृत्ति देने का निर्णय किया है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या दोनों बेरोजगार हैं। इसके अलावा घर के कमाने वाले की किसी कारण मौत हुई है तो उस परिवार के बच्चे को आधी फीस के बराबर छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस मामले में दाखिला प्रक्रिया खत्म होने के बाद ऐसे छात्रों से आवेदन मांगे जाएंगे।

इस मामले में डीयू के स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। डीयू के स्टूडेंट वेलफेयर के डीन व दाखिला समिति के अध्यक्ष प्रो. राजीव गुप्ता ने कहा कि इस तरह की पहल से इन बच्चों को काफी फायदा होगा। हम डीयू की दाखिला प्रक्रिया के खत्म होने के बाद ऐसे छात्रों से आवेदन मांगेंगे। छात्रों से यह आवेदन ऑनलाइन भी मांगे जा सकते हैं। इन आवेदनों में छात्रों को इसका प्रमाण भी देना होगा।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते से यह आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस मामले में अकादमिक परिषद के सदस्य प्रो. रसाल सिंह ने कहा कि डीयू की दाखिला समिति ने अपनी समावेशी दृष्टि के तहत कई निर्णायक पहल की है। इसमें जिन छात्रों के माता-पिता बेरोजगार हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इसके साथ ही जिनके परिवार में कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।

30 जून से छह जुलाई के बीच होंगी प्रवेश परीक्षाएं : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की तरफ से स्नातक पाठ्यक्रम, पीजी व एमफिल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इन सभी की प्रवेश परीक्षाएं 30 जून से छह जुलाई के बीच होंगी। डीयू के 11 स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर होता है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस), बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इंवेस्टमेंट एनालिसिस (बीबीए एफआइए) जैसे स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं होती हैं।

12 जून को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी 57 मंत्रियों को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें सरकार के अगले पांच साल की कार्ययोजना पर चर्चा होने की संभावना है।

न्यूज गैलरी

कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा को मिला सेवा विस्तार

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पीके सिन्हा अगले तीन महीने तक कैबिनेट सचिव बने रहेंगे। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने तीन माह के लिए उन्हें सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। सिन्हा का कार्यकाल अगले बुधवार को समाप्त होने जा रहा था। सिन्हा को सेवा विस्तार मिलने से गृह सचिव राजीव गौबा के कैबिनेट सचिव बनाए जाने की अटकलों पर विराम लग गया है। सिन्हा को पहली बार 13 जून 2015 को कैबिनेट सचिव बनाया गया था। दो साल के तय कार्यकाल के समाप्त होने के बाद उन्हें दो बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है। यह तीसरा सेवा विस्तार है। (जाब्यू)

पीके सिन्हा फाइल

तीसरी बार बढ़ी सीवीसी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि

नई दिल्ली : योग्य आवेदकों की कमी के कारण सरकार को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के शीर्ष पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि लगातार तीसरी बार बढ़ानी पड़ी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कार्मिक मंत्रालय ने मार्च अंत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के पदों को भरने की कवायद शुरू की थी। एक आदेश के अनुसार, इन पदों के लिए मंत्रालय को आवेदन भेजने की अंतिम तिथि एक मई थी। इसे पहली बार बढ़ाकर 22 मई और दूसरी बार छह जून कर दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि अब 17 जून कर दी गई है। मौजूदा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन का कार्यकाल इस महीने पूरा हो जाएगा। (प्रेट्र)

सीसीए को कैडर रिव्यू प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश

नई दिल्ली: सभी केंद्रीय समूह 'ए' सेवाओं में लंबित कैडर रिव्यू पर विचार करते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कैडर नियंत्रण अधिकारियों (सीसीए) से प्रक्रिया में तेजी लाने और जून के आखिर तक प्रस्ताव सौंपने को कहा है। कुछ मामले तो 40 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। यह निर्देश 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के चार दिनों बाद जारी किया गया है। 27 मई को जारी पत्र में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव सी. चंद्रमौली ने सीसीए को निर्देश दिया है कि पूरा कैडर रिव्यू प्रस्ताव 30 जून तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास पहुंच जाना चाहिए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद पता चला है कि 34 केंद्रीय समूह ए सेवा या कैडर को 2018 तक रिव्यू किया जाना था और 11 सेवाओं में यह यथाशीघ्र किया जाना है। (आइएएनएस)

कूटनीति ▶ थिंपू पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएंगे दोनों देश

भूटान के साथ नजदीकी पर जोर

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूटान से शुरू किए थे अपने विदेशी दौरे

अपनी पहली विदेश यात्रा पर शुक्रवार को भूटान पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री डॉ. लोते शेरिंग से मुलाकात की। प्रेट्र

थिंपू, प्रेट्र : विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा पर शुक्रवार को भूटान पहुंचे एस. जयशंकर ने वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री डॉ. लोते शेरिंग से द्विपक्षीय मामलों पर महत्वपूर्ण बातचीत में दोनों नेताओं ने विकास कार्यों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। ऊर्जा के क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया गया। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मौके पर भूटानी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और शुभकामनाएं भी दीं। जयशंकर दो दिनों के भूटान दौरे पर हैं।

मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री शेरिंग ने पद संभालने के बाद जयशंकर के सबसे पहले भूटान आने के लिए खुशी जाहिर की। उन्होंने अपनी भावनाएं ट्विटर के जरिये व्यक्त कीं। जवाब में डॉ. जयशंकर ने भी भूटानी प्रधानमंत्री से मुलाकात पर खुशी जाहिर की और उसे सद्भावनापूर्ण बताया। जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश देकर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया है कि निकट सहयोगी भूटान से विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर की कई मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता हुई। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली से थिंपू पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर भूटानी समकक्ष डॉ. टांडी दोरजी ने उनका स्वागत किया। दोरजी के साथ जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। दोनों पक्षों ने बातचीत सकारात्मक होने की जानकारी दी है। भूटान, भारत का पड़ोसी देश होने के साथ ही निकट सहयोगी भी है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान से ही विदेश यात्राओं की शुरुआत की थी।

भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति को दर्शाती है मालदीव और श्रीलंका यात्रा : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी शनिवार से शुरू हो रही मालदीव और श्रीलंका की यात्रा भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति की महत्ता को दर्शाती है। इस यात्रा से समुद्र से घिरे इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को पहले मालदीव और उसके बाद रविवार को श्रीलंका जाएंगे। माना जा रहा है कि मालदीव उन्हें अपने प्रतिष्ठित सम्मान 'ऑर्डर ऑफ निशानिज्जुद्दीन' से सम्मानित करेगा। मोदी मालदीव की संसद को भी संबोधित करेंगे। यात्रा पूर्व बयान में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के संबंध में कहा, 'भारत के लोग पूरी तरह श्रीलंका के लोगों के साथ है जिन्होंने ईस्टर पर भयानक आतंकी हमलों की गहरी पीड़ा और विनाश झेला है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम श्रीलंका का पूरा समर्थन करते हैं।' इन आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका जाने वाले मोदी पहले राष्ट्र प्रमुख हैं।

सैनिकों को अफसर बनाने को चेन्नई में खुलेगा प्रशिक्षण केंद्र

- सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दी 'यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग' को मंजूरी
- चेन्नई में 200 सैनिकों के पहले बैच को 16 सितंबर से प्रशिक्षण

चेन्नई की इसी अकादमी में तैयार होते हैं सेना के अधिकारी (फाइल)

नई दिल्ली, एएनआइ : सेना में बड़े पैमाने पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों को प्रशिक्षण देकर अफसर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। सैनिकों को अफसर बनने का मौका देकर सेना में 11 हजार अफसरों की कमी पूरी की जा सकती है।

सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस संस्थान का नाम 'यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग' होगा। इसे चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) के परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण केंद्र में सैनिकों को सम्भाषण, नेतृत्व और टीम बिल्डिंग स्किल सिखाए जाएंगे। 200 सैनिकों के पहले बैच को पांच महीने के लिए आगामी 16 सितंबर से प्रशिक्षित किया जाएगा। एक ही साल में सैनिकों को दो ऐसे कोर्स कराने की योजना है। विंग में दस अफसरों की एक कोर टीम होगी जो 'इंस्ट्रक्शनल न्यूक्लियस' बनाएगी।

सेना के एक आंतरिक शोध के मुताबिक सैनिकों को अफसर बनाए जाने में कुल मिलाकर 41.4 फीसद की कमी है। सेना विभिन्न स्तरों पर अपने संभावित अधिकारियों को चुनती या भर्ती करती है। प्रशिक्षित सैनिकों को चुनना उनमें से एक प्रक्रिया है। हालांकि एसएसबी सेंटरों में ऐसे सैनिकों के चयन के दौरान उनकी सफलता की दर काफी कम यानी 8.46 फीसद ही है। इसलिए 'यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग' की स्थापना का विचार आया है। इस प्रशिक्षण के बाद भारतीय सैनिक भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए एसएसबी टेस्ट को पूरे आत्मविश्वास से पूरा कर पाएंगे।

सेना के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि 'यंग लीड्र्स ट्रेनिंग विंग' में भेजे गए सभी सैनिक कमीशंड अफसर नहीं बन पाएंगे। लेकिन उनमें से कई जरूर बनेंगे। यह सैनिक बेहतर कार्यक्षमता के साथ अपनी यूनिटों में अन्य सैनिकों के लिए रोल मॉडल होंगे।

सेना में सैनिकों को सैन्य अफसर बनाने के लिए तीन तरीके हैं। पहला जरिया है आर्मी कैडेट कालेज (एसीसी), दूसरा स्पेशल कमीशंड अफसर (एससीओ एंट्री) और तीसरा पर्मानेंट कमीशन (विशेष सूची) (पीसीएसएल) है। पहले दो तरीकों से अफसर को किसी भी ब्रांच में कमीशन किया जा सकता है। जबकि पीसीएसएल अफसरों की तैनाती विशेष नियुक्ति के तौर पर ही होती है।

'यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग' में सैनिकों के चयन के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन होगा। इसके लिए पचमढ़ी स्थित आर्मी एजुकेशन कार्प्स सेंटर एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा कराएगा। इसमें चयनित सर्वश्रेष्ठ 500 एसीसी प्रतिभागियों को एक सघन स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनमें से सौ सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन होगा। इसके अलावा, किसी आपात आवश्यकता की पूर्ति के लिए दस फीसद प्रतियोगियों को रिजर्व में रखा जाएगा। इसी तरह एससीओ और पीसीएसएल अफसर के लिए सर्वश्रेष्ठ 200 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। इनकी भी गहन स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद 'यंग लीडर्स ट्रेनिंग विंग' में प्रवेश के लिए प्रत्येक में 50 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों का चयन किया जाएगा।

संसद का सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को साधने में जुटी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सोनिया गांधी से मिले संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी
- यूपीए अध्यक्ष से संसद के संचालन और कामकाज को लेकर की चर्चा

नई दिल्ली में शुक्रवार को संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(यूपीए) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की और संसद के आगामी सत्र की कार्यवाही के दौरान सहयोग करने का अनुरोध किया। एएनआइ

संसद का सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है। नई सरकार के सामने बजट के साथ पिछली सरकार के लंबित कई बिलों को पास कराने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में चुनावी कटुता को भुलाकर सरकार अब विपक्ष को साधने में जुट गई है। शुक्रवार को इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अर्जुन राम मेघवाल के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान संसद के कामकाज में विपक्ष के सहयोग पर चर्चा हुई है।

सरकार की ओर से यह पहल इसलिए भी की है, क्योंकि वह विपक्ष के साथ मिलकर ही वह कामकाज को तरजीह देना चाहती है। इसका जिक्र खुद पीएम मोदी ने जीत के बाद किया था। तब उन्होंने कहा था कि, 'सरकार भले ही बहुमत से चलती है, लेकिन देश सर्वमत से चलता है। और हम इसी विचार से चलेंगे।'

सरकार की राज्यसभा में बहुमत की कमी की मजबूरियां भी हैं। इसके चलते उन्हें न चाहते हुए भी विपक्ष को साधकर रखना ही होगा। वैसे भी विपक्षी के असहयोग के चलते सरकार को पिछले कार्यकाल में काफी मुश्किलें उठानी पड़ी थीं। इसके चलते तीन तलाक, नागरिकता बिल सहित कई बिलों को वह पास नहीं करा पायी थीं।

प्रह्लाद जोशी ने पिछले दिनों राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और लोकसभा में द्रमुक नेता टीआर बालू से भी मुलाकात की थी। साथ ही उनसे संसद के कामकाज को लेकर चर्चा की थी। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से ऐसी मुलाकात जल्द ही दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ भी हो सकती है। केंद्र सरकार की इस कवायद का मकसद सर्वमत से काम करने का है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मंशा जता चुके हैं।

संसद सत्र को लेकर रक्षामंत्री के घर मंत्रियों के कोर ग्रुप की बैठक

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शुक्रवार को संसद सत्र से जुड़े मुद्दों पर मंत्रियों के कोर ग्रुप की बैठक हुई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। संसद का सत्र 17 जून से शुरू हो रहा है।

बैठक में मौजूद सूत्रों के मुताबिक आगमी सत्र के दौरान सांसदों के साथ समन्वय, नए सांसदों को संसदीय क्रियाकलापों की जानकारी देने और संसद की स्थायी समिति के गठन को लेकर बैठक में चर्चा की गई। संसद सत्र के पहले दो दिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 19 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। संसद का सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। दरअसल, सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बजट तो पेश करेगी ही। उसकी योजना एक बार में तीन तलाक पर रोक समेत 10 अध्यादेशों को भी कानून में बदलने की है।

रक्षा खरीद मुद्दों की समीक्षा की : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सशस्त्र बलों के परिचालन मामलों और खरीद से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के साथ प्लेटफॉर्मों और परिसंपत्तियों के रखरखाव के बारे में महत्वपूर्ण राजस्व खरीद मामलों पर चर्चा की। बैठक में रक्षा सचिव संजय मित्रा, सचिव (रक्षा वित्त) गार्गी कौल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एनआरसी में शामिल नहीं हुए लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में जाएं : केंद्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने में दो माह से भी कम समय रह गया है। इसमें जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं उन्हें केंद्र ने विदेशी ट्रिब्यूनल से संपर्क करने को कहा है। अपना रिकार्ड सौंपने वाले लोगों के बारे में ट्रिब्यूनल चार माह के भीतर फैसला सुनाएगा।

विदेशी अधिनियम 1946 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों के नाम नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन (एनआरसी) में शामिल नहीं है वह एनआरसी अधिकारियों द्वारा दावा ठुकराए जाने के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ किसी ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं। 'अंतिम आदेश में अपीलकर्ता एनआरसी में शामिल किए जाने का पात्र है या नहीं के बारे में ट्रिब्यूनल की राय शामिल रहेगी। इसमें जिला दंडाधिकारी के उल्लेख पर भी ट्रिब्यूनल की राय शामिल रहेगी।'

कांग्रेस में हो सकते हैं दो कार्यकारी अध्यक्ष

नई दिल्ली, आइएएनएस : राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस नहीं लेने की जिद का सामना कर रही पार्टी कार्यकारी अध्यक्षों के माडल पर विचार कर रही है। नए नेतृत्व पर गहन विचार और खींचतान के बाद पार्टी नेतृत्व कथित रूप से इस बात पर विचार कर रही है कि दो कार्यकारी अध्यक्ष होने चाहिए।

यह भी प्रस्ताव है कि कार्यकारी अध्यक्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से हो। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इस संबंध में कुछ नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम है। दोनों अनुसूचित जाति के नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम आ रहा है ताकि युवा चेहरा भी शामिल रहे। सूत्रों ने कहा कि नया प्रारूप संसद के बजट सत्र से पहले सामने आ सकता है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहने की जिद के कारण पार्टी वैकल्पिक माडल पर विचार करने के लिए बाध्य हुई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी की बुरी तरह से हुई पराजय के कारण वह पद छोड़ने पर अड़े हुए हैं और उन्होंने खुद को पार्टी से दूरी बनाने का फैसला लिया है। पार्टी ने इससे पहले तीन कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में फैसला लिया था। इनमें उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत से एक-एक होते और चौथे कार्यकारी अध्यक्ष संभवतः पश्चिम भारत से लिए जाते।

पूर्व मंत्री असलम ने कहा– मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने को तैयार

नईदुनिया, भोपाल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गैरगांधी परिवार के व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाने की अपील पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं ओलंपियन असलम शेर खान आगे आए हैं। उन्होंने दो साल के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर काम करने की इच्छा जताई है। खान ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने यह हिम्मत जुटाई है। कांग्रेस को इस वक्त हिम्मत की जरूरत है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद 25 मई को हुई कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी ली थी। इसके साथ ही अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। इसके दो दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम खान ने राहुल गांधी को यह पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने दो साल के लिए अध्यक्ष का दायित्व संभालने का दावा पेश किया। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के एलान के बाद खान पहले नेता हैं, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए दावा पेश किया है।

असलम शेर खान ने पत्र में लिखा है कि वह दो साल के लिए अस्थायी कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने और अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी व राजनेता दोनों के तौर पर अनुभव है। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि जिस तरह वह हॉकी विश्व कप में अंतिम समय में मिले मौके पर भारत को बराबरी पर ले आए थे और 1992 में बतौर केंद्रीय मंत्री, विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाये जाने पर नाराज मुस्लिमों को कांग्रेस के पक्ष में करने में सफल रहे थे, उसी तरह इस वक्त कांग्रेस जिस स्थान पर खड़ी है, उससे उबारने में कामयाब रहेंगे।

उन्होंने अफसोस जताया कि इस समय कांग्रेस गम और दुख में है। उसके पास प्रतिपक्ष का नेता चुनने लायक सांसद नहीं हैं। कांग्रेस को राष्ट्रवाद से जोड़ने की जरूरत है। खान ने विश्वास जताया कि दो साल के अस्थायी कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी को बराबरी पर लाकर खड़ा कर देंगे।

चंदा कोचर को ईडी ने 10 जून को फिर तलब किया

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीडियोकॉन समूह को 1,875 करोड़ के ऋण आवंटन में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के तहत आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ चंदा कोचर को पूछताछ के लिए 10 जून को फिर तलब किया है।

बता दें कि वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करने वाली एजेंसी ने इससे पूर्व भी चंदा से गत माह पांच बार इसी मामले में पूछताछ की थी। यह मामला 2009 से 2011 के बीच वीडियोकॉन ग्रुप को आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा दिए गए 1875 करोड़ के ऋण से संबंधित है। आरोप है कि ऋण देने में वित्तीय गड़बड़ियां की गईं। ईडी का आरोप है कि जब चंदा बैंक की प्रमुख थीं तब उन्होंने अपने पति द्वारा संचालित कंपनी को गलत तरीके से करोड़ों रुपये का लाभ पहुंचाया। पति की कंपनी में निवेश के बदले में चंदा ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को आइसीआइसीआइ से ऋण दिलाया था। ईडी ने इस मामले में कोचर दंपती तथा धूत से पूछताछ की थी और उनके घर एवं कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया था। वीडियोकॉन ग्रुप ने अपने 40 हजार करोड़ के ऋण के अधिकांश भाग को 2017 तक नहीं चुकाया। बैंक को 2810 करोड़ रुपये को एनपीए घोषित करना पड़ा जिससे उसे करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा।

पीएम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुरक्षित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 2016 में जंतर-मंतर पर सभा में की थी विवादित टिप्पणी
- 19 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी कि केस दर्ज करना है या नहीं

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई विवादित टिप्पणी के मामले में अदालत 19 जुलाई को फैसला सुनाएगी कि राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देना है या नहीं।

राहुल गांधी फाइल

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2016 में जंतर मंतर पर जनसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत टिप्पणी की थी, जिसमें सेना के बारे में भी बोला था। इस पर अधिवक्ता जोगिंद्र तुली ने अदालत में शिकायत दायर कर राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। गत 15 मई को राउज एवेन्यू अदालत में दाखिल अपने जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ मिली शिकायत पर संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई। राहुल ने अगर प्रधानमंत्री के लिए विवादित शब्दों का प्रयोग किया है तो मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है।

शशि थरूर को मिली जमानत

नई दिल्ली : पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के एक अन्य मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को जमानत दे दी। शुक्रवार को थरूर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के समक्ष पेश हुए। 20 हजार के निजी मुचलके पर थरूर को जमानत मिली है। दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर की तरफ से दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने थरूर के खिलाफ समन जारी कर शुक्रवार को अदालत में पेश होने के आदेश दिए थे। शिकायत में कहा गया है कि बेंगलुरू में एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुई।

ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम अब 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाने के लिए भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम की शुरुआत 1,300 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश से हुई थी। अब इसका कारोबार 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। यही नहीं, आज 200 से ज्यादा उद्योग उपक्रम के कारोबारी साझीदार हैं और इसकी वजह से 20 हजार से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है।

कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) द्वारा आयोजित मैनुफेक्चरिंग इनोवेशन कांक्लेव में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सुधीर मिश्रा ने कहा कि सुपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट की तरह भारत और रूस के बीच कई और क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम होने चाहिए थे। यह संयुक्त उपक्रम ऐसे समय किया गया था जब रूस वित्तीय उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था और भारत को कई और सहयोग समझौते करके इसका फायदा उठाना चाहिए था। मालूम हो कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के एनपीओ मशीनॉस्ट्रोयेनिया के बीच 1998 में ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को जमीन, हवा और जलपोत के साथ-साथ पनडुब्बी से भी छोड़ा जा सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य देश भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं? इसका जवाब उन्होंने सकारात्मक दिया, लेकिन उन्होंने उन देशों के नाम नहीं बताए।

सुधीर मिश्रा ने बताया कि संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के दौरान भारत ने सॉफ्टवेयर डेवलेपमेंट और कुछ हद तक निर्माण के क्षेत्र में अपनी ताकत लगाई। निर्माण के चरण से ही भारतीय उद्योग को भी इसमें शामिल किया गया था और कंपनी ने खुद को डिजाइनिंग और उत्पाद के इंटीग्रेशन तक सीमित रखा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

आधी आबादी अधूरा अधिकार

पुरुषों के मुकाबले तीन चौथाई पगार भी नहीं पाती हैं महिलाएं, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में असमानता का शिकार हैं महिलाएं

महिलाएं वोट देने में आगे, पगार पाने में पीछे

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

1.7 गुना तक ज्यादा मेहनताना पाता है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कामगार

1.3 गुना से ज्यादा है यह आंकड़ा शहरी इलाकों में

14000 रुपये औसत मासिक आय है पुरुष कर्मियों की

8500 से लेकर 10 हजार रुपये तक मिलते हैं महिला कर्मियों को

मेहनत में किसी से पीछे नहीं हैं महिलाएं। फाइल

भारत में राजनीति के क्षेत्र में तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल गए हैं लेकिन आर्थिक क्षेत्र में बराबरी का हक पाने के लिए उन्हें अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाल में संपन्न लोकसभा चुनावों में महिलाओं ने पुरुषों के लगभग बराबर और कई राज्यों में तो उनसे अधिक अनुपात में मतदान किया लेकिन आर्थिक क्षेत्र की कड़वी सच्चाई यह है कि गांव हो या शहर, स्वरोजगार हो या नौकरी महिला कामगारों की महीनेभर की कमाई उनके समकक्ष पुरुष कर्मियों से काफी कम है।

सरकार के ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुष और महिलाओं की मासिक आय में बड़ा अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में एक पुरुष कामगार महिलाओं की अपेक्षा 1.4 से 1.7 गुना ज्यादा मेहनताना पाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुष कर्मचारियों की आय महिलाओं की तुलना में 1.2 से 1.3 गुना ज्यादा है।

'पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे' शीर्षक वाला यह सर्वे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने वर्ष 2017-18 के लिए देश भर में किया था इसके नतीजे 31 मई को जारी किए गए हैं। सर्वे के मुताबिक उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित मजदूरी और वेतनभोगी पुरुष कर्मचारियों की मासिक आय औसत 13,000 से 14,000 रुपये रही जबकि महिला कर्मचारियों की आय मात्र 8.5 हजार से 10,000 रुपये थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में नियमित मजदूरी करने वाले और वेतन भोगी पुरुष कर्मचारियों की मासिक आय 17,000 से 18,000 रुपये के बीच रही, जबकि महिला कर्मचारियों की आय मात्र 14,000 से 15,000 रुपये रही। यही हाल अकुशल श्रमिकों के मामले में भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल महिला श्रमिक को मात्र 166 रुपये से 179 रुपये की मजदूरी मिली जबकि पुरुषों को 253 से 282 रुपये मिले। इसी तरह शहरों में अकुशल पुरुष श्रमिक को 314 रुपये से 335 रुपये तक मजदूरी मिली जबकि महिला श्रमिक की मजदूरी मात्र 186 से 201 रुपये ही रही। स्वरोजगार के मामले में भी तस्वीर कोई अलग नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के जरिए एक पुरुष कामगार महीने भर में 8,500 से 9,700 रुपये कमाए वहीं, महिला कामगार को मात्र 3,900 से 4,300 रुपये की आय हुई। उल्लेखनीय है कि देश में महिलाओं की दशा को लेकर आए दिन सवाल उठते रहते हैं।

8 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का पावस सत्र शुरू होगा। 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कमलनाथ सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस सरकार के दूसरे सत्र में लेखानुदान पारित हुआ था जिसमें चार महीने का बजट सरकार को दिया गया था।

जड़ों से जुड़कर ही आगे बढ़ेगा राष्ट्र : योगी

जागरण संवाददाता, अयोध्या

रामजन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास के 10 दिवसीय 81वें जन्मोत्सव का उद्घाटन करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे गए। मणिरामदास जी की छावनी परिसर में करीब 35 मिनट के उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, अपनी संस्कृति को विस्मृत कर कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आज भारत इसीलिए बुलंदियों को छू रहा है क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को शिरोधार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश में सकारात्मक सोच की सरकार है, जो आस्था एवं विरासत के साथ देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस दिशा में उन्होंने केंद्र के साथ प्रदेश सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया और अयोध्या में हुए कार्यों की चर्चा की। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि इस वर्ष दो अहम घटनाएं हुई हैं। पहली यह कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार आई और दूसरी यह कि प्रयाग कुंभ का आयोजन बेहद भव्यता से हुआ। मुख्यमंत्री ने कुंभ में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वच्छता कर्मियों का पद प्रक्षालन किए जाने को इतिहास की

अयोध्या शोध संस्थान में शुक्रवार को कोदंड राम की प्रतिमा के अनावरण के बाद पुष्प अर्पित करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीतू निषाद

अद्भुत घटना बताया। कहा कि प्रधानमंत्री ने यह पुष्ट किया कि भारतीय समाज में राजा-रंक के बीच भेद नहीं रहा है, न ही अस्पृश्यता के लिए कोई जगह है। उन्होंने कहा कि राम की पावन जन्मभूमि से सबके सुख और सबके मंगल का ऐसा संदेश जाना चाहिए, जिससे भव्य राममंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, वे खारिज हो गए। समाज के बारे में जो अंतःकरण से सोचेगा, देश उसके साथ खड़ा होगा।

करीब चार घंटे के अयोध्या प्रवास में ने तुलसी स्मारक भवन में कोदंड राम की प्रतिमा का अनावरण किया, रामजन्मभूमि एवं हनुमानगढ़ी का दर्शन किया तथा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किए जा रहे राम की पैड़ी के विकास कार्य, भजन सत्संग स्थल तथा बस स्टेशन के निर्माण का जायजा लिया।

कोदंड राम यानी धनुर्धर राम : दक्षिण भारत में राम के विभिन्न स्वरूप में से कोदंड राम एक हैं। कोदंड यानी धनुष। राम जब सीता की खोज के लिए दक्षिण भारत पहुंचे, तो वनवासी रूप में उनके हाथ में उनका धनुष यानी कोदंड था। उन्होंने अपनी पत्नी सीता की रक्षा के लिए धनुष उठाया था। लिहाजा दक्षिण भारत में उनका परिचय एक ऐसे पुरुष के तौर पर होता है, जो 'स्त्री रक्षक' हैं। अयोध्या में कोदंड राम की लगाई गई प्रतिमा सात फीट ऊंची है। इसे बंगलुरू के एम राममूर्ति व एम भूपति नामक दो विख्यात कलाकार भाइयों ने बनाया है।

हिंदुत्व के एजेंडे को फिर धार देने में जुटे उप्र के मुख्यमंत्री

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- अयोध्या की ओर देश-दुनिया का ध्यान खींचने में जुटे योगी
- प्रमुख धर्म स्थलों के विकास पर सरकार का विशेष जोर

लोकसभा चुनाव के दौरान सहारनपुर में शाकंभरी पीठ से दर्शन-पूजन कर चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धार्मिक सक्रियता फिर बढ़ी है। उन्होंने शुक्रवार को अयोध्या में कोदंड भगवान श्रीराम की प्रतिमा के अनावरण से अपने एजेंडे को धार दी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद धार्मिक स्थलों की साफ-सफाई पर विशेष जोर देने के साथ ही योगी ने अयोध्या, काशी और मथुरा के विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी। अयोध्या और मथुरा-वृंदावन को नगर निगम बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने इन नगरों का खूब भ्रमण किया। दीपोत्सव मनाकर अयोध्या की रंगत बदल दी। फिर फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया। इसके पहले इलाहाबाद को प्रयागराज नाम दिया गया। प्रयागराज के कुंभ से योगी का धार्मिक संदेश पूरी दुनिया में गया। कई देशों के लोग कुंभ में आए। रामायण सर्किट और ब्रज सर्किट में भी विकास की योजनाओं को बढ़ावा मिला। सिंधु दर्शन यात्रियों की अनुदान राशि दोगुनी की गई। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट से लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास योजना शुरू की गई हैं।

पर्यटन की दृष्टि से भी बढ़ा अयोध्या का आकर्षण

शुक्रवार को योगी ने अयोध्या में कोदंड भगवान श्रीराम की प्रतिमा के अनावरण के साथ ही अयोध्या हस्तशिल्प में राम संग्रहालय की स्थापना और तीन देशों की कैरेबियन रामलीला यात्रा पर विशेष रिपोर्ट प्रकाशित कर अयोध्या के प्रति नया आकर्षण पैदा किया। दरअसल, सरकार पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या की ओर देश-दुनिया का ध्यान खींच रही है। मंदिरों में देश-विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।

सरकार नहीं चला सकता तो कांग्रेस-जदएस गठबंधन सत्ता छोड़े : येद्दयुरप्पा

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा ने शुक्रवार को कांग्रेस-जदएस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राज्य की सरकार नहीं चला सकता है तो सत्ता छोड़ दे। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि यदि सत्तारूढ़ गठबंधन टूटता है तो उनकी पार्टी मामले को संभाल लेगी और राज्य में मध्यावधि चुनाव नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा हर हाल में स्थायी सरकार देने के लिए काम करती है।

पूर्व मुख्यमंत्री येद्दयुरप्पा ने हुबली में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, किसी को विश्वास नहीं है कि एचडी कुमारस्वामी की नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, 'कुमारस्वामी के बेटे निखिल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। मैं कहता हूं कि यहां किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होगा। हमारे (भाजपा) पास 105 विधायक हैं। अगर वे सरकार चला सकते हैं तो चलाने दो, लेकिन वे विफल होते हैं तो हम सरकार चलाएंगे।' येद्दयुरप्पा उस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें निखिल जदएस कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि भाजपा कहती रही है कि वह कुमारस्वामी सरकार को नहीं गिराएगी।

कांग्रेस अध्यक्ष ने रखी बात ▶ संसद के बाहर और भीतर वायनाड के लोगों की बनेंगे आवाज

मोदी की जनविरोधी नीतियों से बचाएंगे

अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लोगों का धन्यवाद करने पहुंचे हैं राहुल गांधी

मलप्पुरम (केरल), प्रेट्र/एएनआइ : लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पहली लोगों के बीच पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वह मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों से लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए वायनाड के लोगों का आभार जताने पहुंचे राहुल गांधी ने मूसलाधार बारिश के बीच ही रोड शो किया। उनके स्वागत और दीदार के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े रहे। भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लोगों को धन्यवाद देने के लिए तीन की यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने पहले दिन निलंबुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'मौजूदा सरकार और नरेंद्र मोदी ने देश में नफरत का माहौल पैदा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी यह जानती और समझती है कि प्यार और स्नेह ही नफरत से लड़ने का एकमात्र रास्ता है।' आम चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले गांधी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की। कांग्रेस कार्यसमिति ने उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया है। हालांकि, वो

केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में शुक्रवार को पहली बार पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन करते राहुल। एएनआइ

अपने फैसले पर अड़े हुए हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि वह वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने और बेहतर वायनाड के निर्माण के लिए यहां के लोगों के साथ काम करने को लेकर आशांवित हैं। राहुल ने कहा कि वह मोदी सरकार और खुद मोदी से देश के कमजोर तबके को बचाने के लिए समर्पित हैं। खुले वाहन में सवार राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी थे। वायनाड के साथ ही राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी से भी लोकसभा चुनाव लड़े थे। अमेठी में जहां उन्हें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से 55 हजार से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा था, वहीं वायनाड में उन्होंने चार लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को लोकसभा की 20 में से 19 सीटें मिली हैं।

नक्सल प्रभावित माने जाने वाले कालीकवू के संकरे रास्ते से जब राहुल गांधी का काफिला गुजरा तो सुरक्षा एजेंसियों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। उत्साहित भीड़ राहुल गांधी के नारे लगा रही थी, सुरक्षा बलों के लिए भीड़ को काबू में करना मुश्किल हो रहा था।

राहुल गांधी ने कहा कि वह भले ही वायनाड के चुने गए हैं, लेकिन संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पूरे केरल के लोगों से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही कर दी कर्मचारियों की पदोन्नति

नईदुनिया, भोपाल : पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब तक फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश बीज विकास निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी गई। तत्कालीन प्रबंध संचालक विनय बर्मन ने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले पदोन्नति आदेश जारी किए। दो नाराज कर्मचारी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं।

बर्मन 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने 29 दिसंबर को कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी। पदोन्नति इतनी गोपनीय रखी गई कि कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। मामला तब खुला, जब निगम के कर्मचारी रवि मालवीय और लाल सिंह तत्कालीन प्रबंध संचालक के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार बर्मन ने निगम के क्षेत्रीय कार्यालय सागर में पदस्थ सहायक प्रबंधक हीरालाल अहिरवार को प्रक्षेत्र प्रबंधक वर्ग-एक के पद पर पदोन्नत कर उन्हें क्षेत्रीय प्रबंधक सागर पदस्थ कर दिया, तो क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के सहायक प्रबंधक शंभूसिंह बारिया को प्रक्षेत्र प्रबंधक वर्ग-एक में पदोन्नत कर इंदौर में ही पदस्थ कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि इस फैसले में रोस्टर नियमों का पालन नहीं किया गया। रोस्टर के मुताबिक चार पद में से दो सीधी भर्ती के थे और दो अन्य पद पदोन्नति से भरे जाने थे। लेकिन रोस्टर के विपरीत दो पदों की जगह तीन पद भर दिए गए। कर्मचारी रवि मालवीय ने जबलपुर और लाल सिंह ने ग्वालियर की हाई कोर्ट ब्रांच में याचिका लगाई है। फरवरी माह में लगाई गई याचिका पर इस माह सुनवाई होनी है।

कांग्रेस सरकार में वाजपेयी संस्थान के मुताबिक काम करेगा प्रशासन

वैभव श्रीधर, भोपाल

- मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में प्रशासन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के मुताबिक काम करेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रशासनिक कसावट लाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। व्यवस्था में बदलाव के दौरान वायपेयी संस्थान की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा।

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान ने विभागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके एक रिपोर्ट पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय सौंपी थी। इसके निष्कर्षों पर मंथन करके किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 जून को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक के जो भी नतीजे होंगे, उन्हें आगामी कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती को भेजा जाएगा।

भाजपा सरकार को दी थी रिपोर्ट, लागू करेगी कांग्रेस : सूत्रों के मुताबिक वाजपेयी संस्थान ने एक साल पहले विभागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके एक रिपोर्ट तत्कालीन भाजपा सरकार को सौंपी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच प्रदेश में सरकार बदल गई।

अब मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ ने प्रशासनिक कसावट के लिए व्यवस्था परिवर्तन पर जोर देते हुए गैर जरूरी विभाग, आयोग, निगम और मंडलों को बंद करने की बात कही थी। साथ ही इस बात पर सभी मंत्रियों और अधिकारियों को फोकस करने को कहा गया

संस्थान ने अध्ययन करके इस बारे में शासन को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें क्या अनुशंसा की गई हैं, इसे देखा नहीं है, क्योंकि यह प्रतिवेदन संस्थान में मेरे आने से पहले सौंप दिया गया था।

– आर परशुराम, महानिदेशक, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल

है कि समान प्रकृति के काम वाली योजनाओं पर और विभागों को एक कर दिया जाए ताकि दोहराव न हो।

एक छतरी के नीचे कई विभाग लागे की पहल : कमलनाथ की मंशा के अनुरूप प्रशासन में बदलाव करने के लिए सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की रिपोर्ट पर मंथन करने पर विचार हुआ। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों की बैठक बुलाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 55 विभागों के 26 समूह बनाए जाएं। बड़े समूहों में अपर मुख्य सचिव पदस्थ किया जाए ताकि प्रभावी प्रशासन एवं समन्वय हो सके। इसके लिए अपर कृषि उत्पादन आयुक्त जैसा मॉडल भी अपनाया जा सकता है। इस मॉडल के तहत कृषि, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे विभाग एक छतरी के नीचे आते हैं। इन विभागों से जुड़ी संस्थाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण रहता है और विवाद की सूरत में मध्यस्तता करने के लिए एक मंच मिल जाता है। इससे मुख्य सचिव और कैबिनेट का समय भी बचता है।

सवर्ण आरक्षण का विरोध राजद को पड़ा महंगा

अरविंद शर्मा, पटना

- लोकसभा चुनाव में हार की जांच के लिए बनी समिति का आकलन
- यादवों से अति पिछड़ी जातियों का फासला भी बना हार की वजह
- पड़ताल का ब्योरा राजद प्रमुख लालू प्रसाद तक पहुंचाएंगे रामचंद्र पूर्वे

लोकसभा चुनाव में राजद (राष्ट्रीय जनता दल) की शिकस्त की वजहें तलाशी जा रही हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में दमदार लड़ाई की जमीन तैयार हो सके। प्रारंभिक तौर पर तीन सदस्यों की टीम ने जो खोजा है, उसके मुताबिक सवर्ण आरक्षण का विरोध राजद के नए नेतृत्व को सबसे ज्यादा भारी पड़ा है। गठबंधन के घटक दलों के आधार वोटरों की उदासीनता के साथ-साथ यादवों से अति पिछड़ी जातियों का बढ़ता फासला भी हार की वजह बना है।

पड़ताल का मौखिक ब्योरा शनिवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद तक पहुंचा दिया जाएगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे रांची गए हैं। चुनाव नतीजे के बाद हार की हताशा से उबरने के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पराजय के वास्तविक कारणों की पड़ताल जरूरी समझा था। इसके लिए 28 मई को राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनी, जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी और आलोक मेहता भी शामिल हैं। रिपोर्ट हफ्ते भर के अंदर देनी थी, किंतु समय ज्यादा बीत गया। अभी तक प्रक्रिया ही चल रही है।

तेजस्वी की नकारात्मक छवि बन गई : प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि सवर्ण आरक्षण के प्रबल विरोध के चलते राजद का न केवल वर्तमान का नुकसान हुआ है, बल्कि भविष्य की सियासत के भी प्रभावित होने का खतरा है। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पार्टी की कमान संभाली थी, उसकी चौतरफा तारीफ हो रही थी। जाति-बिरादरी से अलग युवाओं का एक वर्ग ऐसा था जो तेजस्वी को प्रगतिशील मानकर बिहार का भविष्य देख रहा था। किंतु राजद प्रवक्ता मनोज झा के राज्यसभा में झुनझुना बजाने से उसकी भावनाओं को धक्का लगा। जिनके लिए हल्ला मचाया गया, उनका साथ तो नहीं ही मिला, उल्टे प्रगतिशील तबके के बीच तेजस्वी की नकारात्मक छवि बन गई। राजद के सवर्ण नेता आज तक समझ नहीं पाए हैं कि पहले के अपने घोषणा पत्रों में सवर्ण आरक्षण का पक्ष लेने वाले लालू के उत्तराधिकारी ने अबकी यूटर्न किसकी सलाह पर लिया।

घटक दल वोट ट्रांसफर तक नहीं करा पाए : पराजय का दूसरा सबसे प्रमुख कारण महागठबंधन के घटक दलों के आधार वोट का ट्रांसफर नहीं होना माना जा रहा है। राजद का आधार वोट तो साथी दलों को मिला, लेकिन कुशवाहा, मांझी और मल्लाहों का वोट राजद के पक्ष में नहीं पड़ा। गांवों में अतिपिछड़ी जाति के लोगों का यादवों के साथ स्वभाविक तालमेल नहीं हो पाना भी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। भाजपा की तुलना में राजद का निचले स्तर का प्रबंधन बेहद कमजोर था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर इस पर काम नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट में भाजपा की जीत को साजिश का हिस्सा भी बताया गया है।

शाह की बढ़ी सुरक्षा, मिलेंगे एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुरक्षा घेरे को मजबूत करते हुए दिल्ली पुलिस ने उनके आवास पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। शाह ने पिछले हफ्ते ही अपना कार्यभार संभाला है।

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री की सुरक्षा की समीक्षा के बाद उनके निवास पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। वर्तमान में शाह को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की ओर से जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की जा रही है। अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त बल दिल्ली पुलिस के हैं।

गृह मंत्री जल्दी ही उस आवास में स्थानांतरित हो सकते हैं, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी को मिला हुआ था। सुरक्षा कारणों से शाह की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो को लगाया जा सकता है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बहरहाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना के संभालने तक दिल्ली पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करना जारी रखेगी। अधिकारी ने बताया कि सिंह के आवास की सुरक्षा फिलहाल अर्धसैनिक बल कर रहे हैं।

गृह मंत्री के निजी सचिव बने बिहार के साकेत कुमार

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइएएस अधिकारी साकेत कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुमार की नियुक्ति 29 जुलाई 2023 तक की गई है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) में 2009 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं। इससे पहले कुमार पिछले वर्ष तत्कालीन संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा के निजी सचिव नियुक्त किए गए थे।

एक अन्य आदेश में एम. इमकोंगला जमीर को कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 22 जुलाई 2020 तक के लिए की गई है। 2002 बैच के आइएएस अधिकारी जमीर कर्नाटक कैडर के हैं। 2015 में भी उन्हें ईरानी का निजी सचिव नियुक्त किया गया था। उस समय ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री थीं।

नौकरशाह आशीष कुमार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वह 27 अगस्त 2021 तक निजी सचिव रहेंगे। 2005 बैच के आइएएस अधिकारी कुमार तमिलनाडु कैडर के हैं।

2009 बैच के आइएएस अधिकारी हैं साकेत

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार कैडर के 2009 बैच के आइएएस साकेत कुमार बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता मधुबनी के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। डॉन बॉस्को मधुबनी और मॉडर्न स्कूल दिल्ली से स्कूली शिक्षा पाने के बाद उन्होंने स्नातक और पीजी की पढ़ाई दिल्ली के हिंदू कॉलेज से की। दूसरे प्रयास में संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास करने वाले साकेत 13वें स्थान पर आए थे। उस साल संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बिहार के सफल प्रतिभागियों में वह अव्वल रहे थे। साकेत वैशाली में एसडीओ व समस्तीपुर में डीडीसी का पद संभाल चुके हैं। इसके

साकेत कुमार फाइल

बाद वह बांका और खगड़िया में डीएम रहे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के पूर्व वह बिहार के भवन निर्माण विभाग में अपर सचिव के रूप में तैनात थे।

मजबूत इरादे

हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिये गठबंधन की राजनीति और उम्मीदवारों के नाम पर रायशुमारी कर रहे हैं, परिवार की आपसी कलह पर चौटाला की दो टूक, गद्दारों का नहीं इनेलो पार्टी में कोई काम

इनेलो को फिर खड़ा कर चुनावी नींव तैयार कर रहे चौटाला

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा के चार बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला एक सप्ताह से पार्टी संगठन में जान फूंकने का काम रहे हैं। चौटाला राज्य के सभी जिले नाप चुके हैं और शनिवार को उनका आखिरी जिला स्तरीय दौरा है। चौटाला जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहां कार्यकर्ता सम्मेलनों के बाद प्रमुख पदाधिकारियों से अलग मंत्रणा कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से न केवल गठबंधन की राजनीति पर उनकी राय ली जा रही है, बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तलाश भी हो रही है।

जेबीटी भर्ती मामले में सजा काट रहे इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला फिलहाल पैरोल पर हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पैरोल में अड़ंगा डाल दिया गया था। अब पैरोल मिली तो चौटाला ने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का रुख किया। अब इनेलो के राजनीतिक मामलों की कमेटी की बैठक के बाद चौटाला हर जिले में दस्तक दे रहे हैं। चौटाला कार्यकर्ताओं को तसल्ली बंधा रहे हैं कि बिखराव जैसी मौजूदा स्थिति पार्टी में पहली

ओमप्रकाश चौटाला फाइल

> बड़े चौटाला साहब आयरन मैन हैं। राजनीति के बड़े उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं। पार्टी में गद्दारों का कोई काम नहीं है। यह बात चौटाला साहब खुद स्पष्ट कर चुके हैं। हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद का सिलसिला चल रहा है। कई बार ऐसे मौके आए, जब पार्टी टूटने के बाद फिर से संभलकर मजबूती से खड़ी हुई है। इनेलो अपने काडर बेस कार्यकर्ताओं के बूते फिर सत्ता में वापसी करेगी।
>
> **अभय सिंह चौटाला, नेता इनेलो विधायक दल, हरियाणा**

बार नहीं आई है। इससे पहले भी पार्टी कई बार भितरघात, टूट-फूट और बिखराव का शिकार हुई है, लेकिन हर बार पार्टी नए सिरे से खड़ी हुई। इसके लिए चौटाला ने सेहरा कार्यकर्ताओं के सिर ही बांधा है।

चौटाला कार्यकर्ता सम्मेलनों में पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव का माहौल भी तैयार कर रहे हैं। उनकी याददाश्त अभी भी गजब की है। अपने जिला स्तरीय दौरों के बीच चौटाला शुक्रवार को आराम करने की मंशा से चंडीगढ़ पहुंचे। मगर आराम करने के बजाय उन्होंने सुबह को पंचकूला में कार्यकर्ता सम्मेलन किया और शाम को अभय सिंह चौटाला के निवास पर प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की बैठक ली।

84 साल के चौटाला में कार्यकर्ताओं को नाम लेकर दूर से पहचानने की गजब की क्षमता है। पुराने से पुराने कार्यकर्ता को नाम से बुलाना चौटाला का राजनीतिक स्टाइल है। कार्यकर्ता उनके इसी स्टाइल के कायल हैं। कार्यकर्ता सम्मेलनों के बाद कुछ कार्यकर्ता चौटाला के साथ परिवार की आपसी कलह से हुए नुकसान की चर्चा भी करते हैं। इस मुद्दे पर चौटाला पूरी तरह से स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि गद्दारों को पार्टी में किसी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। उनका इशारा अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला की तरफ है।

मनोहर पर हमला और दीपेंद्र की तारीफ चौटाला की रणनीति का हिस्सा : चौटाला राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर राजनीतिक हमला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ चौटाला की रणनीति का पार्ट है। अतीत में कांग्रेस और इनेलो (तत्कालीन जनता दल व जनता पार्टी) एक साथ सत्ता चला चुके हैं। ऐसे में इनेलो के रणनीतिकारों को लगता है कि यदि हरियाणा के चुनावी रण में कांग्रेस, इनेलो और बसपा मिल जाएं तो सत्तारूढ़ भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी रणनीति पर काम भी चल रहा है। चौटाला के दीपेंद्र प्रेम पर हुड्डा ने जब उन्हीं के अंदाज में प्रतिक्रिया जाहिर की तो दोनों बड़े घरानों के बीच राजनीतिक प्रेम-प्यार की पींगें बढ़ने की संभावनाओं को बल मिला है।

सरकार को घेरने की कोशिश में खुद घिरे गुजरात के नेता विपक्ष

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की कक्षा छह की किताब में राष्ट्रगान के रचयिता के नाम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे नेता विपक्ष परेश धनाणी खुद घिर गए।

किताब के पिछले कवर पर राष्ट्रगान (जन गण मन...) का शीर्षक राष्ट्रगीत और रचयिता का नाम रवींद्रनाथ ठाकुर छपा है। नेता विपक्ष परेश धनाणी टैगोर व ठाकुर सरनेम को लेकर भ्रमित हो गए और शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, 'दंभी राष्ट्रवाद...ऐसी भूल करने वाले बच्चों को क्या पढ़ाएंगे।' इसके बाद मंडल के विशेषज्ञ कमलेश परमार सामने आए और बताया कि पश्चिम बंगाल में रवींद्रनाथ टैगोर के नाम के साथ ठाकुर ही लिखा जाता है। गुजरात में भी बोलचाल में यही प्रचलित है। राजनीतिक विश्लेषक प्रो. हरि देसाई ने भी इसे भूल करार देते हुए ट्वीट हटा लेने की सलाह दी। इसके बाद तो नेता विपक्ष सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए।

आज मिलेंगे 466 युवा सैन्य अधिकारी

जेएनएन, नई दिल्ली : आइएमए देहरादून और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी बोधगया में शनिवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देहरादून से 382 और बोधगया से 84 कैडेट अधिकारी बनकर निकलेंगे।

जनमत

मुद्दा

क्या कांग्रेस से हाथ मिलाना, सिंगूर आंदोलन और ज्योति बसु को पीएम न बनाने जैसे निर्णय देश की वाम राजनीति के सिमटने की वजह बने?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

facebook.com/muddajagran

mudda@jagran.com

18 नगर निकायों में चुनाव कराने की मांग की है पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सरकार से। इन निकायों का कार्यकाल 2018 में ही पूरा हो चुका है और सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है।

नीति आयोग को निष्फल बता ममता ने बैठक में आने से किया इन्कार

दो टूक ▶ बंगाल की सीएम ने पीएम को लिखा पत्र, कहा–बैठक में आना निरर्थक

आयोग ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की 15 जून को बुलाई है बैठक

जागरण संवाददाता, कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 15 जून को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। साथ ही कहा है कि एक संस्था के तौर पर यह 'निष्फल' है। राज्य की योजनाओं में मदद के लिए इसके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं।

गौरतलब है कि देश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मोदी 15 जून को नीति आयोग के संचालन परिषद की पांचवीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ऐसे में मोदी को पत्र लिखकर ममता ने बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया है। साथ ही उनको लिखे पत्र में सुझाव दिया कि सहकारी संघवाद को बढ़ाने और संघीय नीति की मजबूती के लिए अंतरराज्यीय परिषद (आइएससी) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में नीति आयोग से प्राप्त अनुभव ने मेरे पहले के विचार को बल दिया कि हमें संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित आइएससी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और देश की प्रमुख इकाई के तौर पर आइएससी को अपने कार्य के निष्पादन के लिए इसमें समुचित संशोधन कर इसके कामकाज का दायरा बढ़ाना चाहिए।

कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बोलती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एएनआइ

आयोग के गठन को बताया था एकतरफा पहल : अपने पत्र में ममता ने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री से चर्चा किए बगैर नीति आयोग के गठन की एकतरफा घोषणा की गई है। उन्होंने नीति आयोग के अधिकारियों और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयानों का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के प्रयास के तहत थिंक-टैंक को धन आवंटित करने की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। बंगाल में तृणमूल और भाजपा में जारी सियासी संग्राम की बीच ममता द्वारा नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का यह फैसला अहम माना जा रहा है।

भंग करने की घोषणा की थी : नीति आयोग को लेकर ममता काफी चिढ़ी हुई हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने एलान किया था कि यदि उनकी समर्थन वाली सरकार केंद्र में आती है तो नीति आयोग को भंग कर फिर से योजना आयोग को बहाल किया जाएगा।

योजना आयोग फिर से बहाल करने की रखी मांग: पत्र भेजने के बाद ममता ने संवाददाता सम्मेलन में नीति आयोग के पुनर्गठन का विरोध करते हुए कहा कि योजना आयोग कहीं ज्यादा प्रभावी था। वह ज्यादा सफल रहता। योजना आयोग को वापस लाना चाहिए।

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी मोदी को भेजी थी तल्ख चिट्ठी : बता दें कि इससे पहले ममता भाजपा पर शपथ ग्रहण समारोह में सियासत का आरोप लगाते हुए मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बनी थीं। पत्र में ममता ने लिखा था, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आपको बधाई! संवैधानिक आमंत्रण पर मैंने शपथ ग्रहण में शामिल होने का फैसला किया था। हालांकि, पिछले कुछ घंटे में मीडिया रिपोर्ट में मैंने देखा कि बीजेपी दावा कर रही है कि बंगाल में 54 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। यह पूरी तरह से झूठ है। बंगाल में कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई है।

पंजाब में मेडिकल में दाखिले के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी

राजीव शर्मा, फरीदकोट

- पहले 10वीं से 12वीं पंजाब से करना था जरूरी, अब नियम में बदलाव
- राज्य के आठ मेडिकल कॉलेजों में 1125 सीटों पर होगा दाखिला

पंजाब सरकार ने नीट-2019 के परिणाम की घोषणा के एक दिन बाद राज्य के आठ मेडिकल कॉलेजों (पांच प्राइवेट और तीन सरकारी) में एमबीबीएस की 1125 सीटों पर दाखिला लेने के नियम में बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस साल एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी के पास पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाणपत्र) होना ही जरूरी है, जबकि इससे पहले पंजाब में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों का 11वीं और 12वीं कक्षा पंजाब से होना जरूरी थी।

पंजाब में पिछले लंबे समय से नियम बना हुआ था कि एमबीबीएस में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों की 11वीं व 12वीं पंजाब से की होनी चाहिए। 2014 में पंजाब सरकार ने इसमें 10वीं कक्षा भी पंजाब से करना जरूरी कर दिया जिसे कुछ विद्यार्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर फैसला 2016 में आया था। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर पंजाब सरकार ने मार्च 2016 में अधिसूचना जारी करते हुए प्रावधान किया था कि सेशन 2019-20 से एमबीबीएस में दाखिला लेने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ-साथ विद्यार्थी की 10वीं, 11वीं व 12वीं कक्षा भी पंजाब से की होनी चाहिए, लेकिन नीट का नतीजा घोषित होने के अगले दिन वीरवार शाम मेडिकल शिक्षा व खोज विभाग ने मार्च 2016 में जारी उस अधिसूचना को वापस ले लिया। नई अधिसूचना जारी करते हुए इस सेशन से दाखिले के लिए सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी कर दिया।

नए नियम से हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के विद्यार्थियों को झटका : पंजाब सरकार के नए नियम से हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के विद्यार्थियों को झटका लगा है। इन दोनों राज्यों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर ही दाखिले का प्रावधान है और वह पंजाब में दाखिला लेने की मंशा से 11वीं व 12वीं कक्षा करने के लिए चंडीगढ़ के आसपास पंजाब के स्कूलों में दाखिला ले लेते थे। ऐसा करके वह अपने राज्य के साथ-साथ पंजाब में दाखिला लेने के लिए योग्य बन जाते थे, लेकिन इस सेशन से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा।

छत्तीसगढ़ में बघेल ने कलेक्टरों के हवाले किया बिजली अमला

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में बिजली गुल होने और कटौती की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। इससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इतने आहत हुए हैं कि उन्होंने व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सीधे कलेक्टरों को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को जिले के बिजली अफसरों और कर्मियों की बैठक लेकर पूरा सिस्टम ठीक करने का निर्देश दिया है। इधर, बिजली कंपनी प्रबंधन व्यवस्था दुरुस्त कर लिए जाने का दावा कर रहा है। प्रबंधन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आंधी-तूफान की वजह से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। वनांचलों में भी बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहां व्यवस्था दरुस्त करने में लगे बिजली कर्मियों का सामना सांप- बिच्छू से सामना हो रहा है, फिर भी वे काम कर रहे हैं। कंपनी ने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली का पर्याप्त उत्पादन होता है फिर भी ऐसी शिकायतों का आना खेदजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा अगर संबंधित अधिकारी बिजली से संबंधी गड़बड़ी और शिकायतों को दूर नहीं कर सकते तो उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अफसरों के खिलाफ बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

भाजपा–तृणमूल की पोस्टकार्ड जंग से डाकिये परेशान

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- विभाग के छूट रहे हैं पसीने, पोस्टकार्ड की बिक्री कई गुना बढ़ी
- मुख्यमंत्री आवास पर लगातार पहुंचाए जा रहे हैं पोस्टकार्ड

पश्चिम बंगाल में 'जय श्रीराम' नारे को लेकर भाजपा व तृणमूल कांग्रेस में छिड़ी जंग से डाकिये परेशान हो गए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर लगातार पत्र पहुंचाए जा रहे हैं। इससे विभाग के पसीने छूट रहे हैं। इस बीच पोस्टकार्ड की बिक्री भी कई गुना बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाजपा से चल रही राजनीतिक लड़ाई के चलते पिछले कुछ दिनों से कालीघाट पोस्ट ऑफिस में लगातार पोस्टकार्ड आ रहे हैं। इन पर 'जय श्रीराम' लिखा होता है और इन्हें ममता के यहां भेजा जा रहा है। बावजूद इसके पोस्टऑफिस में इनका अंबार लगा हुआ है। ममता का घर इसी पोस्ट ऑफिस के कार्यक्षेत्र में आता है।

पोस्ट ऑफिस के सूत्रों ने कहा कि आमतौर पर सीएम के लिए 30 से 40 पोस्टकार्ड और रजिस्टर्ड लेटर आते थे। लेकिन, अचानक से इनकी संख्या कई गुना बढ़ गई है। यह आंकड़ा प्रतिदिन आने वाले सभी कार्डों के 10 प्रतिशत है। इस बीच रेलवे मेल सर्विस से भी सीएम को भेजने के लिए करीब 4500 पोस्टकार्ड पहुंचे हैं।

तृणमूल 'जय हिंद, जय बांग्ला' लिखे पोस्टकार्ड भेज रही : 'जय श्रीराम' लिखे पोस्टकार्ड भेजे जाने से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस खुश नहीं है। यही वजह है कि उसने भी पोस्टकार्ड का जवाब पोस्टकार्ड से देना शुरू कर दिया है। तृणमूल 'जय श्रीराम' की जगह पर 'जय हिंद, जय बांग्ला' लिखे पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज रही है।

पीएम को प्रतिदिन 8000 पोस्टकार्ड भेजने का दावा : राज्य के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने कहा, 'मुख्यतः उत्तर 24 परगना, हावड़ा और हुगली के हमारे समर्थक प्रतिदिन आठ हजार पोस्टकार्ड पीएम को भेज रहे हैं। वर्तमान समय में अब पोस्टकार्ड की कमी हो गई है और हमने फैसला किया है कि अब पत्र छापे जाएंगे और उसे पीएम को भेजा जाएगा। हम पीएमओ को इन पत्रों को भेजना जारी रखेंगे।'

बंगाल में रोक के बावजूद भाजपा ने निकाला विजय जुलूस

जेएनएन, कोलकाता

- प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का दो-टूक, कहा-ममता बनर्जी नहीं कर सकतीं फैसला
- मेदिनीपुर से पार्टी सांसद की पुलिस को चुनौती, कहा-हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए

पश्चिम बंगाल में भाजपा के विजय जुलूस पर ममता सरकार के रोक लगाने के बावजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं मेदिनीपुर से पार्टी सांसद दिलीप घोष की अगुआई में रायगंज के कालियागंज इलाके में विजय जुलूस निकाला गया।

विजय जुलूस शुरू होने से पहले घोष ने दो-टूक कहा कि भाजपा विजय जुलूस निकालेगी या नहीं, यह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तय नहीं करेंगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि विजय जुलूस निकाला जाएगा। पुलिस में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। विजय जुलूस में हजारों की तादाद में भाजपाई शामिल हुए। हालांकि रायगंज से विजयी भाजपा सांसद व वर्तमान में केंद्रीय महिला व बाल विकास राज्यमंत्री देवश्री चौधरी शामिल नहीं हुईं।

घोष ने बताया कि विजय जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से काफी पहले ही अनुमति ले ली गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक से विजय जुलूस नहीं निकालने देने की घोषणा कर देंगी तो वे इसे नहीं मानेंगे। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भाजपा को बंगाल में कहीं भी विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं देने की घोषणा की थी।

उन्होंने कहा था कि भाजपा ने रुपये के बल पर बंगाल में 18 लोकसभा सीटें जीती हैं। वह अभी बंगाल की सत्ता पर काबिज नहीं हुई है जो चुनावी नतीजे आने के 14 दिन बाद भी विजय जुलूस निकाले। मुख्यमंत्री ने कड़े लहजे में यह भी कहा था कि मनाही के बावजूद अगर कहीं विजय जुलूस निकाला गया और हिंसा हुई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता में आयोजित होने वाला बीफ फूड फेस्टिवल स्थगित

जासं, कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में कुछ दिनों बाद होने वाले बीफ फूड फेस्टिवल को सुरक्षा करणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी गई। इससे पहले 23 जून को मध्य कोलकाता के सुडर स्ट्रीट के एक कैफे में होने वाले 'कोलकाता बीफ फेस्टिवल' का नाम बदलकर 'कोलकाता मीट फेस्टिवल' कर दिया गया था। इवेंट कराने वाली कंपनी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, हमें डर है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए। चीजें अब हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। इन सभी कारणों के चलते 'कोलकाता बीफ फेस्टिवल' को रद किया जाता है।

इवेंट मैनेजमेंट टीम ने आगे लिखा, हमारी टीम के सदस्यों में से एक को कल 300 से अधिक कॉल आए, जिनमें कार्यक्रम को लेकर समर्थन से कहीं अधिक कॉल धमकी भरे रहे थे। टीम के सदस्यों में से एक ने कहा, मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं, इसके अलावा मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी निष्क्रिय करना पड़ा है। मुझे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी फोन आए हैं। उन्होंने दोहराया कि घटना का राजनीति या धर्म से कोई लेना-देना नहीं था। कई प्रकार के बीफ की तैयारी के साथ फेस्टिवल का उद्देश्य अच्छे भोजन का जश्न मनाने का था।

आखिर सीबीआइ दफ्तर पहुंचे कोलकाता के पूर्व सीपी राजीव

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- सारधा चिटफंड घोटाले में चार घंटे की गई पूछताछ, बयान रिकॉर्ड

सारधा चिटफंड घोटाले के मामले में आइपीएस अफसर व कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त (सीपी) राजीव कुमार आखिरकार शुक्रवार को सॉल्टलेक स्थित सीबीआइ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सीबीआइ की जांच टीम ने उनसे चार घंटे तक पूछताछ की। हालांकि, सीबीआइ कार्यालय से निकलने के बाद राजीव कुमार बिना किसी से कुछ भी बातचीत किए चले गए। राजीव कुमार के पूरे बयान को रिकॉर्ड भी किया गया है।

गौरतलब है कि पिछले महीने ही सीबीआइ ने नोटिस जारी कर राजीव कुमार को उपस्थित होने को कहा था, पर उन्होंने सीबीआइ को चिट्ठी लिखकर छुट्टी का हवाला देते हुए कुछ और दिनों की मांग की थी। यही नहीं, पिछले माह ही राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआइ ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। उनकी तलाश में सीबीआइ टीम उनके आवास पर भी पहुंची थी।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से हटाई रोक, हाई कोर्ट ने दी राहत : फरवरी में शिलांग में राजीव कुमार से पांच दिनों के भीतर करीब 40 घंटे पूछताछ की गई थी, परंतु, उनके बयान से संतुष्ट नहीं होने पर सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की

राजीव कुमार फाइल

मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुमार पर लगी गिरफ्तारी की रोक हटा ली थी। हालांकि, इस बीच हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है, लेकिन उन्हें पूछताछ व जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं सारधा चिटफंड मामले में ही इसी सप्ताह दो दिन आइपीएस अर्णव घोष से लगातार दो दिनों तक पूछताछ की गई है।

सीबीआइ द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने पर सुबह 10.45 बजे ही राजीव कुमार सीबीआइ कार्यालय सीजीओ कॉम्पलेक्स पहुंच गए थे। सीबीआइ की टीम ने उनसे दो चरण में पूछताछ की। पहले सुबह 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई। बीच में 15 मिनट का ब्रेक दिया गया। उसके बाद फिर दो घंटे पूछताछ की गई।

स्कूलों की तरह अब सरकारी अस्पतालों में गूंजेगा गायत्री मंत्र

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

- स्त्री रोग विभाग, प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थियेटर में सुबह चलेगा गायत्री मंत्र, दिन में पुराना संगीत

हरियाणा में सरकारी स्कूलों की तरह अब अस्पतालों में भी गायत्री मंत्र गूंजेगा। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पीड़ा कम करने के लिए स्त्री रोग विभाग, प्रसव कक्ष और ऑपरेशन थियेटर में म्यूजिक सिस्टम पर गायत्री मंत्र सुनाया जाएगा। डिलीवरी के दौरान हीलिंग साउंड थैरेपी से प्रसव पीड़ा कम होगी और प्रसूता का ब्लड प्रेशर भी सामान्य बना रहेगा। विभिन्न अस्पतालों के गायनी वॉर्डों में मरीजों के लिए टोकन सिस्टम पहले ही लागू किया जा चुका।

केंद्र सरकार की 'लक्ष्य' योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में महिलाओं को हीलिंग थैरेपी देने के लिए जोर-शोर से काम शुरू हो गया है। अस्पतालों के गायनी वार्ड, लेबर रूम और ऑपरेशन थियेटर में स्पीकर लगाए जाएंगे जिन पर सुबह गायत्री मंत्री का जाप चलेगा। इसके बाद दिन में पुराना संगीत बजाया जाएगा। योजना को पूरी तरह कारगर बनाने के लिए स्वास्थ्य निदेशालय ने गायनी वॉर्ड और लेबर रूम में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

पड़ोसी प्रदेश राजस्थान सहित दूसरे राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू इस योजना के अच्छे नतीजे आए हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर मुस्लिमों के विरोध के चलते योजना खटाई में भी पड़ी, लेकिन हरियाणा में इसकी संभावनाएं कम हैं। चिकित्सकों का दावा है कि गर्भावस्था के दौरान संगीत थैरेपी महिला और बच्चे के लिए बेहतर होती है। गर्भावस्था के दौरान महिला में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जिससे प्रसूताओं की मनोस्थिति बदल जाती है। गायत्री जाप और संगीत सुनने से लेबर रूम का न सिर्फ माहौल अच्छा होगा, बल्कि प्रसूताओं के मानसिक स्तर में भी सुधार होगा।

स्कूलों में प्रयोग रहा कारगर : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पिछले साल प्रार्थना की शुरुआत गायत्री मंत्र और समापन राष्ट्रगान के साथ खत्म करने का सिलसिला शुरू किया गया था जिसके बेहतर नतीजे आए हैं। 20 मिनट की प्रार्थना सभा में छात्रों को गायत्री मंत्र का सही उच्चारण और इसका अर्थ बताया जाता है। इससे छात्रों का ध्यान बढ़ा और वे बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इस साल बारहवीं की बोर्ड परीक्षा में जहां निजी स्कूलों का पास प्रतिशत 72.61 फीसद पर सिमट गया, वहीं सरकारी स्कूलों के 76.39 फीसद बच्चों ने सफलता पाई जो पिछले सात वर्षों में सर्वाधिक है।

दिल्ली से कोलकाता जाकर मुस्लिम वकील ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे

जासं, कोलकाता : दिल्ली के जाने माने वकील डॉ. सैयद अहमद ने कोलकाता पहुंच कर 'जय श्रीराम' के नारे लगाए। अनोखे अंदाज में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध करते हुए उन्होंने शहर के कई स्थानों पर नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ जुट गई और उसने भी नारे लगाए।

हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलते ही डॉ. अहमद ने ब्रिज के पास 'जय श्रीराम' का नारा लगाया। इसके बाद हावड़ा ब्रिज पार करने के बाद भी उन्होंने नारेबाजी की। खास बात यह रही उन्हें ऐसा करते देख भारी संख्या में एकत्र हुए स्थानीय लोगों ने भी नारे लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गलत तरीके से मुस्लिमों को बरगला कर तमाम सियासी पार्टियां अपनी रोटी सेंकती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भाजपा पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाने वाली राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 'जय श्रीराम' के नारे पर आपत्ति ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने भविष्य की राजनीति को लेकर बेहद चिंतित हैं। मुख्यमंत्री पर मुस्लिमों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज का मुसलमान विकास के साथ है, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ऐसे में कई बार 'जय श्रीराम' का नारा लगा उन्होंने यह बताने की कोशिश की वह मुस्लिम होने के बावजूद भगवान राम का सम्मान करते हैं।

दैनिक जागरण के सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म विश्वास.न्यूज की पड़ताल में सामने आया सच

फर्जी है एमपी के बैतूल में खजाना मिलने का दावा

विश्वास.News
क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है
www.vishvasnews.com

जेएनएन, नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर खजाने के नाम पर सोने के सिक्कों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि यह खजाना मध्य प्रदेश के बैतूल में एक डैम की खोदाई के वक्त मिला। विश्वास न्यूज की टीम की पड़ताल में यह दावा फर्जी साबित हुआ। बैतूल से कोई खजाना नहीं मिला है। दरअसल जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो इटली के कोमो शहर में पिछले साल मिले खजाने की हैं।

पड़ताल: विश्वास न्यूज की टीम ने सबसे पहले वायरल तस्वीरों को ध्यान से देखा। चार तस्वीरें सोने के सिक्कों की हैं तो एक तस्वीर में स्थानीय लोग दिख रहे हैं। टीम ने सोने के सिक्कों वाली तस्वीरों को गूगल रिवर्स इमेज टूल में डालकर सर्च किया तो कई ऐसी वेबसाइट के लिंक मिले, जहां इन सिक्कों की सच्चाई बताई गई थी। एक ऐसा ही लिंक टीम को इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट का मिला। जिसमें 11 सितंबर 2018 को एक खबर प्रकाशित की गई, जिसकी हेडिंग थी : **Amphora filled with hundreds of Roman gold coins found during archaeological dig in Italy.** खबर में बताया गया कि इटली के कोमो शहर में एक थिएटर के बेसमेंट में खोदाई के दौरान हजारों सोने के सिक्के मिले। ये सिक्के हजारों साल पुराने हैं। फिर टीम ने **InVID** टूल की मदद से इटली सरकार के ट्विटर हैंडल को देखा तो वहां एक ट्वीट के साथ वायरल तस्वीरें मिलीं। इतालवी भाषा में किए गए इस ट्वीट को टीम ने गूगल ट्रांसलेट की मदद से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। ट्वीट कुछ इस प्रकार है, कोमो शहर के मध्य में पुराने सोने के सिक्के मिले। इसके बाद टीम ने मध्य प्रदेश स्थित बैतूल के नई दुनिया अखबार से संपर्क किया तो पता चला कि किया जा रहा दावा झूठा है।

क्या है वायरल पोस्ट में?
देवेंद्र सोनी (@devendra.sony.7) नाम के फेसबुक यूजर ने 4 जून को पांच तस्वीरों को अपलोड करते हुए लिखा : ग्राम पंचायत खेड़ली गांव रावण बाड़ी बैतूल में डैम की खोदाई करते वक्त अंग्रेजों के जमाने का खजाना!!!! इस पोस्ट को अबतक 125 लोग शेयर कर चुके हैं।

झूठी खबर और अफवाहों की हकीकत जानने के लिए वाट्सएप करें:
9205 270 293

खंडन

संस्था ने ऑस्कर विजेता ननद-भाभी को फिल्म के अन्य कलाकारों की तरह बताया, कहा, दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने की तैयारी के चलते स्नेहा नहीं कर रही थी काम

एक्शन इंडिया ने सुमन और स्नेह के आरोपों को नकारा

जागरण संवाददाता, हापुड़

ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म की मुख्य कलाकार स्नेह और उनकी भाभी सुमन द्वारा एक्शन इंडिया नामक संस्था पर उन्हें सेवामुक्त करने के आरोप लगाने के बाद संस्था का प्रशासनिक विभाग सामने आया है। शुक्रवार को संस्था के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सुमन और स्नेह अन्य कलाकारों की तरह ही फिल्म की पात्र हैं। लघु फिल्म किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर आधारित नहीं है, बल्कि सेनेटरी पैड यूनिट स्थापित करने तथा उससे ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक करने की कहानी है।

एक्शन इंडिया के प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्नेह ने संस्था की काठीखेड़ा इकाई में 15 अगस्त 2018 तक कार्यकर्ता के रूप में काम किया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने के लिए तैयारी करने के कारण काम नहीं किया। इसलिए वह संस्था

ऑस्कर अवार्ड विजेता सुमन और स्नेह। फाइल

की कार्यकर्ता नहीं रहीं। 25 जनवरी को काठीखेड़ा इकाई पर बनाई गई लघु फिल्म 'पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस' ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुई। इस फिल्म में स्नेह और सुमन भी अन्य महिलाओं और कार्यकर्ताओं की तरह ही पात्र हैं। संस्था से अलग होने के बाद भी संस्था ने उन्हें ऑस्कर के लिए अमेरिका के लॉस एंजिलिस में भेजने का निर्णय लिया। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने और वहां रहने का समस्त खर्च संस्था के सहयोग से किया गया। इसलिए संस्था पर दो-चार हजार रुपये नहीं देने के आरोप निराधार है।

सुमन ने कहा, संस्था दे रही गलत जानकारी : ऑस्कर पुरस्कार फिल्म की मुख्य पात्र सुमन ने कहा कि उनकी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किए जाने के बाद पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था ने ई-मेल कर जानकारी दी थी। इसकी सूचना संस्था ने उन्हें नहीं दी। जब पुरस्कार प्रदाता संस्था ने उन्हें और स्नेह को साथ लाने पर जोर दिया तब संस्था उन्हें अमेरिका ले जाने पर मजबूर हुई। इसके बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खर्चा कर पासपोर्ट बनवाया। अमेरिका में होने वाला खर्चा एक अन्य संस्था ने वहन किया। इंडिया एक्शन संस्था द्वारा उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं।

यह है मामला : गांव काठीखेड़ा निवासी सुमन वर्ष 2010 में एक्शन इंडिया संस्था से जुड़ीं, जबकि स्नेह जनवरी 2017 में जुड़ी। दोनों सबला केंद्र में सेनेटरी नैपकिन बनाने और बेचने का काम करती थीं। तीन माह पहले उनकी फिल्म 'पीरियड : एंड ऑफ सेंटेंस' को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्नेह और सुमन समेत उनकी नौ साथियों को पुरस्कार के रूप में एक-एक लाख रुपये दिए थे। आरोप है कि एक्शन इंडिया नामक संस्था के पदाधिकारियों ने सुमन से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिए गए एक लाख रुपये को संस्था को देने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने संस्था छोड़ने के लिए दबाव बनाया। इस दबाव के कारण सुमन और स्नेह ने मजबूरी में नौकरी छोड़ दी। उन लोगों ने संस्था पर डेढ़ माह का वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है।

सरकारी गवाह बनना चाहती हैं इंद्राणी, फैसला 4 जुलाई को

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- आइएनएक्स मीडिया में मामले में पूर्व वित्तमंत्री चिदंबरम आरोपित
- पुत्र कार्ति चिदंबरम के खिलाफ भी दर्ज है मामला

आइएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में सरकारी गवाह बनाने की आइएनएक्स मीडिया की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट 4 जुलाई को फैसला सुनाएगी। 24 मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी आरोपित हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पी. चिदंबरम व उनके बेटे व सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ अलग-अलग मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी पता लगा रही है कि कार्ति चिदंबरम को 2007 में कैसे विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) से आइएनएक्स मीडिया के लिए मंजूरी मिली। इस दौरान उनके पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। अब तक की जांच में सामने आया है कि एफआइपीबी की स्वीकृति के लिए आइएनएक्स मीडिया के निदेशकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी. चिदंबरम से मुलाकात की थी, ताकि उनके आदेश में कोई देरी नहीं हो। सरकारी गवाह बनने की इंद्राणी मुखर्जी की याचिका का जांच एजेंसी ने समर्थन किया है।

सीबीआइ ने अदालत में कहा था कि इंद्राणी के गवाह बनने से सुबूत जुटाने में मदद मिलेगी। अदालत ने सुनवाई के दौरान मुखर्जी से पूछा था कि क्या उन पर इसके लिए कोई दबाव है, जिससे उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने खुद सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई थी। इंद्राणी मुंबई की भायखला जेल में बेटी शीना बोरा की हत्या के जुर्म में सजा काट रही है।

4 चार्जमैन गोलाबारूद की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने पर निलंबित कर दिए गए हैं मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थित आयुध निर्माणी खमरिया (ओएफके) में। वरिष्ठ महाप्रबंधक अरविंद कुमार अग्रवाल ने सैन्य टीम के दौरे के तत्काल बाद मिली रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई की है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 8 जून 2019

सीबीएसई संबद्धता के लिए एकलव्य विद्यालय 30 तक करें आवेदन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आदिवासी बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए चल रहे एकलव्य आवासी विद्यालयों को 30 जून तक संबद्धता के लिए आवेदन करने की इजाजत दी है। सीबीएसई ने विशेष मामले के तौर पर इन विद्यालयों की संबद्धता के लिए समय बढ़ाते हुए विशेष लिंक तैयार किया है। इसके जरिये विद्यालय सीबीएसई से संबद्धता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये विद्यालय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत आते हैं।

जनजातीय मंत्रालय के अवर सचिव पीके साहू ने एकलव्य विद्यालयों की सीबीएसई से संबद्धता के बारे में आ रही दिक्कतों का हल निकलने की जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि अभी तक कुल 433 एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूलों, पांच एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल और दो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्टस को मंजूरी दी जा चुकी है। गत फरवरी में हुई लोक लेखा समिति (पीएसी) बैठक में पेश रिकार्ड के मुताबिक इनमें से 226 स्कूल चालू हो चुके हैं जिनमें से 68 स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता मिल चुकी है और कई ने संबद्धता के लिए आवेदन कर रखा है। 17 जनवरी से 7 मार्च के बीच कई राज्यों ने मंत्रालय को बताया कि सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन करने में कई दिक्कतें आ रही हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि अन्य सरकारी महकमों के तहत आने वाले स्कूलों को 2018 के नियमों के तहत संबद्धता दी जाती है उसी तरह एकलव्य विद्यालयों को भी दी जाएगी।

हरियाणा के कांग्रेसियों की लड़ाई राहुल के दरबार पहुंची

बढ़ा विवाद ▸ जयतीर्थ दहिया ने भेजी अशोक तंवर की शिकायत

शिकायत में कहा–बैठक के बाद मुझे गालियां दी गईं, अब बताओ मैं क्या करूं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा में कांग्रेस की कलह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अशोक तंवर को हटाने के लिए हाईकमान पर दबाव बढ़ा दिया है। कांग्रेस के 17 विधायकों में से 13 तंवर को हटाने के हक में हैं। ये सभी विधायक हुड्डा खेमे के हैं। अगले एक पखवाड़े में यदि तंवर को प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया तो हुड्डा समर्थक विधायक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसकी नींव नौ जून को दिल्ली में होने वाली हुड्डा समर्थकों की खास बैठक में पड़ सकती है।

10 साल तक सूबे के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नौ जून को दिल्ली में अपने खास समर्थकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक को हालांकि लोकसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा करने और विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में पेश किया जा रहा है। मगर हुड्डा समर्थक विधायक अशोक तंवर के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित करने के साथ ही सर्वसम्मति से उन्हें पद से हटाने की मांग कर सकते हैं। हुड्डा समर्थक विधायकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में संगठन की कमी के कारण पार्टी की हार हुई है। इसका ठीकरा अशोक तंवर के सिर फोड़ा जा रहा है। तंवर के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव इसलिए लाया जा सकता है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद राई से विधायक जयतीर्थ दहिया को गालियां दी हैं।

हुड्डा समर्थकों की घेराबंदी में फंसे अशोक तंवर ने अपने पद से इस्तीफा देने की बजाय यहां तक कह दिया कि उन्हें गोली मार दो, लेकिन हुड्डा समर्थक तंवर के इस बयान को इमोशनल ड्रामा करार दे रहे हैं। उनकी दलील है कि तंवर के ऐसा कहने से संगठन का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले साढ़े चार साल में तंवर न तो जिला अध्यक्षों की घोषणा कर पाए और न ही ब्लॉक प्रधान नियुक्त कर सके। विधायकों को पार्टी कार्यक्रमों की सूचना तक नहीं दी जाती। हुड्डा समर्थक कुछ नेता कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी से भी खुश नहीं हैं। हालांकि किरण को कई मौकों पर हुड्डा के खेमे में खड़ा देखा गया है, लेकिन उन पर तंवर खेमे की छाप लगी हुई है।

हुड्डा समर्थक विधायक तंवर के विरुद्ध राई से एमएलए जयतीर्थ दहिया की उस शिकायत को ढाल बना रहे हैं, जो उन्होंने शुक्रवार को राहुल गांधी को भेजी है।

09 जून की बैठक में 13 विधायक बनाएंगे तंवर को हटाने का दबाव

कांग्रेस दिग्गजों की लड़ाई से हाईकमान असहज

पार्टी हाईकमान राज्य के कांग्रेसियों की इस लड़ाई से बेहद असहज महसूस कर रहा है। राज्य में कांग्रेस आधा दर्जन गुटों में बंटी हुई है। रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई और कु. सैलजा का अलग गुट है, जबकि तंवर गुट के साथ किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव और अवतार सिंह भड़ाना खड़े हैं। बाकी नेता हुड्डा खेमे के गिने जाते हैं। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम चल रहे हैं।

आइआइटी जोधपुर के सहायक प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप

जागरण संवाददाता, नोएडा : आइआइटी जोधपुर के एक सहायक प्रोफेसर पर महिला से दुष्कर्म व मारपीट के मामले में कोतवाली सेक्टर 20 में एफआइआर दर्ज की गई है। पीड़िता का आरोप है कि नौकरी के सिलसिले में बातचीत करने के लिए सेक्टर 16ए फिल्म सिटी स्थित गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस में प्रोफेसर से मिलने आई थी। इस दौरान आरोपित ने गेस्ट हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया।

सेक्टर 20 पुलिस के अनुसार मूलरूप से राजस्थान की रहने वाली पीड़िता दिल्ली में रहती है। वह निजी कंपनी में काम करती है। आरोपित सहायक प्रोफेसर विवेक विजयवर्गीय को वह वर्ष 2000 से जानती है। उस दौरान आरोपित ने उसे कोचिंग में पढ़ाया था। पीड़िता ने कुछ माह तक उनके साथ आइआइटी जोधपुर में भी काम किया। पीड़िता का आरोप है कि बुधवार शाम विवेक ने उसे फोन कर नोएडा में गेस्ट हाउस में बुलाया था। वह यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आया था। पीड़िता ने बताया कि कुछ माह पहले उसने अपना रिज्यूम आरोपित को मेल किया था। बातचीत के बाद नौकरी की चर्चा को लेकर बृहस्पतिवार दोपहर करीब सवा 11 बजे वह गेल के गेस्ट हाउस में पहुंची थी। जहां सहायक प्रोफेसर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर मारपीट की। कोतवाली सेक्टर 20 प्रभारी राजबीर सिंह चौहान ने बताया कि शिकायत पर आइआइटी जोधपुर में कार्यरत 45 वर्षीय प्रोफेसर के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। मामले की जांच चल रही है।

वर्तमान में 14 राज्यों में हैं उप मुख्यमंत्री

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने नया राजनीतिक प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी कैबिनट में एक साथ पांच उप मुख्यमंत्रियों को रखने का फैसला किया है। वर्तमान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में उप मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ गोवा और उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं। इनमें से आठ भाजपा के हैं, जबकि दो कांग्रेस के हैं।

किन प्रदेशों में कितने उप मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश: दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य
दिल्ली: मनीष सिसोदिया
गोवा: विजय सरदेसाई, मनोहर अजगाओंकर
बिहार: सुशील कुमार मोदी
गुजरात: नितिन भाई पटेल
राजस्थान: सचिन पायलट
तमिलनाडु: ओ पन्नीरसेल्वम
त्रिपुरा: जिष्णु देव वर्मा
कर्नाटक: जी परमेश्वर
मणिपुर: वाई जॉय कुमार सिंह
मेघालय: प्रेस्टन तिनसंग
मिजोरम: त्वानलुइया
नगालैंड: वाई पैटन

संविधान में नहीं है कोई व्यवस्था : उप प्रधानमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकारें अक्सर किसी को संतुष्ट करने या फिर किसी अन्य जरूरत के चलते इन पदों का इस्तेमाल करती हैं। इनकी सीमा निर्धारित नहीं है।

डिफेंस एयरपोर्ट से खत्म हो सकता है लैंडिंग चार्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 80 से कम सीटों वाले विमानों के लिए 15 डिफेंस एयरपोर्ट से से लैंडिंग चार्ज खत्म कर सकती है। सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विमान कंपनी को एयरपोर्ट पर हर लैंडिंग के लिए अपने विमान के वजन के हिसाब से लैंडिंग चार्ज चुकाना पड़ता है। डिफेंस एयरपोर्ट भारतीय वायु सेना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'उड्डयन मंत्रालय से एक एयरलाइन ने 80 से कम सीटों वाले विमान के लिए 15 डिफेंस एयरपोर्ट पर लैंडिंग चार्ज खत्म करने का अनुरोध किया है। यह तय किया गया है कि विभाग के सचिव जल्द ही इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखेंगे। जिन शहरों में ये 15 डिफेंस एयरपोर्ट स्थित हैं वहां से 80 से कम सीटों वाले विमान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं।'

सांसद बनने के बाद पहली बार एनआइए कोर्ट में पेश हुईं प्रज्ञा ठाकुर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

एनआइए कोर्ट पहुंची साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। एएफपी

▸ कहा, मालेगांव धमाके के बारे में कोई जानकारी नहीं

▸ सांसद चुने जाने के बाद वह कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहती थीं

भोपाल से सांसद चुने जाने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शुक्रवार को पहली बार मुंबई के विशेष एनआइए कोर्ट में पेश हुईं। वहां जज ने उनसे दो सवाल पूछे, जिसका जवाब उन्होंने 'न' में दिया।

2008 में हुए मालेगांव विस्फोट कांड की आरोपित साध्वी प्रज्ञा को गुरुवार को ही एनआइए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए छूट ले ली थी। शुक्रवार को वह कोर्ट पहुंचीं। दो अन्य आरोपित सुधाकर द्विवेदी एवं समीर कुलकर्णी भी मौजूद थे। एनआइए कोर्ट के विशेष जज विनोद पाडलकर ने तीनों से सवाल पूछे। पहला, क्या आप लोग जानते हैं या आपके वकील ने बताया है कि अब तक कितने गवाह पेश हो चुके हैं? साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि नहीं मालूम, जबकि सुधाकर द्विवेदी ने कहा कि 116 गवाह पेश हो चुके हैं। दूसरा, पेश सभी गवाहों ने बताया है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। आपका क्या कहना है? प्रज्ञा एवं द्विवेदी ने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, समीर कुलकर्णी ने कहा कि यह सच है।

इससे पहले साध्वी प्रज्ञा अक्टूबर 2018 में मालेगांव विस्फोट कांड का आरोप तय होते वक्त एनआइए कोर्ट में हाजिर हुई थीं। सांसद चुने जाने के बाद वह कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट चाहती थीं, लेकिन जज ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का हवाला देते हुए उन्हें अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे, जिसमें जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध चल रहे मामलों को जल्द निपटाने पर जोर दिया गया है। जज ने सभी सात आरोपितों को सप्ताह में कम से कम एक बार कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है।

ढाई घंटे तक कोर्ट में खड़ी रहीं : साध्वी प्रज्ञा अपने दो सहायकों के सहारे दोपहर 12.45 बजे कोर्ट में पहुंची थीं। कार्यवाही शुरू होने से पहले कोर्ट में उनके एक सहायक ने आरोपितों के बैठने के स्थान पर एक लाल आसनी बिछाई, जिस पर वह बैठीं। इसके बाद सुधार द्विवेदी से मुंबई की खराब यातायात व्यवस्था पर बात करती रहीं। कार्यवाही शुरू होने पर जज ने मानवीय आधार पर उन्हें कुर्सी पर बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने खड़े रहने की इच्छा जताई। मध्यावकाश में जज अपने चैंबर में चले गए तो साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में अपने वकील पर झल्लाती दिखीं।

पत्रकार राघव बहल के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लांड्रिंग का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पत्रकार राघव बहल के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। उन पर विदेश में अघोषित संपत्ति खरीदने के लिए मनी लांड्रिंग का आरोप है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राघव के खिलाफ आयकर विभाग की शिकायत और आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए ईडी ने इसी हफ्ते की शुरुआत में उनके खिलाफ इंफोर्समेंट केस इंफॉरमेशन रिपोर्ट (ईसीआइआर) दर्ज की है। यह पुलिस की एफआइआर के समकक्ष होती है। उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आयकर विभाग ने हाल ही में राघव बहल के खिलाफ मेरठ की अदालत में कालाधन निरोधी कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था।

ईडी की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए राघव बहल ने आरोप लगाया कि सभी करों का ईमानदारी और तत्परतापूर्वक भुगतान करने के बावजूद बिना कोई गलत काम किए उन्हें उनका शिकार किए जाने का अहसास हो रहा है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और ईडी के प्रमुखों को ईमेल के जरिये पत्र भेजे हैं।

केरल के तट पर आज पहुंचेगा मानसून, गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली, प्रेट्र/रायटर : भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने कहा है कि 24 घंटे में मानसून केरल तट पर पहुंच जाएगा। वैसे केरल में मानसून पहली जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार इसमें एक हफ्ते की देरी हुई है।

आइएमडी ने अपने मानसून बुलेटिन में कहा, 'इसके (मानसून) धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व की ओर रुख करने की बहुत संभावना है, जिससे केरल में 8 जून के आसपास दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है।' मौसम विभाग ने इस बार मानसून के सामान्य रहने का भी पूर्वानुमान जताया है।

मानसून के केरल पहुंचने के हफ्ते भर बाद ही देश के उत्तरी क्षेत्रों को प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पास तक पहुंच गया है। हालांकि, शुक्रवार को दिल्ली को गर्मी से कुछ राहत मिली, क्योंकि अधिकतम पारा गिरकर 44 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 40.2 डिग्री पर आ गया था।

उप्र में आंधी–बारिश का कहर, नौ लोगों की मौत

जेएनएन, लखनऊ : उप्र के अधिकांश भू-भाग में गुरुवार रात आंधी, बारिश के साथ ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। विद्युत पोल, पेड़ गिरे। सैकड़ों गांवों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। इस दौरान नौ लोगों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में आंधी-पानी से तापमान करीब तीन डिग्री लुढ़क कर 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य के मुकाबले एक डिगरी कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान में गुरुवार के मुकाबले सात डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

जून में औसत से कम बारिश : मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जून महीने में औसत से कम बारिश होने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश होगी।

जम्मू में सैन्य प्रतिष्ठानों का वीडियो बनाते चार पाकिस्तानी जासूस पकड़े

राज्य ब्यूरो, जम्मू

सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से हताश पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी (आइएसआइ) जम्मू संभाग में किसी बड़े सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इसका पर्दाफाश राज्य पुलिस की ओर से छह सदस्यीय जासूसी मॉड्यूल से पूछताछ के आधार पर किया गया है। फिलहाल पकड़े गए चार जासूसों से पूछताछ जारी है।

यह मॉड्यूल आइएसआइ के कर्नल इफ्तिखार अहमद और हिज्ब कमांडर आमीर खान से सीधे संपर्क में था। आइएसआइ सिर्फ किसी बड़े हमले को अंजाम ही नहीं देना चाहती है बल्कि ऊधमपुर, डोडा और कठुआ में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश में भी है। फिलहाल पकड़े गए जासूसों से पूछताछ जारी है। स्मार्ट फोन के जरिए सीमा पार पहुंचाए गए वीडियो फुटेज और तस्वीरों के अलावा उनके वाट्सएप डाटा को भी खंगाला जा रहा है।

सैन्य प्रतिष्ठान की वीडियो बनाते पकड़े गए थे युवक : इस मॉड्यूल की गिरफ्तारी का सिलसिला करीब 11 दिन पहले जम्मू के बाहरी क्षेत्र रतनूचक में स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान की वीडियोग्राफी करते पकड़े गए मुश्ताक अहमद मलिक पुत्र अत्ता मुहम्मद निवासी शीलं बंदास डोडा और नदीम अख्तर पुत्र मुहम्मद शफी निवासी मलार कठुआ की पूछताछ से शुरू हुआ। इन दोनों से मिले सुरागों के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने सद्दाम हुसैन पुत्र मुहम्मद बट, सफदर अली पुत्र मुहम्मद यूनुस, मुहम्मद सलीम पुत्र कमरदीन और अब्दुल करीम पुत्र मुहम्मद शफी को पकड़ा। इनमें सफदर अली ही जिला ऊधमपुर में खनेड़ का रहने वाला है, जबकि अन्य तीन जिला कठुआ के लोहाई इलाके के रहने वाले हैं। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि मुश्ताक अहमद मलिक का एक रिश्तेदार पहले जिला डोडा का नामी आतंकी था। बाद में वह गुलाम कश्मीर चला गया था। उसने ही सबसे पहले इस मॉड्यूल को तैयार किया। पकड़े गए यह सभी लोग जिला कठुआ, ऊधमपुर और डोडा में हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क तैयार करने में जुटे थे। इन्होंने खुद अभी किसी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दिया था।

आइएसआइ के कर्नल से वाट्सएप और मोबाइल एप से होती थी बातचीत : पूछताछ में इन्होंने बताया कि आइएसआइ के कर्नल इफ्तिखार के साथ उनकी वाट्सएप और एक अन्य मोबाइल एप के जरिए बातचीत होती थी। कर्नल इफ्तिखार के साथ उनका संपर्क सीमा पार बैठे एक आतंकी ने कराया था। उसने ही हिज्ब कमांडर आमिर खान से भी इनका संपर्क कराया था। कर्नल इफ्तिखार के निर्देशानुसार ही वह विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों की वीडियोग्राफी कर उसे पहुंचाते थे।

सिर्फ जासूसी नहीं था काम : पकड़े गए छह जासूसों से पूछताछ कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि यह सिर्फ जासूसी का काम ही नहीं कर रहे थे बल्कि ऊधमपुर, डोडा और कठुआ में हिज्ब का नेटवर्क संभालने की तैयारी भी कर चुके थे। अगर यह पकड़े नहीं जाते तो कश्मीर में या फिर जिला किश्तवाड़ या डोडा के किसी जंगल में आतंकी ट्रेनिंग ले रहे होते। क्योंकि सीमा पार से इन्हें आदेश था कि पहले वह कुछ इलाकों की वीडियोग्राफी कर भेजें। उसके बाद वह डोडा या किश्तवाड़ पहुंचे, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।

सोपोर में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला, दो जवान घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के सोपोर में शुक्रवार को आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला किया। इसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। वारदात के बाद आतंकी भाग निकले। हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस बीच, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

शुक्रवार दोपहर को सोपोर में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड थाना परिसर के भीतरी हिस्से में गिरा और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। इस धमाके में दो पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद और कांस्टेबल अब्दुल अजीज घायल हो गए हैं। थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने तुरंत अपनी पोजीशन संभाली और घायल साथियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां अली मोहम्मद की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, जम्मू के जिला डोडा स्थित चिल्ली-बाला गांव में सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद किया है। राष्ट्रीय राइफल्स मुख्यालय में सेना के प्रवक्ता ने बताया कि संदिग्ध लोगों के देखे जाने की सूचना पर जवानों ने तलाशी अभियान चलाया था।

ईएसआइसी मातृत्व अवकाश घोटाले में दर्ज हो सकता है केस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

ईएसआइ कारपारेशन (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) में मातृत्व अवकाश (सवेतन) हित लाभ मामले में सीबीआइ, चंडीगढ़ कभी भी केस दर्ज कर सकती है। फिलहाल तो ईएसआइसी की ऑडिट टीम बारीकी से सेक्टर-23 शाखा कार्यालय में घोटाले की जांच में जुटी है। जैसे ही जांच पूरी होगी, इस कार्यालय से संबंधित कर्मचारियों का निलंबन कर दिया जाएगा।

बता दें कि महिला कर्मी अगर किन्हीं कारणों से गर्भपात (तीन माह की गर्भावस्था) करा लेती हैं तो 42 दिन, दो बच्चों के जन्म के बाद महिला अगर तीसरे बच्चे को जन्म देती है तो उसे 84 दिन तथा पहले या दूसरे बच्चे के जन्म पर 182 दिन मातृत्व अवकाश (सवेतन) हित लाभ मिलता है। ईएसआइसी की इस योजना का लाभ लेने को ही ठेकेदार ने घोटाले का खेल खेला था।

ईएसआइसी के अधिकारी कहते हैं कि अब उनका फोकस सेक्टर-23 शाखा कार्यालय की जांच को पूरा करना है, साथ ही सीबीआइ की ओर से केस दर्ज किए जाने का इंतजार है। केस दर्ज होने के साथ ही सीबीआइ की टीम जांच का दायरा बढ़ाएगी। हो सकता है कि फरीदाबाद में सीबीआइ की कार्रवाई पूरी होने के बाद ईएसआइ मुख्यालय की ओर से देश के अन्य शहरों में भी सीबीआइ से जांच कराई जाए। फिलहाल तो ईएसआइसी की ऑडिट टीमें देश भर के शाखा कार्यालय का मातृत्व अवकाश हित लाभ मामले की जांच कर रही हैं।

> हमने सीबीआइ, चंडीगढ़ को पहले ही केस दर्ज करने को लिख कर दिया है। हमारी ऑडिट टीम अपने स्तर पर जांच कर रही हैं। अभी तक सीबीआइ ने मामला दर्ज नहीं किया है।
>
> **–एके रंगा, उप निदेशक (हितलाभ), ईएसआइसी।**

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कारगिल योद्धा को दी अंतरिम जमानत

गुवाहाटी, आइएएनएस : गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कारगिल योद्धा रहे मोहम्मद सनाउल्लाह को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। पिछले महीने उन्हें एक ट्रिब्यूनल ने विदेशी करार दे दिया था, जिसके बाद उन्हें हिरासत शिविर में रखा गया था। कोर्ट ने भारत सरकार, असम सरकार, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के अधिकारियों व असम पुलिस के जांच अधिकारी समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है।

जस्टिस एम. भूयान व जस्टिस पीके डेका की खंडपीठ ने 20 हजार की जमानत राशि और दो जमानतदारों की शर्त पर सनाउल्लाह की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, पीठ ने सेवानिवृत्त सैनिक सनाउल्लाह को बिना पुलिस अधीक्षक (बार्डर) की जानकारी के कामरूप नहीं छोड़ने का आदेश दिया।

सनाउल्लाह की तरफ से मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह ने मामले की पैरवी की, जबकि प्रतिवादी के वकील यूके नायर थे। हाई कोर्ट में शुक्रवार को इंदिरा जयसिंह के साथ मौजूद वकील बी. रहमा ने कहा, 'हमें जमानत आदेश मिल गया है। वह हिरासत शिविर से छोड़े जाएंगे।'

पर्दे पर झलकेगा बदायूं दुष्कर्म कांड का दर्द

आर्टिकल 15

बदायूं के कटरा सआदतगंज गांव में दरिंदगी के बाद दो बहनों को मारकर पेड़ से टांग दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जताई थी चिंता, अब मामला कोर्ट में विचाराधीन

जागरण संवाददाता, बदायूं

बदायूं में गंगा की कटरी में बसे बेहद पिछड़े गांव कटरा सआदतगंज में 26 मई 2014 को देश को शर्मसार करने वाले वाकये ने पूरी दुनिया में इसे सुर्खियों में ला दिया था। वजह भी बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली थी। दबंगई की तो इंतहा, जिसके दम पर दो सगी बहनों के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, कृत्य छिपाने के लिए दोनों को मारकर गांव के बाहर पेड़ से टांग दिया गया था। मामला मीडिया की सुर्खियां बनने पर तत्कालीन सपा सरकार जागी। एसआइटी से लेकर सीबीआइ जांच बैठी। हाई कोर्ट तक उतार-चढ़ाव आते रहे, लेकिन परिजनों को इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया। अलबत्ता, बेटियों के साथ होने वाली हैवानियत को उजागर करने की बॉलीवुड की कोशिश से एक बार फिर कटरा कांड सुर्खियों में आ गया है। घटना पर फिल्म आर्टिकल-15 बनकर तैयार है। इसी माह रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म में आरोपियों की जाति को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ब्राह्मण समाज पात्रों को लेकर आपत्ति जता रहा है।

आर्टिकल–15 का पोस्टर। फाइल

यह था घटनाक्रम: उसहैत थाना क्षेत्र के गांव कटरा सआदतगंज गांव की रहने वाली दो नाबालिग सगी चचेरी बहनें देर शाम शौच जाने की बात कहकर घर से निकली थीं। देर रात तक घर नहीं पहुंचीं। परिजन तलाश करने निकले। रात एक बजे दोनों के शव आम के बाग में पेड़ से टंगे पाए गए थे। रात में ही हंगामा मचा तो गांव के पप्पू यादव, भाई अवधेश यादव, उर्वेश यादव के अलावा कटरा चौकी पर तैनात सिपाही सत्यपाल व सर्वेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया।

जमकर हुई सियासत : इसके बाद जमकर सियासत भी हुई। शुरुआती दौर में किशोरियों के अनुसूचित जाति का होने की बात प्रचारित हुई तो बसपा प्रमुख मायावती गांव पहुंच गईं। बाद में पता चला कि किशोरियां पिछड़ी जाति के परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आए। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई।

अखिलेश सरकार में हुई घटना : मामला तूल पकड़ा तो शुरुआत में एसआइटी जांच हुई। आरोपितों को जेल भेज दिया गया। बाद में तत्कालीन अखिलेश सरकार पर और दबाव बढ़ा। जांच सीबीआइ को सौंपी मगर वह भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आखिर में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया। अदालत में चुनौती दी। स्थानीय अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा। आखिर में बदायूं की पॉक्सो कोर्ट ने रिपोर्ट खारिज कर दी। आरोपितों के खिलाफ मामला अब भी विचाराधीन है और सभी आरोपित जमानत पर हैं।

टॉयलेट : एक प्रेमकथा- फिल्म में भी कटरा सआदतगंज कांड का जिक्र आया था। इशारा था कि किस तरह घर में शौचालय न होने से इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं।

> आर्टिकल–15 फिल्म इसी माह रिलीज होने वाली है। फिल्म का विरोध कौन लोग और क्यों कर रहे हैं यह तो उन्हीं से पूछिए। इसका जवाब वही दे सकते हैं। पहले फिल्म देखिए, उसके बाद कोई सवाल कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा।
>
> **–अनुभव सिन्हा, फिल्म निर्देशक**

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अब सिर्फ दो मिनट रुकेगी ट्रेन

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

▸ एक जुलाई से लागू हो सकता है रेलवे का यह टाइम टेबल

▸ मालगाड़ी को चलाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए हो रही पहल

रेलवे के नए टाइम टेबल में देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के सिर्फ दो मिनट ठहराव की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। यह व्यवस्था अधिक से अधिक मालगाड़ी को चलाने का रास्ता प्रशस्त करने के लिए की जा रही है। हालांकि ट्रेनों का स्टापेज दो मिनट होने पर बुजुर्ग और बच्चों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में दिक्कत होगी।

रेलवे का यह टाइम टेबल एक जुलाई से लागू किया जाना है। इसे लेकर बोर्ड स्तर पर तैयारी हो रही है। रेलवे बोर्ड में इन दिनों देश के सभी रेल मंडलों के परिचालन विभाग की टीम टाइम टेबल तैयार करने में जुटी है। टीम पर अधिक से अधिक मालगाड़ी चलाने के लिए दबाव है, जिसके कारण सभी प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव का समय कम करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके अलावा छोटे स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टापेज खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। इससे मालगाड़ी संचालन को रास्ता सुगम होगा।

परिचालन विभाग की टीम के विरोध के बावजूद रेल अधिकारियों का कहना है कि देश के वे स्टेशन जहां ट्रेनों के गार्ड और चालक बदले जाते हैं और पानी भरा जाता है, वहां पर ठहराव पांच मिनट और अन्य सभी बड़े और प्रमुख स्टेशनों पर दो मिनट ठहराव करने की व्यवस्था करें। छोटे स्टेशन पर ट्रेनों का स्टापेज खत्म कर दें या एक मिनट का करें। मुरादाबाद रेल मंडल के बरेली, हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर रुकने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव पांच मिनट से घटाकर दो मिनट किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट घोषित कराने की योजना है।

48 हजार श्रद्धालु आठ दिन में हिमालय पर पांचवें धाम हेमकुंड में मत्था टेक चुके हैं। 2013 की आपदा के बाद इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। समुद्रतल से 15225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब सिखों का सबसे ऊंचा एवं पवित्र तीर्थस्थल है।

न्यूज गैलरी

दाऊद के भाई कासकर को अस्पताल में भर्ती कराएं : कोर्ट

ठाणे : स्थानीय कोर्ट ने सेंट्रल जेल के अधिकारियों को अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर को शाम तक सेंट जार्ज या जेजे अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया है। सेंट्रल जेल में बंद इकबाल की ओर से उसके वकील विशाल इंगोले द्वारा दायर अर्जी पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। मीडिया से बातचीत में इंगोले ने कहा, 'मेरा मुवक्किल मधुमेह, हाई ब्लड प्रेसर का मरीज है और पैरों में सूजन के कारण वह चल नहीं पाता है।' ठाणे पुलिस के फिरौती विरोधी सेल ने सितंबर 2017 में कासकर को फिरौती के आरोप में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)

मुंबई में क्रिकेटर की चाकू मारकर हत्या

मुंबई : मुंबई के भांडुप इलाके में पेट्रोल पंप के पास गुरुवार देर रात तीन अज्ञात हमलावरों ने एक स्थानीय क्रिकेटर की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसकी पहचान राकेश पंवार (करीब 30 वर्ष) के रूप में हुई। बचपन के मित्र होने का दावा करने वाले गोविंद राठौर ने बताया कि उत्तर पूर्व मुंबई में स्थित महावीर पेट्रोल पंप के पास जब बदमाशों ने हमला किया तब राकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। गोविंद ने कहा, 'मैं उसके साथ नहीं था। खान परिवार से उसकी पुरानी रंजिश है।' गोविंद ने बताया कि राकेश क्रिकेट कोच था। युवाओं को ट्रेनिंग देता था। (एएनआइ/आइएएनएस)

अभियान ▶ धान रोपाई से पहले सरकार किसानों तक पहुंचाएगी मशीन

पराली के धुएं से दिल्ली को बचाने की मुहिम हुई तेज

पंजाब, हरियाणा सहित प्रभावित राज्यों को 21 जुलाई तक का दिया समय, मांगा गया ब्योरा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पराली के जहरीले धुएं से दिल्ली को बचाने के लिए सरकार ने अभी से ही मुहिम तेज कर दी है। पंजाब, हरियाणा सहित पराली जलाने की घटनाओं में शामिल राज्यों से इस दिशा में मजबूत उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी से किसानों को बांटे जाने वाले उपकरणों सहित तैयारियों से जुड़ा ब्योरा भी मांगा है। पराली जलाने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सरकार ने फिलहाल 12 सौ करोड़ का बजट जारी कर रखा है। इनमें पिछले साल करीब छह सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

पराली को लेकर सरकार की चिंताओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, अभी धान की रोपाई शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोकथाम के लिए मैदान में उतर गई है। पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल यह मुहिम तब शुरू की गई, जब धान की कटाई शुरू हो गई थी। ऐसे में इससे रोकथाम के पर्याप्त उपाय नहीं हो पाए थे। बावजूद इसके पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी दर्ज हुई है। पंजाब में यह कमी 11 फीसद और हरियाणा में 29 फीसद दर्ज हुई थी। पिछले साल की खामियों से सबक लेते हुए राज्यों को इस बार खास ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए गए है। इनमें किसानों को समय पर पराली को नष्ट करने वाले कृषि उपकरण उपलब्ध कराने सहित निगरानी के लिए दस्तों को गठन और जागरूकता अभियान छेड़ने को कहा गया है। राज्यों से इसके तहत 21 जुलाई तक मशीनों की वितरण करने को कहा गया है।

वायु प्रदूषण का प्रतीकात्मक फोटो।

किराए पर भी मिलेंगी पराली नष्ट करने वाली मशीनें

पिछले साल की चूक से सबक लेते हुए सरकार ने इस बार किसानों को बिल्कुल सस्ती दरों पर पराली नष्ट करने वाली मशीनों को उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है। इसके लिए एक मोबाइल एप भी तैयार किया गया है। इसमें किसानों को दी गई मशीनों का ब्योरा रहेगा। पिछले साल कई जिलों में मशीनें खाली पड़ी थी, जबकि दूसरे कई जिलों में मशीने न बंट पाने के चलते किसानों के सामने बुआई के लिए पराली जलाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

बहू ने सास से की क्रूरता, वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, नारनौल : वाट्सएप ग्रुपों में वायरल हुई दो वीडियो क्लिप ने सास के प्रति बहू की क्रूरता की पोल खोल दी है। वीडियो क्लिप में पुत्रवधू बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटती दिख रही हैं। पुलिस ने जांच के बाद गांव निवाजनगर निवासी करीब 80 वर्षीय चांदबाई की शिकायत पर उसके बेटे घनश्याम की पत्नी कांता के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपित महिला वीडियो वायरल होने के बाद से भाग निकली है।

पुलिस ने बुजुर्ग चांदबाई को अस्पताल में भर्ती करवाया है। उधर, वीडियो क्लिप बनाकर वायरल करने वाली छात्रा को भी कांता के जेठ के लड़के विजय ने जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पुलिस ने आरोपित विजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार चांदबाई का पति बीएसएफ से बतौर इंस्पेक्टर सेवानिवृत हुए थे।

20 साल पहले उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से चांदबाई पेंशन ले रही हैं। दिल्ली निवासी सुनील की बेटी दीपिका छुट्टियों में यहां चांदबाई के पड़ोस में नानी के घर आई है। वह डीयू में पढ़ती है। जब वह छत पर बने कमरे में जा रही थी तो उसकी नजर चांदबाई की पिटाई करती उसकी बहू कांता पर पड़ी। इसके बाद दीपिका ने वीडियो बना लिया। नारनौल एसपी चंद्रमोहन ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग महिला की शिकायत पर महिला थाना में उसकी पुत्रवधू कांता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और वृद्धा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

लापता एएन-32 को तलाशने के लिए निगरानी विमान लगाए

नई दिल्ली, एएनआइ : वायुसेना के लापता एएन-32 विमान को खोजने के प्रयास लगातार जारी हैं। पांचवे दिन शुक्रवार को खोज अभियान में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के उपग्रहों के साथ-साथ नौसेना के निगरानी विमान पी-8आइ और विमानन अनुसंधान केंद्र (एआरसी) के निगरानी विमान ग्लोबल-5000 को भी लगाया गया। एएन-32 विमान की तलाश के लिए नौसेना के पी-8आइ विमान ने शुक्रवार सुबह तमिलनाडु में अराकोन्नम में आइएनएस राजाली से उड़ान भरी।

इसमें विशेष तरह के रडार और सेंसर लगे हुए हैं। इससे पहले भी इस अभियान में पी-8आइ विमान का इस्तेमाल किया गया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एआरसी के ग्लोबल-5000 विमान में भी विशेष तरह के सेंसर लगे हुए हैं जो जमीन की बेहतर तस्वीरें उपलब्ध कराने में सक्षम हैं।

वायुसेना ने ट्वीट कर बताया, 'इलाके की छानबीन के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक, रडार, उपग्रहों समेत ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना, पुलिस, राज्य सरकार, अर्धसैनिक बल और स्थानीय लोग अभियान में अहम योगदान दे रहे हैं।' वायुसेना ने आगे कहा कि जब भी मौसम साथ देता है तब हेलीकॉप्टरों, परिवहन विमानों, मानवरहित विमानों और अन्य सेंसरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अलांग स्थित वायुसेना की पूर्वी कमान के वरिष्ठ अधिकारी खोज अभियान को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बुधवार को खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टरों के जरिये खोज अभियान को रोकना पड़ा था, लेकिन दो सुखोई-30 एमकेआइ और एक सी130जे विमानों ने रात में भी अभियान जारी रखा था। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

एनटीआरओ के उपग्रहों के साथ-साथ पी-8आइ और ग्लोबल-5000 विमान भी कर रहे तलाश

एएन-32 विमान प्रतीकात्मक

राजनाथ सिंह ले रहे नियमित जानकारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लापता विमान के खोज और बचाव अभियान की नियमित रूप से जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने लापता विमान और उसमें सवार सभी लोगों को खोजने के लिए हर मुमकिन संसाधनों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

रुपिन दर्रे से एयरलिफ्ट किए तीन घायल ट्रैकर

जागरण संवाददाता, शिमला : जिला शिमला और किन्नौर की सीमा पर स्थित रुपिन दर्रे में फंसे घायल ट्रैकरों के दल को शुक्रवार को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल लिया गया। तीन घायल ट्रैकरों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि 27 सदस्यीय दल सांगला की ओर निकल गया। घायलों को जतोग के आर्मी अस्तपाल में भर्ती करवाया गया है। सेना का हेलीकॉप्टर सुबह 6.25 बजे शिमला से रुपिन दर्रे के लिए रवाना हुआ। सात बजे के बाद घायल दो महिलाओं व एक पुरुष को सेना के हेलीकॉप्टर में शिमला पहुंचाया गया। बाकी सभी अपने गंतव्य सांगला की तरफ रवाना हो गए। एयरलिफ्ट किए ट्रैकरों को प्रशासन ने शिमला पहुंचने के बाद आर्मी के जतोग स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि ट्रैकर सुधा भट्टाचार्य के घुटने में चोट लगी है। दूसरी महिला डॉ. सुप्रिया को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। महिला ट्रैकर के पति ब्रिग्रेडियर राजा भट्टाचार्य के पांव में हल्की मोच आई है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों ट्रेकर की हालत स्थिर है। गौर रहे कि ट्रैकरों का यह दल तीन जून के जाखा पहुंचा था। चार जून को वह जाखा से किन्नौर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रुपिन दर्रे में लोअर वाटरफॉल के पास फंस गए थे।

बिलकिस बानो मामले में दोषी आइपीएस अधिकारी आरएस भगोरा बर्खास्त

अहमदाबाद, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2002 के बिल्कीस बानो मामले में दोषी करार दिए गए गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी आरएस भगोरा को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक दिन पहले 30 मई को बर्खास्त कर दिया। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। गुजरात के गृह विभाग के उप सचिव (जांच) एमआर सोनी ने कहा कि 60 वर्षीय अधिकारी 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। जिस समय बर्खास्त किए जाने का आदेश आया उस समय आइपीएस अधिकारी अहमदाबाद में पुलिस उपायुक्त (यातायात) पद पर कार्यरत थे।

सोनी ने कहा, 'राज्य के गृह विभाग को भगोरा की बर्खास्तगी के संबंध में 29 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय से सूचना मिली थी। हमने 30 मई को आदेश थमाया जिसका मतलब है कि उन्हें सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले हटाया गया।'

सरकारी रिकार्ड के अनुसार, भगोरा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी थे और उन्हें 2006 में प्रोन्नत कर आइपीएस बनाया गया था। बर्खास्त होने का अर्थ यह है कि भगोरा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के सभी लाभ से वंचित रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष मार्च में गुजरात सरकार से कहा था कि वह भगोरा सहित उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करे जिन्होंने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में कर्तव्य पालन में कोताही की थी। बांबे हाई कोर्ट ने भगोरा को दोषी ठहराया था। कर्तव्य पालन में कोताही करने वाले चार अधिकारियों में एक पुलिस उपाधीक्षक, दो इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी शामिल हैं। ये सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

- **अधिकारी के सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिया आदेश**
- **कर्तव्य पालन में कोताही पर बांबे हाई कोर्ट ने भगोरा को ठहराया था दोषी**

गोधरा कांड के बाद फैले दंगे के दौरान दाहोद जिले के रनधिकपुर गांव में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार बानो को सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। बानो के आग्रह पर शीर्ष कोर्ट ने अगस्त 2004 में मामला मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। घटना के समय पांच माह की गर्भवती बानो के साथ दुष्कर्म करने वाले 11 लोगों को मुंबई की विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दंगे के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी।

निचली अदालत ने भगोरा सहित पांच पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया था। बांबे हाई कोर्ट ने 2017 में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए इन पुलिसकर्मियों को धारा 218 (अपना कर्तव्य नहीं निभाने) और 201 (सुबूतों से छेड़छाड़) का दोषी करार दिया। शीर्ष कोर्ट ने 2017 में स्पष्ट सुबूत होने के आधार पर भगोरा की अपील खारिज कर दी थी।

मप्र के ई-टेंडर घोटाले में गिरफ्तार आइआइटियन निकला नौवीं पास

नई दुनिया, भोपाल (मप्र)

मध्य प्रदेश के ई-टेंडर घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने जिस मनीष खरे को सात दिन से गिरफ्तार कर रखा है, उसकी असलियत अब खुली है। उसे अब तक कानपुर आइआइटी से इंजीनियरिंग डिग्रीधारी समझा जा रहा था, वास्तव में वह केवल नौवीं तक ही शिक्षित है। अब ईओडब्ल्यू उसके मित्रों और अन्य संपर्कों की भी पड़ताल में जुट गई है।

ई-टेंडर घोटाले में 28 मई को गुजरात की एक कंपनी सोरठिया वेलजी एंड रत्न के एजेंट के रूप में काम करने वाले मनीष खरे को गिरफ्तार किया था। करीब एक साह तक मनीष ईओडब्ल्यू को आइआइटी कानपुर से उत्तीर्ण बताता रहा, लेकिन अब उसकी हकीकत खुली है कि उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है। वहीं से उसने कक्षा नौवीं तक की शिक्षा ली और इसके बाद पढ़ाई नहीं की। मनीष खरे के पिता रेलवे में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी रहे जिनके कारण उसकी रेलवे में पैठ बनी और वहां पेटी कांट्रेक्टर के तौर पर काम करने लगा।

कंपनियों से संपर्क कर दिलाता था टेंडर : सूत्रों के अनुसार खरे से पूछताछ में सामने आया है कि उसे ऑस्मो आइटी सॉल्यूशंस के माध्यम से टेंडर खुलने के पहले जानकारी मिल जाती थी। इसके बाद खरे टेंडर में भाग लेने वाली उन कंपनियों से बात करता था जिनके टेंडर की कीमत पहले नंबर के टेंडर से ज्यादा होती थीं। जो कंपनी उसमें रुचि दिखाती थी, उसके लिए खरे, ऑस्मो आईटी सॉल्यूशन्स से मिलकर टेंडर की कीमत बदल देता था।

- **उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है आरोपित**
- **आरोपित के एक बिल्डर साथी ने जांच एजेंसी पर बनाया था दवाव**

साथियों पर रखी जा रही नजर

ईओडब्ल्यू द्वारा अब उसके मित्रों और संपर्कों के बारे में पड़ताल की जा रही है। खरे के एक बिल्डर मित्र ने दोस्ती निभाने के लिए सरकार के नौकरशाह संपर्कों के माध्यम से जांच एजेंसी पर दबाव बनाने का प्रयास भी किया था। अब इस बिल्डर मित्र की इस घोटाले में भूमिका को लेकर ईओडब्ल्यू द्वारा जांच की जा रही है।

यमुनोत्री धाम में कपड़े से ढका दान पात्र जांच के आदेश

जागरण संवाददाता उत्तरकाशी : यमुनोत्री धाम में दान पात्र को कपड़े से ढकने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक खुले पात्र में दान लिया जा रहा है। तीर्थ यात्रियों की शिकायत पर यमुनोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष और बड़कोट के एसडीएम अनुराग आर्य ने तहसीलदार बुद्धिराम सरियाल को जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने पुलिस को भी कार्रवाई के लिए कहा है। दूसरी ओर यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष जगमोहन उनियाल ने कहा कि दानपात्र पर कपड़ा डालने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ है तो एसडीएम को देखना चाहिए। एसडीएम मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। यमुनोत्री धाम में दान पात्र को लेकर विवाद पहली बार नहीं है। पहले ही इसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल, यह दानपात्र मंदिर के मुख्य द्वार पर रखा गया है। एसडीएम आर्य ने बताया कि तीर्थ यात्रियों ने उनसे शिकायत की है कि पात्र को कपड़े से ढक दिया गया है और इस पात्र के ऊपर एक खुला पात्र रख यात्रियों से दान राशि डलवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह भी आरोप है कि कुछ लोग दानपात्र में तार डालकर धनराशि निकाल रहे हैं।

नंदा देवी में लापता पर्वतारोहियों की खोज में तीन हेलीकॉप्टरों ने की रेकी

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़

नंदा देवी ईस्ट आरोहण के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के पर्वतारोहियों की तलाश जारी है। सर्च आपरेशन के दौरान नंदा देवी चोटी पर नजर आए पांच लोगों के शवों को निकालने के लिए शुक्रवार सुबह वायुसेना के तीन हेलीकाप्टरों ने नंदा देवी क्षेत्र की रेकी की। इस डेयर डेविल आपरेशन में बागेश्वर के पिंडारी से पैदल शुरू होने वाले खोज को लेकर आइटीबीपी मंत्रणा कर रही है। इधर, नंदा देवी चोटी सहित उच्च हिमालय में शुक्रवार शाम को हिमपात होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

नंदा देवी ईस्ट अभियान के दौरान 26 मई को ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के सात पर्वतारोही और भारतीय लाइजन अफसर हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। जिनमें ब्रिटेन के टीम लीडर मार्टिन मोरिन, जॉन चार्लिस मैकेन्स, रिचर्ड प्याने, रूपर्ड वेबैल, अमेरिका निवासी एंथोनी सुडेकम, रोनाल्ड वीमेल, ऑस्ट्रेलिया निवासी महिला पर्वतारोही रूथ मैकेन्स और भारतीय लाइजन अफसर चेतन पांडेय लापता हो गए थे।

वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खोज एवं बचाव अभियान के तहत पांच शव नंदा देवी क्षेत्र में नजर आ चुके हैं। इन शवों को निकालने के लिए डेयर डेविल ऑपरेशन के तहत आइटीबीपी के 12 पर्वतारोही समेत एसडीआरएफ के 12 और एनडीआरएफ की तीस सदस्यीय टीम यहां पहुंची है। इसके अलावा चार सदस्य भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के आए हैं। नंदा देवी में हेलीकॉप्टर से अभियान के संचालन की दिक्कतों को देखते हुए बागेश्वर के पिंडारी से पैदल अभियान की रणनीति बनाई गई है। जिला प्रशासन और आइटीबीपी ने इस अभियान में समय लगने की संभावना जताई है। इस क्रम में गुरुवार को वायु सेना के दो चीता हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ पहुंचे थे। शुक्रवार तड़के वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टरों ने नंदा देवी क्षेत्र की रेकी कर वहां के मौसम तथा अभियान के लिए संभावनाओं को टटोला है।

खोज एवं बचाव कार्य के संचालन के लिए आइटीबीपी के डीआइजी एपीएस निंबाडिया के नेतृत्व में मंत्रणा चल रही है। पैदल खोज एवं बचाव अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रेस्क्यू अभियान के लिए एनडीआरएफ की आठवीं बटालियन गाजियाबाद के तीस जवान व अधिकारी पहुंचे हैं। नेतृत्व कर रहे पंकज कुमार ने बताया कि उनका दल उत्तराखंड में रेस्क्यू चला चुका है।

पंजाब में बोरवेल में फंसे दो वर्षीय मासूम के लिए बचाव कार्य जारी, जुटी सेना

जेएनएन, संगरूर

पंजाब के संगरूर के भगवानपुरा गांव में गुरुवार शाम 4.30 बजे घर के बाहर खेत में खेलते समय नौ इंच चौड़े व 140 फीट गहरे बोरवेल में गिरे दो वर्षीय बच्चे की जिंदगी व मौत से जंग शुक्रवार शाम को भी जारी रही। फतेहवीर को बचाने के लिए गुरुवार शाम 7 बजे से एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया था।

शुक्रवार सुबह सात बजे पटियाला से सेना की असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजीमेंट की टीम भी पहुंची और राहत कार्य की कमान संभाल ली। इसके बाद बोरवेल के साथ-साथ चार फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर सीमेंट के पाइप लगाकर टनल बनाने का कार्य आरंभ किया। फतेहवीर को बोर में गिरे लगभग 27 घंटे हो चुके हैं।

रात 1 बजे व फिर सुबह 4 बजे बच्चे ने की हरकत : फतेहवीर को सुरक्षित रखने के लिए बोर में ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए सिलेंडर लगाए गए हैं। साथ ही कैमरों की मदद से उसकी हरकत पर भी नजर रखी जा रही है। वीरवार देर रात एक बजे फतेहवीर ने हरकत की थी। इसके बाद सुबह चार बजे भी हरकत हुई। इसके बाद दिनभर कोई हरकत नहीं हुई।

करीब 120 तक खोदनी है टनल, 50 फीट तक पहुंचा कार्य : एनडीआरएफ की टीम के प्रयास सफल न होने पर असॉल्ट इंजीनियरिंग रेजीमेंट पटियाला की टीम को सुबह बुलाया गया। रेजीमेंट ने सुबह लगभग 10 बजे बोरवेल के साथ ही टनल बनाने का काम आरंभ किया। शाम 6 बजे तक 50 फीट तक ही खोदाई हो पाई। आठ घंटे की जद्दोजहद के बाद भी खोदाई का लगभग आधा काम ही हो पाया है। इस टनल के माध्यम से जवानों को नीचे उतारकर बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर निकालने की योजना है।

सुनाम (संगरूर) के नजदीकी गांव भगवानपुरा में बोरवेल के पास ही बनाया जा रहा गड्ढा। शुक्रवार रात तक बच्चे को बोरवेल से निकालने का काम जारी था। जागरण

हिमाचल की पांगी घाटी में दिखा भूरा भालू व हिम तेंदुआ

जागरण संवाददाता, चंबा

हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में दुर्लभ हिम तेंदुआ की मौजूदगी दर्ज की गई है। घाटी की तुआन बीट में लगाए गए वन्य प्राणी विंग के कैमरों में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। साथ ही इसी श्रेणी में शामिल भूरा भालू भी कैमरे में कैद हुआ है। चंबा जिले में यह दूसरा मौका है, जब हिम तेंदुआ देखा गया है। इससे पहले भरमौर के कुगती वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एरिया में वर्ष 2006 में मौजूदगी पाई गई थी।

पांगी में सेचु नाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत आने वाली तुआन बीट के वनरक्षक राजेंद्र ने ट्रैकर कैमरे लगा रखे हैं। इसमें हिम तेंदुए तथा भूरे भालू की फोटो कैद हुई हैं। वन्य प्राणी विंग के वनमंडल अधिकारी निशांत मंढोत्रा ने हिम तेंदुए तथा भूरे भालू की मौजूदगी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भूरे भालू पर शोध करने वाले देश के वैज्ञानिक डॉ. विपन राठौर पूर्व में ही पांगी घाटी में हिम तेंदुए की मौजूदगी को लेकर आश्वस्त थे।

मौजूदा समय में डॉ. राठौर पांगी घाटी में भूरे भालू और हिम तेंदुए को लेकर शोध कार्य में जुटे हैं। अब हिम तेंदुए की पांगी में मौजूदगी के बाद डॉ. राठौर अपने शोध कार्य को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। पांगी घाटी के सेंचू नाला, सुराल, चैहणी पास, चस्क भटोरी व गुलधार नामक स्थानों पर किए गए शोध में भूरे भालुओं व हिम तेंदुए को देखा गया है, लिहाजा अब यहां पर शोध कार्य जारी है।

कुछ ही देशों में पाए जाते हैं : हिम तेंदुए और भूरे भालू विश्व के कुछ देशों में ही पाए जाते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व भर में हिम तेंदुआ प्रजाति की संख्या 5000 से भी कम है। भारत में इनकी संख्या करीब 200 है।

भूरा भालू हिमाचल समेत 23 संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद : भूरा भालू भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में शामिल है। भूरे भालू की आबादी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 23 संरक्षित क्षेत्रों में है। वनमंडल अधिकारी वन्य प्राणी विंग निशांत मढ़ोत्रा कहते हैं कि काला भालू समुद्र तल से दो हजार मीटर की ऊंचाई से नीचे रहना पसंद करता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ झुंड में रहना इसकी आदत में शुमार है, जबकि भूरा भालू आमतौर पर समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई से नीचे कभी नहीं आता है। यह झुंड के बजाय अकेला ही रहता है। मात्र प्रसव के दौरान ही यह झुंड में रहता है।

वन्य प्राणी विभाग के कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीरें

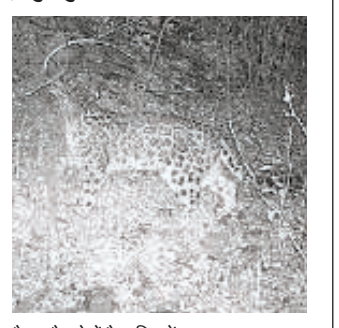

ट्रैकर कैमरे में कैद हिम तेंदुआ। जागरण

कैमरे में कैद भूरा भालू। जागरण

दस फीसद ही मांसाहारी

भूरे भालुओं में मात्र दस फीसद ही मांसाहारी होते हैं, जबकि 90 फीसद भोजन के रूप में जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। भूरे भालू के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से दिए गए एक प्रोजेक्ट पर भी डॉ. राठौर कार्य कर चुके हैं। भूरा भालू अमेरिकी भालू की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसका भार एक से डेढ़ क्विंटल तक होता है और जब यह इंसानों की तरह खड़ा होता है तो इसकी लंबाई करीब छह फीट होती है।

अभ्यर्थियों की मांग

महाराष्ट्र का मामला, अभ्यर्थी कर रहे काउंसलिंग के दौरान पूर्व में दिए विकल्पों में बदलाव पर लगी रोक हटाने की मांग

मेडिकल पीजी कोर्स मामला फिर पहुंचा कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) कोर्स में प्रवेश का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कुछ अभ्यर्थी नए सिरे से होने वाली काउंसलिंग में पूर्व में दी गई प्राथमिकता में बदलाव पर रोक के खिलाफ कोर्ट आए हैं। अभ्यर्थियों ने कोर्ट से आदेश में संशोधन कर रोक हटाने की मांग की है। कोर्ट मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

शुक्रवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अर्जी का जिक्र करते हुए छात्रों के वकीलों ने मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 17 जून तक काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसलिए उनकी अर्जी पर जल्द सुनवाई की जाए। पीठ ने अनुरोध स्वीकार करते हुए सोमवार को सुनवाई की मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने चार जून को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि वह 10 फीसद गरीबों का कोटा हटने के बाद तैयार की गई नई मेरिट लिस्ट के मुताबिक फिर से अंतिम दौर की काउंसलिंग करे। कोर्ट ने राज्य सरकार को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया 17 जून तक पूरी करने का आदेश दिया था। साथ ही कहा था कि काउंसलिंग के दौरान छात्रों को पूर्व में चुने गए विकल्पों में बदलाव की इजाजत नहीं होगी। कुछ छात्रों ने इसी पर एतराज जताते हुए आदेश में बदलाव कर विकल्प बदलने की इजाजत देने की मांग की है।

चार जून को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से पूरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा था ताकि छात्रों में प्रवेश को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता और भ्रम न रहे।

वास्तव में मूल रूप से यह मामला गरीबों के लिए 10 फीसद आरक्षण से जुड़ा था। पिछले सप्ताह प्रधान न्यायाधीश की अवकाशकालीन पीठ ने गरीबों के लिए 10 फीसद आरक्षण लागू करने की महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सीटें बढ़ाए बगैर इस वर्ष पीजी कोर्स में प्रवेश में आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरक्षण लागू होने से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कोर्ट ने सरकार से 10 फीसद आरक्षण हटाकर नई मेरिट लिस्ट बनाने को कहा था। सरकार ने नई मेरिट लिस्ट बनाई थी, लेकिन इसके बाद नए सिरे से काउंसलिंग नहीं कराई थी। इस पर कोर्ट ने चार जून को नए सिरे से अंतिम दौर की काउंसलिंग कराने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्र पूर्व में दिए गए विकल्प नहीं बदल सकते।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

- **जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध**
- **कोर्ट के आदेश के मुताबिक 17 जून तक काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया होनी है पूरी**

नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म का प्रयास, चिल्लाने पर पीटा और मुंह में ठूंसे पत्थर

नईदुनिया, धार (मप्र) : मध्य प्रदेश के धार जिले की धरमपुरी तहसील के एक गांव में सातवीं में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बालिका से उसके चाचा ने दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपित अपने मामा के यहां रह रही भतीजी को घर ले जाने का बोलकर मोपेड पर बैठाकर ले गया था। रास्ते में सुनसान स्थान पर नाबालिग से ज्यादती करने की कोशिश की तो बालिका चिल्लाने लगी। इस पर चाचा ने मारपीट की और मुंह बंद करने के लिए पत्थर ठूंस दिए। इसके बावजूद बालिका ने हिम्मत नहीं हारी। चीख सुन आसपास से लोग आए तो काका भाग निकला। घटना मंगलवार शाम ओंकारेश्वर परियोजना की नहर वाले रास्ते की है। यहां बालिका बेहोशी की हालत में मिली थी। खेतों में पानी दे रहे किसानों ने 108 एंबुलेंस की मदद से उसे शासकीय अस्पताल धामनोद पहुंचाया गया। इसके बाद परिजन बालिका की गंभीर हालत को देखते हुए इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल ले गए। गुरुवार रात बालिका होश में आई। बालिका की शिकायत पर पुलिस ने चाचा पर प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपित फरार है।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 8 जून 2019

दैनिक जागरण

समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है

संघीय ढांचे का निरादर

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की आगामी बैठक में शामिल होने से इन्कार करके यही साबित किया कि वह अभी भी चुनाव के दौर वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकी हैं। शायद उन्हें इसकी परवाह नहीं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके वह पश्चिम बंगाल के हितों की ही अनदेखी करेंगी। यह वही ममता बनर्जी हैं जो एक समय अपने नेतृत्व वाले राजनीतिक मोर्चे का नाम संघीय मोर्चा रख रही थीं ताकि राज्यों के अधिकारों को प्राथमिकता देती हुई दिख सकें, लेकिन आज वह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ खड़ी होना पसंद कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें जनादेश को स्वीकार करने में मुश्किल हो रही है। वह उन चंद मुख्यमंत्रियों में शामिल थीं जिन्होंने मोदी सरकार के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने से इन्कार किया। यह भी ध्यान रहे कि वह चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी को न केवल प्रधानमंत्री मानने से इन्कार कर रही थीं, बल्कि उनसे फोन पर बात करना भी जरूरी नहीं समझ रही थीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह कई केंद्रीय योजनाओं को लागू करने से भी इन्कार करती रही हैं। इनमें आयुष्मान भारत योजना भी है और देश के पिछड़े जिलों के विकास की भी योजना।

राजनीतिक खुन्नस में जनकल्याण और विकास की केंद्रीय योजनाओं से अपने राज्य को वंचित रखना सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। यह एक तरह की जनविरोधी राजनीति भी है। मुश्किल यह है कि ऐसी सस्ती और जनविरोधी राजनीति का परिचय अन्य अनेक दल भी देते रहते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि बीते दिनों द्रमुक नेताओं ने हिंदी थोपे जाने का हल्ला मचाकर किस तरह सस्ती राजनीति का प्रदर्शन किया। हिंदी के नाम पर द्रमुक और कुछ अन्य दलों के नेता किस तरह जनता को गुमराह कर रहे थे, इसका पता इससे चलता है कि तमिलनाडु उन राज्यों में प्रमुख है जहां हिंदी को पठन-पाठन का हिस्सा बनाया गया है। बहुत दिन नहीं हुए जब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआइ को राज्य के मामलों की जांच करने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया था। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना था। आखिर ऐसे मनमाने फैसले लेने वाले नेता किस अधिकार से संघीय ढांचे को मजबूती देने की जरूरत जता सकते हैं? पता नहीं ममता बनर्जी चंद्रबाबू नायडू के राजनीतिक पराभव से कोई सीख लेंगी या नहीं, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि वह संकीर्ण राजनीतिक हितों को इतनी अहमियत दे कि राज्य के हित पीछे छूटते हुए दिखें। लोकसभा चुनावों के समय राहुल गांधी की तरह नीति आयोग को खत्म करने का वादा कर रहीं ममता बनर्जी को इस आयोग की रीति-नीति से शिकायत हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह उसकी बैठकों में शामिल होने से इन्कार करें। नीति आयोग को निष्प्रभावी संस्था बताते हुए उन्होंने योजना आयोग को बहाल करने की मांग की है। यह तय है कि ऐसी मांग करते समय वह इससे भली तरह परिचित होंगी कि ऐसा नहीं होने जा रहा है।

अपराध पर अंकुश जरूरी

बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध पर यदि अंकुश नहीं लग पा रहा तो निश्चय ही यह बेहद चिंताजनक है। आए दिन होने वाली बड़ी-छोटी आपराधिक घटनाएं बताती हैं कि भले ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मोर्चे पर लंबे-चौड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन अपराधियों के हौसले पस्त नहीं हो रहे। राजधानी सहित विभिन्न जिलों में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, डकैती, अपहरण सहित अन्य तरह की गंभीर आपराधिक घटनाओं पर तत्काल अंकुश जरूरी है। इसके लिए पुलिस तंत्र की गहन समीक्षा के साथ ही अपराधियों से साठगांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों को चिन्हित करना होगा। वैसे पुलिस मुख्यालय इस दिशा में काम कर रहा है। हाल के दिनों में कई दागी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अपराध नियंत्रण को लेकर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अक्सर दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं। फिर भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा। ऐसे में पुलिस मुख्यालय को और भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। देखा जाए तो बड़ी आपराधिक घटनाओं में अपवाद छोड़कर अधिकांश में जांच के नाम पर पुलिस सिर्फ खानापूरी करती नजर आती है। यही कारण है कि पुलिस के प्रति आम लोगों में निराशा का भाव ज्यादा है। कहीं-कहीं तो यह आक्रोश में भी तब्दील होते देखा जा सकता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के रास्ते में यह एक बड़ी बाधा है। इस स्थिति में परिवर्तन लाए बिना कानून का राज स्थापित नहीं किया जा सकेगा। पुलिस की कार्यशैली में अपेक्षित बदलाव और क्षमता में वृद्धि भी कम आवश्यक नहीं है। आज के दौर में जब अपराधी नए-नए तरीके और तकनीक अपना रहे हैं तो पुलिस को भी उनसे पार पाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन से लैस करना होगा। अभी पुलिस के पास आधुनिक संसाधनों एवं तकनीक का अभाव और बेहतर प्रशिक्षण की कमी एक बड़ी समस्या है। पुलिस की चुनौती लगातार बढ़ रही है, जबकि वह इस हिसाब से तैयार नहीं दिखती। अपराध नियंत्रण के लिए इस स्थिति में बदलाव किया जाना समय की मांग है।

समाधान के इंतजार में सांप्रदायिक समस्या

कैप्टन आर विक्रम सिंह

भारत के विचार के साथ अल्पसंख्यक वर्ग का सामंजस्य बैठाना आसान न था, लेकिन हिंदुओं की भीड़ में पहचान गुम न हो जाए इसलिए मजहब को और मजबूती से पकड़ लिया गया

लोकसभा चुनाव परिणाम हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए आत्मचिंतन का एक अवसर हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर इस जनादेश में अल्पसंख्यक समाज की क्या भूमिका रही? हमें इस प्रश्न पर अपने यहां की सांप्रदायिक पृष्ठभूमि को देखते हुए विचार करना होगा। इस क्रम में यह भी देखना होगा कि विश्व में वे कौन से देश हैं जिन्होंने अपनी सांप्रदायिक समस्या का समाधान कर लिया है? जब अरब सेनाओं ने संपूर्ण अरब क्षेत्र पर विजय के बाद ईरान का रुख किया तो वहां का प्राचीन धर्म ही समाप्त हो गया। इसी के साथ वहां कोई सांप्रदायिक समस्या बची ही नहीं। पाकिस्तान में आजादी के समय 22 प्रतिशत हिंदू थे। आज 1.5 प्रतिशत ही बचे हैं। बांग्लादेश में 1947 में 28 प्रतिशत हिंदू थे। आज 8 प्रतिशत रह गए हैं। इंडोनेशिया में 87 प्रतिशत, मलेशिया में 62 प्रतिशत मुस्लिम हैं। शेष समाज बौद्ध, हिंदू, ईसाई आदि इतनी अल्पसंख्या में है कि इन देशों में भी कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं है। स्पष्ट है कि आज जिन देशों में यह समस्या नहीं है तो वहां इसका मुख्य कारण जनसांख्यिकी के अनुपात का पूरी तरह से एक धर्म के पक्ष में होना है। जहां समस्या है, उनमें प्रमुख है चीन के उइगर मुस्लिमों वाला इलाका और म्यांमार का रोहिंग्या क्षेत्र। चीन ने समाधान के लिए प्रशिक्षण कैंपों का सहारा लिया है। 1933 में उइगर और चीनी आबादी का अनुपात जो क्रमशः 77 और 5.5 प्रतिशत था, वह 2015 में 45 और 42 प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि चीनी शासक जनसांख्यिकी में परिवर्तन के माध्यम से समस्या का समाधान करते मालूम पड़ रहे हैं। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या 10 लाख थी। 2015 से वहां उत्पीड़न का क्रम प्रारंभ हुआ और 9 लाख रोहिंग्यों ने भागकर बांग्लादेश, फिर चोरी छिपे भारत में भी शरण ली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर म्यांमार की बड़ी आलोचनाएं हो रही हैं, किंतु उन्होंने अपनी समस्या का, जैसा उनकी समझ में आया, समाधान कर लिया।

भारतीय राजनीति की आज की मजहबपरस्ती के बहुत पहले इतिहास के लंबे दौर में अन्य देशों के समान अपनी सांप्रदायिक समस्या के समाधान के अवसर आए थे, लेकिन सक्षम नेतृत्व के अभाव के कारण समाधान के रास्ते नहीं बने। समाधान की जो सूरतें बनीं वे स्थगित होती गईं। मुगल साम्राज्य के पराभव के बाद यदि दिल्ली में मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ होता तो आज भारत में बहुत-सी अन्य समस्याएं तो होतीं, लेकिन कोई हिंदू-मुसलमान समस्या न होती। पानीपत की तीसरी जंग में मराठों की हार और फिर भारत में बढ़ते ब्रिटिश वर्चस्व ने समाधान को स्थगित कर दिया। यदि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की पराजय हो जाती तो फिर आंतरिक सत्ता संघर्ष इस सांप्रदायिक समस्या का भी समाधान कर देता, लेकिन ब्रिटिश विजयी हुए और समाधान की स्थितियां नहीं बनीं। फिर बदलते हुए घटनाक्रम में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, आधुनिकता के रुझान, अंग्रेजों की सांप्रदायिक संतुलन की नीति आदि ने इस सांप्रदायिक विवाद को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जब तक ब्रिटिश खुद इसमें भागीदार नहीं हो गए। अंग्रेजों की सक्रिय भागीदारी 1905 में बंगाल के सांप्रदायिक विभाजन से सामने आती है। यहां से आगे हिंदू-मुस्लिम हित बड़े स्पष्ट रूप से एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखते हैं। वह समस्या जिसे 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद से ही समाधान की दरकार थी, स्थगित होते-होते 1940-47 में भारत विभाजन के मुहाने पर लाकर खड़ी कर दी गई। 'दो राष्ट्रों के सिद्धांत' के तहत एक नकली देश की सरहदें बनाकर सांप्रदायिक समस्या का समाधान पुनः स्थगित कर दिया गया।

अवधेश राजपूत

अविभाजित भारत में मुस्लिम आबादी 33 प्रतिशत थी। आजादी के आंदोलन में आखिरकार यह तय हुआ कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह पाएंगे। पाकिस्तान निर्माण के मूल में भारतीय राष्ट्रीयता का अस्वीकार है। पाकिस्तान बनने के बाद भारत की 15 प्रतिशत मुस्लिम आबादी को सहअस्तित्व का दर्शन विकसित करना चाहिए था, लेकिन देश विभाजन के बाद भारत में पाकिस्तानी सोच का विकास हुआ। जब कहीं धर्मपरिवर्तित समाज को उसके इतिहास, संस्कृति से काट दिया जाता है तो फिर वहां का इतिहास उसका नहीं रहता। इतिहास के नायक आपके शत्रु हो जाते हैं। संस्कृति का अस्वीकार हो जाता है। गैरमुल्की सोच के प्रभाव से अपना ही देश दारुल हरब हो जाता है। भारत के मुख्य भाग से विभाजन के बाद मात्र 16 प्रतिशत लोग ही पाकिस्तान को रुखसत हुए। पाकिस्तान बनवाने के बाद अधिकांश अल्पसंख्यक समाज एक मजहबी खुमार के साथ भारत में रह गया, जबकि इस अल्पसंख्यक समाज को अपने को पाकिस्तानी सोच से पूरी तरह से बाहर लाने का काम करना था। यह काम इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि हमारी राजनीति उसे वोट बैंक के रास्ते पर ले आई, जिसके कारण अलग पहचान बनाए रखना फायदे का सौदा हो गया।

भारत के बड़े नेताओं खासकर गांधी और नेहरू ने आजादी के आंदोलन में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तुर्की के खलीफा को हटाए जाने को अपना मुद्दा बना लिया। भारत के विचार के साथ अल्पसंख्यक वर्ग का सामंजस्य बैठाना आसान काम नहीं था, पर हिंदुओं की भीड़ में पहचान गुम न हो जाए इसलिए मजहब को और मजबूती से पकड़ लिया गया। वंदे मातरम का विरोध करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का असम्मान करना, अपने असल इतिहास एवं संस्कृति को भूले रहना, विभाजन के बाद फिर से अलगाव की भावना को हवा देना यह तो फर्ज नहीं था। राष्ट्रीयता की भावना मजहब विरोधी नहीं है। अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा राष्ट्रवाद को सम्यक महत्व न दे पाना, देश के विभाजन को अर्थहीन कर देता है।

पाकिस्तान से अब तक हुए चार युद्ध इसी विभाजित मानसिकता की उपज हैं। हर युद्ध आमंत्रण था समस्या के समाधान का, लेकिन हमें ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जो कश्मीर जैसी सांप्रदायिक समस्या को अंतिम समाधान तक ले जाता। दोष नेतृत्व का भी नहीं है, क्योंकि जैसा समाज होता है उसे वैसा ही नेतृत्व भी मिलता है। हम उन्हें नेता मानते रहे जिसकी सोच कभी समाधान की रही ही नहीं। समस्या के स्थगन को वे समाधान मानते रहे। ये हम ही हैं जो आजादी की जंग में कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ नहीं खड़े हुए। हमने उन्हें फांसी चढ़ने दिया। जेल तोड़ कर आजाद नहीं कराया। फिर आंसू बहाते रहे। गुलामी की संस्कृति का भार हमारी आत्मा पर बहुत भारी रहा है। इसी गुलाम मानसिकता से पैदा समझौतापरस्ती देश की सांप्रदायिक समस्या की जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने इस मनोवैज्ञानिक-सांप्रदायिक समस्या को जीवित रखा है। राष्ट्रवाद का कोई मध्य मार्ग नहीं होता। यदि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो फिर आप राष्ट्रविरोधी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की निर्णायक विजय के बाद राष्ट्रनिरपेक्षखंडित सोच वाले कैंपों में खलबली है। समाधान का समय कभी भी घोषणा करके नहीं आता। राष्ट्र ने तो अपना निर्णय सुना दिया। अब मुश्किल फैसलों का-समाधान का कालखंड प्रारंभ होने को है।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

वक्त की मांग है पुरुष आयोग का गठन

क्षमा शर्मा

मानव अधिकार स्त्री-पुरुष, दोनों के होते हैं और कानून का काम सभी के मानव अधिकारों की रक्षा करना है

पिछले साल मी टू अभियान का बहुत शोर हुआ था। उस दौरान महिलाओं का एक वर्ग कह रहा था कि अच्छा है कि औरतें अपने प्रति हुए यौन अपराधों की बातें कह रही हैं। बात सच भी थी, क्योंकि औरतों को अपने प्रति हुए इस तरह के अपराधों को छिपाने की सलाह कोई और नहीं उनके परिवार वाले ही देते थे, लेकिन यह भी सच है कि धीरे-धीरे झूठे मामले सामने आने लगे। मी टू आंदोलन अमेरिका से शुरू होकर यहां पहुंचा। अमेरिका में एक अटार्नी जनरल पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया गया। बाद में आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि वह तो उन्हें जानती ही नहीं। कभी मिली भी नहीं। अपने यहां भी एक ब्यूटी पेजेंट में भाग लेने वाली एक लेखिका ने एक बड़े लेखक पर ऐसे आरोप लगाए, लेकिन जब उस लेखक ने उस महिला की मेल सार्वजनिक कर दी तो वह मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। यह भी लगा कि इस तरह की बातें बढ़-चढ़कर इसलिए भी की गईं ताकि रातों रात प्रसिद्धि मिल सके। इस मी टू विमर्श पर कई तरह के विचार सामने आए। वे महिलाएं इस विमर्श से बाहर थीं जो दो जून की रोटी और अपने बाल-बच्चों के लिए हाड़-तोड़ मेहनत करती हैं और इसी दौरान तमाम तरह के अत्याचार और शोषण से गुजरती हैं। ऐसी महिलाएं चर्चा का विषय तब बनती हैं जब कोई एनजीओ या बड़ा संस्थान अथवा मीडिया उन्हें अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाता है। मी टू के दिनों में ही वी टू, ही टू, मैन टू की आवाजें सुनी गईं, लेकिन वे बहुत धीमी थीं।

महिलाओं को अधिकार मिलें और कानून उनकी सहायता करे, लेकिन कानून के नाम पर निरपराधों को फंसाना, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ है। मानव अधिकार न केवल स्त्रियों के होते हैं, न केवल पुरुषों के। वे सबके लिए होते हैं और कानून का काम सभी के मानव अधिकारों की रक्षा करना है। अफसोस कि स्त्रियों के लिए जो कानून बने हैं वे इतने एकपक्षीय हैं कि वे औरतों को देवी और सदा सच बोलने वाली और पुरुषों को खलनायक के तौर पर पेश करते हैं। ये एकपक्षीय कानून पुरुषों के घर की औरतों को भी पितृसत्ता का प्रतीक मानकर सताने का काम करते हैं। इसीलिए जेंडर न्यूट्रल कानूनों की मांग उठने लगी है। जो भी अपराधी हो-स्त्री या पुरुष उसे सजा मिले। कानून का काम अपराधी को सजा देना ही होना चाहिए। उसकी लाठी से निरपराध को क्यों सताया जाए?

हाल में मीडिया के एक हिस्से में मैन टू अभियान चला। मैन टू अभियान चलाने में अग्रणी भूमिका अभिनेत्री पूजा बेदी ने निभाई। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पुरुषों के अधिकारों की बातें भी होनी चाहिए। आखिर यह वह जमाना नहीं जिसे पितृसत्ता के वर्चस्व का पर्याय माना जाता हो। अब महिलाओं को भी पूरे अधिकार हैं। इसके बावजूद महिलाएं जब चाहें तब खुद को शक्तिशाली कहती हैं और जब चाहे तब बेचारी दिखाने लगती हैं। उदाहरण के तौर पर लिव इन में रहने वाली महिलाएं, जो रिश्ता टूटने पर दुष्कर्म का आरोप लगा देती हैं। जबकि अदालतें सहमति से संबंध को दुष्कर्म नहीं मानतीं। पूजा बेदी ने मी टू के दिनों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन दिनों पीआर एजेंसीज सक्रिय हो गई थीं। वे फिल्म जगत में जगह बनाने को आतुर लड़कियों को सलाह दे रही थीं कि वे नामी-गिरामी लोगों पर ऐसे आरोप लगा दें। इससे उनकी चर्चा होगी और काम मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े देकर यह भी बताया कि अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 तक दुष्कर्म के जितने मामले दर्ज कराए गए उनमें से 53.2 प्रतिशत झूठे पाए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों में भी बताया गया है कि दहेज से संबंधित दस प्रतिशत केस झूठे होते हैं। उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा कि जो कानून महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों से रक्षा के लिए बनाया गया था उसे ससुराल वालों और पति से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पूजा बेदी ने मांग की कि वक्त आ गया है कि महिला कमीशन की तर्ज पर पुरुष कमीशन भी बनाया जाए ताकि निरपराध पुरुष भी अपनी बात कह सकें, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं सुनता-न मीडिया, न सरकार और न ही समाज। वे बरी होने के बाद भी अपमान झेलने को मजबूर होते हैं। उनका परिवार तहस-नहस हो जाता है।

अपने देश में हर वर्ष औसतन 94 हजार पुरुष आत्महत्या करते हैं। यह संख्या औरतों के मुकाबले छह प्रतिशत अधिक है। आत्महत्या का बड़ा कारण पारिवारिक और वैवाहिक विवाद होता है। इस पर महिला अधिकारों की एक प्रवक्ता ने बड़ी मासूमियत से कहा था कि पुरुष ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं। क्या इसकी जांच-पड़ताल की जरूरत नहीं कि आखिर कोई अवसाद का शिकार क्यों होता है?

(लेखिका साहित्यकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सच्चा जीवन

जो व्यक्ति ईश्वर को कभी नहीं भूलता और सदैव अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाता है और बदले में जो मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाता है, वही सच्चा और सुखी है। बुद्ध ने कहा कि कामी व्यक्ति अनेक बार मरता है। जितनी कामना, उतनी बार मृत्यु। संतोष जीवन है और असंतोष मृत्यु। संतोष का मतलब है कि अपने कर्म को पूरे उत्साह से करना और उससे जो भी फल मिले उससे संतुष्ट हो जाना है।

मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन उसके विचार ही हैं। मनुष्य को यह जानना-समझना होता है कि कौन-सा विचार उसका मित्र है और कौन-सा शत्रु। सकारात्मक विचार अपने साथ कई दोस्तों को लाता है और नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति दुश्मनों से घिर जाता है। असल में सभी लोग जीवन को अपने-अपने नजरिए से देखते हैं, कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, कोई कहता है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, कोई कहता है कि जीवन एक यात्रा है, कोई कहता है कि जीवन एक दौड़ है। हम जिस नजरिए से जीवन को देखेंगे, हमारा जीवन वैसा ही बन जाएगा, लेकिन सच्चा जीवन वही जी सकता है, जो अपने जन्म और मृत्यु के बीच के समय को भरपूर हास्य और प्रेम से भर दे।

अक्सर मनुष्य अपने भविष्य एवं अतीत के बारे में सोचता रहता है और इस चक्कर में वह वर्तमान की कोई परवाह नहीं करता, जबकि जीवन वर्तमान में ही है। कल कभी नहीं आता, जो है वह आज और अभी है। जो समय बीत गया, उसे याद करके मनुष्य को पछताना नहीं चाहिए। अगर अतीत में मनुष्य से कोई गलती हुई भी है तो उसे उससे सबक लेकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को भविष्य में आने वाले संकटों को देख घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य का वर्तमान आनंदित है, उसका भविष्य भी सुंदर होगा। वर्तमान को आनंदित बनाने के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। जैसे वह यह कार्य क्यों करना चाहता है, क्या वह इसको अकेले कर पाएगा या उसे और लोगों की जरूरत पड़ेगी और इस काम के नतीजे क्या होंगे। बिना सोचे-विचारे किए गए काम का नतीजा अक्सर दुख देता है।

आचार्य अनिल वत्स

तथ्य-कथ्य | खास लोकसभा सीटों पर नोटा को मिले वोट (कोष्ठक में कुल नोटा वोटों का प्रतिशत)

हमारे समय में 'अंधेर नगरी'

मैंने अपने एक शिक्षक से सवाल किया कि 'अंधेर नगरी' आज के समय में हम क्यों पढ़ें? सर ने सवाल दागा कि मैं पूछता हूं कि क्यों न पढ़ें? बात तो सही है कि क्यों न पढ़ें। अंधेर नगरी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी नगरी है जिसमें अंधेर है। अंधेर का अर्थ अगर आप केवल उजाले की अनुपस्थिति से लगाएंगे तो ठीक-ठीक नहीं समझ पाएंगे। यहां अंधेर का मतलब गड़बड़ी, निराशा और ऐसी स्थिति का होना है जिसमें वह सब होता है जिसे नहीं होना चाहिए। यानी अव्यवस्था ही व्यवस्था के रूप में स्वीकृत है। आजकल जिसे हम न्यू नॉर्मल कहते हैं, वह दरअसल एबनॉर्मल है, लेकिन उसे कोई मानने को तैयार नहीं। यह 'अंधेर नगरी' एक रूपक में बदल जाता है और इसका विस्तार नगर तक सीमित न रहकर समस्त देश हो जाता है। और आज के दौर में जब अंधेर नगरी के रूपक के नजरिए से अपने देश को देखते हैं तो इस रूपक का नवीन अर्थ हमारे सामने खुलता जाता है और इसकी सीमाओं का भी पता चलता है।

फिर से

'अंधेर नगरी' में अंधेर का मतलब गड़बड़ी, निराशा और ऐसी स्थिति का होना है जिसमें वह सब होता है जिसे नहीं होना चाहिए

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 'अंधेर नगरी चौपट राजा' नाटक अंग्रेजी शासन के दौर में लिखा था। यह वह दौर था जब हिंदी में नाट्य लेखन शैशवास्था में था, भारतेंदु नाटक के इर्द-गिर्द हिंदी समाज में राजनीतिक और समाज सुधार की चेतना के प्रसार को केंद्रित रखे हुए थे। वे नाटक लिखते थे, अभिनय करते थे, रंग मंडलियां तैयार करते थे... विविध स्तरों पर सक्रिय थे। 'अंधेर नगरी' के लिखे जाने तक वे 'भारत दुर्दशा' लिख चुके थे जिसमें वे आधुनिक भारत की चिंताजनक स्थिति को व्यंग्य और यथार्थ के जरिये दिखा चुके थे, लेकिन 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट भी लागू हो चुका था। नाटक और नाट्य प्रदर्शनों पर अंग्रेजी शासन की नजर थी। नाटकों पर प्रतिबंध लगना शुरू था। नाटककार सीधे-सीधे अंग्रेजी शासन की आलोचना करने के बजाय रूपक के जरिये अंग्रेजी शासन के सच को बयां करने की युक्तियां खोज रहे थे। 'अंधेर नगरी' को भी ऐसी ही युक्ति में गिना जा सकता है। इस युक्ति के जरिये भारतेंदु ने लोक प्रचलित प्रहसन को अपनी प्रतिभा से समसामयिकता में ढाल कर ऐसे नाटक में तब्दील किया जो अपने दौर में तो लोकप्रिय हुई ही, प्रकाशन और पहले मंचन के बाद से ही प्रासंगिक बनी रही। दुख की बात है कि आज एक भी सामयिक साहित्यिक प्रयास हमारे सामने नहीं है जिसमें आज के सच का निरूपण हो और वह जनता तक संप्रेषणीय हो? अगर नहीं है तो हमें 'अंधेर नगरी' की शरण में जाना ही होगा उसे पढ़ना होगा, मंचित करना होगा, क्योंकि वह बाजार और राज्य दोनों की हकीकत बयान करता है। आज यही दोनों नियामक शक्तियां हमारे जीवन पर हावी होने की लगातार कोशिश कर रही हैं।

'अंधेर नगरी' को ऐसे दौर में पढ़िए जहां बाजार में हर चीज बिकाऊ है, वस्तु का मोल उसकी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है और इस अंधेर नगरी में बुनियादी सवालों को कोई सुनने वाला नहीं है कि गरीब की बची खुची संपत्ति को कौन लूट रहा है? कहां तो राजा का दावा है कि उसके यहां ऐसा न्याय होगा जैसा यम के यहां भी नहीं, लेकिन इस न्याय व्यवस्था में नागरिकों का हाल क्या हो गया है?

(साभार : रंग विमर्श ब्लॉग में अमितेश)

मेलबाक्स

चुनाव नतीजों ने दिया नया संदेश

लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपने आलेख 'राजनीतिक सबक सिखाने वाले नतीजे' में जातिवादी राजनीति के गणित को तोड़ने वाली सामाजिक केमिस्ट्री की जो बात की है, वह देश को नया राजनीतिक संदेश दे रही है। देश के विभिन्न प्रदेशों में जातिवाद और संप्रदायवाद से उपजे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने पिछले तीन दशकों से अपने सांप्रदायिक और जातिवादी गणित से केंद्र में बहुमत की सरकार नहीं बनने दी। 2014 में पहली बार देश की जनता ने क्षेत्रीय दलों के इस जातिगत गणित को तोड़कर केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा नीत राजग सरकार स्थापित की। बहुमत युक्त मोदी सरकार की सबका साथ-सबका विकास से समन्वित राष्ट्रहितैषी नीतियों ने देश के आम जनमानस को इतना प्रभावित किया कि 2019 का आम चुनाव ही मोदीमय हो गया। इस आम चुनाव में भाजपा के पक्ष में जाने वाले पचास प्रतिशत वोट ने यह साबित कर दिया कि मोदी सरकार की जनहितैषी नीतियों से देश संतुष्ट है। मोदी के पक्ष में बन रहे सामाजिक रसायन को कांग्रेस सहित सपा, बसपा और राजद जैसे बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल समय रहते भांप नहीं पाए। ये दल इसी मुगालते में रहे कि जनता परिवर्तन चाहती है। अपने चुनावी गणित को जनता के सामने रखते हुए इन विपक्षी दलों से एक और चूक हो गई कि इन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का नीतिगत विरोध न करके मोदी के साफ-सुथरे व्यक्तित्व पर कीचड़ उछाला। यह चूक इनको इतनी भारी पड़ी कि जनता ने विपक्ष की इस बकवास को नकारते हुए मोदी के पक्ष में झूमकर मतदान किया और अकेली भाजपा को बहुमत से बहुत आगे 303 सीटों पर ले जाकर खड़ा कर दिया। देश की जनता द्वारा मोदी के राष्ट्रसेवी व्यक्तित्व के प्रति व्यक्त किया गया यह विश्वास अकल्पनीय था। इस जन-विश्वास से यह संदेश प्रसारित हुआ है कि अब देश को जातिगत विकृत राजनीति नहीं, अपितु भ्रष्टाचार मुक्त विकास चाहिए। ऐसे में अभी भी परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद की विकृत राजनीति में जकड़े विपक्षी दलों को इस नए राजनीतिक संदेश से सबक लेने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

पर्यावरण को भी सुधारें

मोदी सरकार-2 सबका साथ सबका विकास सूत्र को लेकर देश के चहुंमुखी विकास को लक्ष्य बनाकर काम कर रही है। देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनसंख्या वृद्धि ये चार प्रमुख समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। इससे तो निपटना ही है, किंतु उससे भी ज्यादा विकराल समस्या बढ़ते प्रदूषण की है। इस पर भी आज ही ध्यान देने की जरूरत है। अगर आज ध्यान नहीं दिया तो कल वाली पीढ़ी किसी भी अग्रज को माफ नहीं करेगी। जब उसे सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। जैसे आज बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। सड़कों का विकास हो, पर सीमेंट कंक्रीट के जंगल का नहीं। विशाल अट्टालिकाएं बनें पर उसके साथ ही वहां हरियाली की सीमा भी निश्चित की जाए, कारखानों का उत्थान हो किंतु उससे फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था भी हो। करोड़ों की संख्या में पेड़-पौधे रोपे जाएं, वे कागजी न होकर वास्तविक हों साथ ही उनकी सही देखभाल भी हो। बरसात के पानी को रोकने, तालाबों व नहरों के निर्माण आदि के काम भी युद्ध स्तर पर हों तो जल संकट से तो मुक्ति मिल ही सकती है साथ ही खेती और नए लगे पेड़ पौधों को सींचने के लिए पानी की भरपूर व्यवस्था भी हो सकती है। हरा-भरा गांव होगा तो हरा-भरा शहर भी, हरा-भरा प्रदेश होगा तो हरा-भरा देश भी। जो आज तो सुकून देगा किंतु कल भी सुकून भरी जिंदगी से नई पीढ़ी को लबरेज कर देगा।

mahesh_nenava@yahoo.com

हिंदी पर फिर हाय-तौबा

हिंदी के मुद्दे पर दक्षिणी भारत में उठे विरोध के स्वरों को दबाने के लिए केंद्र सरकार को जिस तरह त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश में संशोधन करना पड़ा, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश में शिक्षा की दिशा तय करना भी दबाव की राजनीति से मुक्त नहीं है। अब विद्यार्थी छठी कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक विषय को छोड़ सकते हैं। जाहिर है, गैर हिंदी भाषी प्रदेशों में ज्यादातर बच्चे हिंदी को ही छोड़ेंगे। हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जानेवाली भाषा है। अफसोस की बात है कि सुविचारित त्रिभाषा फार्मूले की सिफारिश पर सिर्फ इसलिए अमल नहीं हो पाएगा कि कुछ प्रदेशों के राजनीतिज्ञ इसके दूरगामी परिणामों को समझने के बजाय इसे अपनी आंखों की किरकिरी मानने की भूल कर बैठे हैं।

युधिष्ठिर लाल कक्कड़, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1,400 नए वाहन रोज आते हैं दिल्ली की सड़कों पर जिससे यहां वाहनों का भार अत्यधिक हो चुका है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को सर्वसुलभ और सस्ता करना ही बेहतर उपाय हो सकता है ताकि लोगों को रोजमर्रा के कामकाज निबटाने में आसानी होने के साथ प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिल सके।

आजकल

प्रो. लल्लन प्रसाद
पूर्व विभागाध्यक्ष, बिजनेस इकोनॉमिक्स विभाग, दिल्ली विवि

समग्र रोजगार के बिना अधूरा है विकास

अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, रोजगाार के साधन उस गति से नहीं बढ़ रहे हैं। बिना रोजगार के विकास की स्थिति का मुख्य कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। प्रतिमाह 10 लाख नए लोगों को रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। बड़े उद्योग, मशीनों और ऑटोमेशन के बल पर पनपते हैं, जहां पूंजी प्रधान हो जाता है और श्रम गौण। यूरोप के अधिकांश देशों में कुल आबादी आज भी वही है जो पांच-छह दशक पहले थी। भारत की आबादी में तब से करीब 100 करोड़ का इजाफा हो चुका है। ऐसे में हमें सभी को रोजगार मुहैया कराने के लिए चीन से सीखने की जरूरत है जिसने वर्तमान आबादी को रोजगार प्रदान करने के साथ बढ़ती जनसंख्या को भी नियंत्रित किया है

पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। वर्ष 2013 में विश्व में यह 11वें स्थान पर थी, जो 2019 आते-आते पांचवें स्थान पर पहुंच गई है। इस दौरान देश भर में सड़कों समेत आधारभूत उद्योगों (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का तेजी से विकास हुआ। बैंकों के अदेय ऋण पर लगाम लगाने में सरकार काफी हद तक कामयाब होती दिखी है। वर्ष 2018 की अंतिम तिमाही में विकास दर 8.3 प्रतिशत थी, यानी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। किंतु विकास दर में अब कुछ कमी आई है। पिछली तिमाही में यह 6.6 प्रतिशत था। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हुई है, पिछले 21 महीनों का सबसे न्यूनतम औद्योगिक विकास दर 0.1 प्रतिशत था जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंताजनक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि का लाभ किसानों को नहीं मिला, क्योंकि कीमतों में गिरावट आ गई। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि किसान को अपनी लागत निकालना मुश्किल हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में वर्षा औसत से कम हुई, कई इलाकों में सूखा पड़ा। अधिकांश राज्यों में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर किसानों से उतनी खरीदारी नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी। कई राज्यों में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान कागजों पर रह गए, बहुत कम संख्या में किसान लाभान्वित हुए। छोटे-बड़े उद्योगों में उत्पादन वृद्धि न होने से नए रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं, जबकि आबादी तेजी से बढ़ रही है।

उपभोक्ता पदार्थों की मांग

उपभोक्ता पदार्थों की मांग में कमी होने से कारखानों में उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसका असर कच्चे माल, मशीनों आदि की मांग पर पड़ रहा है। उद्योगों में निवेश में भी कमी आई है, यद्यपि शेयर बाजार में उछाल ही अधिक था गिरावट कम। करीब 23 विनिर्माण उद्योगों में 12 उद्योग मांग में गिरावट से प्रभावित हुए। मार्च 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 0.4 प्रतिशत नीचे गया। सबसे अधिक प्रभावित उद्योग थे- कार, दोपहिये और तिपहिये वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और महंगे उपभोक्ता पदार्थ। इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता पदार्थों की मांग पर असर नहीं पड़ा, स्टील और सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि हुई। बिजली और ऊर्जा के अन्य साधनों का उत्पादन भी बढ़ा। कुल मिलाकर औद्योगिक विकास दर 3.6 प्रतिशत रहा जो पिछले वर्ष के 4.4 प्रतिशत से कम था। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में शिथिलता के मुख्य कारण थे उपभोक्ता पदार्थों की मांग में कमी और निवेश में गिरावट। देश के 60 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी आमदनी में कमी

देश भर में ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करना होगा ताकि कौशल निर्माण के साथ रोजगार में भी बढ़ोतरी हो सके

का सीधा प्रभाव उपभोक्ता पदार्थों की मांग पर पड़ता है। बढ़ती बेरोजगारी भी मांग की कमी का कारण बनती है। कीमतों को नियंत्रण में रखने में सरकार सफल रही, किंतु कृषि और आम उपभोक्ता पदार्थों की कीमतें कम होने से किसानों और छोटे-बड़े उत्पादकों को नुकसान हुआ। सब्जियों की कम कीमतों का खामियाजा किसानों को अक्सर भुगतना पड़ता है। सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोपों से किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विपत्तियों से जूझने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है जिसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण से लोगों के पास रुपये की जो कमी हुई उसका असर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

खेती-किसानी में सुधार

किसानों को कर्ज से मुक्त करने और उनकी आमदनी बढ़ाने के जो प्रयास पिछले वर्षों में हुए हैं उनमें तेजी लाने की आवश्यकता है। देश के दो राज्यों- तेलंगाना और ओडिशा में इस दिशा में कुछ सफल प्रयोग हुए हैं। तेलंगाना में हर किसान को 4,000 रुपये प्रति एकड़ वर्ष में दो बार दिया जाता है जो सीधे उसके बैंक खाते में जाता है। राज्य सरकार पर इससे 12,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है, किंतु किसानों की माली हालत में इससे सुधार हुआ है। ओडिशा सरकार सतही और छोटे किसानों के बैंक खाते में 5,000 रुपये वर्ष में दो बार डालती है। राज्य सरकार पर इससे वर्ष में 3,400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है। इससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है जिसके अंतर्गत छोटे किसानों, जिनके पास दो एकड़ या इससे कम कृषि योग्य भूमि है उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष बैंक खातों के जरिये दिया जाता है। भुगतान वर्ष में तीन बार 2,000 रुपये के हिसाब से देने का प्रावधान है जो फलसों की बुवाई के पूर्व किसान को मिलता है जिससे वह बीज, खाद आदि का प्रबंध कर सकें। करीब 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। हालांकि यह रकम किसान की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है, पर एक अच्छी शुरुआत है, रकम बढ़ाई जानी चाहिए। केंद्र सरकार पर इससे 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा जिसे बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता।

पहले भी हुए कर्ज माफी के प्रयास

किसानों की कर्ज माफी के प्रयास बीते वर्षों के दौरान भी कुछ सरकारों ने की थी। वर्ष 1990 में वीपी सिंह ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा करते हुए 10,000 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए। वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह ने 52,260 करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का वादा किया। वर्ष 2014-18 के बीच सात राज्यों में 1,82,802 करोड़ रुपये के कर्ज माफी के वादे किए। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। मालूम हो कि कर्ज माफी का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो बैंकों से कर्ज लेते हैं। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सतही और छोटे किसानों में कुल 30 प्रतिशत ही बैंकों से ऋण लेते हैं। ऐसे में जब करीब 70 प्रतिशत किसान बैंकों से लोन लेते ही नहीं हैं, तो कर्ज माफी की सुविधा का उनके लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। अभी भी बड़ी संख्या में किसान साहूकारों और सूदखोरों के चंगुल में है। किसानों के लिए अनुदान को सीधे उनके खातों में जमा करा देना, कर्ज माफी की अपेक्षा कहीं अधिक लाभकर है। इसका लाभ उन सभी किसानों को मिलता है जिनके लिए यह योजना बनाई जाती है।

किसान को मिले सही मूल्य

किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य मिले, इसके लिए नियुक्त आयोग द्वारा निर्धारित कीमत पर राज्य सरकारें किसानों से जो अनाज खरीदती हैं उस योजना में भी सुधार की आवश्यकता है। अधिकांश राज्य उतनी मात्रा में खरीद नहीं करते जितना किसान चाहते हैं। केंद्र सरकार की नई योजना किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना देने का वादा करती है। सरकार अगले तीन वर्षों में किसानों की आदमनी दोगुनी करने को भी कृतसंकल्प है। सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष नवंबर में एक लाख किसान देश के विभिन्न भागों से राजधानी में एकत्रित हुए जिसे किसान मुक्ति मोर्चा की संज्ञा दी गई। किसानों की दो प्रमुख मांगे थीं- कर्ज से मुक्ति हो और उत्पाद की सही कीमत मिले। फरवरी 2019 में करीब पचास हजार किसान नासिक से पैदल चलकर मुंबई पहुंचे और वहां राज्य सरकार के सामने यही प्रतिवेदन किया।

आजादी के सात दशक बाद भी किसानों की माली हालत में सुधार न होना अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। वर्षों से किसानों की आत्महत्या के समाचार आते रहे हैं और सिलसिला अब भी जारी है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। पिछले पांच वर्षों में केंद्र सरकार के बजट में गांवों और किसानों के लिए आवंटित राशि में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, यानी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, किंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विश्व व्यापार संगठन की रोक के बावजूद अमेरिका सहित कई विकसित देशों में भी किसानों को तरह-तरह की सब्सिडी दी जाती है। भारत का किसान तो विकसित देशों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, सरकार की जिम्मेदारी है उसकी माली हालत सुधारने की।

औद्योगिक उत्पादन व खेती को प्राथमिकता

उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछली दो तिमाहियों में रेपो रेट (जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं) में कमी की है, किंतु इसका उतना लाभ हुआ नहीं जितना अपेक्षित था। अधिकांश बैंकों ने कर्ज देने के ब्याज दर में उतनी कमी नहीं की जो कर्ज की मांग बढ़ा सके। बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी के कारण निवेशकों की ओर से भी कर्ज की मांग में अपेक्षित तेजी नहीं आई। अर्थव्यवस्था के मूल में वस्तुओं और सेवाओं की मांग है, जब मांग में गिरावट आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनका प्रभाव मांग पर अनुकूल होना चाहिए। इनकम टैक्स में पांच लाख रुपये तक की आमदनी कर मुक्त करने और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि आदि ऐसे ही कदम हैं। छोटी बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं भी आनी चाहिए। सेविंग्स और फिक्स डिपोजिट पर ब्याज दर इतने कम हो गए हैं कि उनमें धन जमा करना आकर्षक नहीं रहा गया है। शेयरों में निवेश से अभी भी बड़ी संख्या में लोग डरते हैं, क्योंकि कीमतों में इतने उतार-चढ़ाव होते हैं जो आम निवेशक सह नहीं सकते। म्यूचुअल फंड्स में बड़ी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं जो पूंजी बाजार के लिए शुभ संकेत हैं।

औद्योगिक विकास के लिए बचत और निवेश दोनों में वृद्धि की आवश्यकता है। आर्थिक सुधारों को भी तेज करने की आवश्यकता है। जीएसटी में सरलीकरण की और आवश्यकता है। व्यापारियों को रिफंड समय से नहीं मिल रहा है, अफसरशाही अभी भी हावी है। लघु और मध्यम उद्योग और व्यापार इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। मुद्रा योजना में भी नए उद्योग/ व्यापार के लिए धन उतना आसानी से मिलता नहीं जितना प्रशासन दावा करती है।

रोजगार मुहैया करानी की दिशा में सबसे बड़ी समस्या है हमारी निरंतर बढ़ती हुई आबादी। आबादी पर नियंत्रण करके चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को जो ऊंचाई दी है उससे हमें भी सीखने की आवश्यकता है। सकल उत्पाद की दृष्टि से हम विश्व की पांच महान आर्थिक शक्तियों में आ गए हैं, किंतु प्रति व्यक्ति आय में बहुत पीछे हैं, जिसका मुख्य कारण है बेलगाम बढ़ती जनसंख्या।

विदेशी निवेश में भी पिछले कुछ महीनों में करीब एक फीसद की कमी आई है। बाजार में मंदी और चुनाव के परिणामों के बारे में आशंका इसके मुख्य कारण थे। केंद्र में फिर से एक स्थिर सरकार आ जाने पर यह स्थिति शीघ्र ही बदल जाएगी। औद्योगिक उत्पादन को पटरी पर लाना, किसानों की आमदनी और रोजगार के नए अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में होनी चाहिए।

ट्वीट-ट्वीट

जिस देश में हर साल हजारों बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा हो, हजारों बच्चियों की हत्या हो रही हो, उस देश में बीते कई दशकों में दुष्कर्म और हत्या के मामले में इकलौती फांसी साल 2004 में धनंजय चटर्जी नाम के शख्स को हुई और हम सोचते हैं कि फिर कोई निर्भया या अन्य कोई बच्ची नहीं मारी जाएगी। सुशांत सिन्हा @SushantBSinha

महेंद्र सिंह धौनी भारतीय सेना में ले. कर्नल हैं। इसके अलावा उनके पास विशेष बल की मानद उपाधि भी है। आइसीसी के नियम हैं कि खिलाड़ी मैदान में राजनीतिक, धार्मिक व नस्लीय प्रतीक धारण नहीं कर सकते। धौनी के दस्तानों पर बलिदान बैज इस दायरे में नहीं आता।

अभिषेक सिंघवी@DrAMSinghvi

प्रिय बीसीसीआइ, अगर आइसीसी ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करे तो भारतीय सेना की पैरा रेजिमेंट को अपना स्पांसर घोषित कर दें। फिर हर जगह बलिदान बैज को अपने स्पांसर का प्रमुख लोगो घोषित कर दें।

यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी को मिले यथोचित सम्मान

डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय

केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ एक चिंताजनक खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से हिंदी की अनिवार्यता वाले अनुच्छेद को बाहर किया गया है। यह देशहित में सही फैसला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज हिंदी भारतीय जन-मन की अनिवार्यता बन गई है। आज तमिलनाडु के राजनेता भी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों के माध्यम से हिंदी पढ़ा रहे हैं। उनका हिंदी विरोध महज दिखावा और क्षुद्र राजनीतिक कारणों से है। हिंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार भी नेहरू की तरह ढुलमुल रवैया अपनाएगी तो गलत संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह समझना होगा कि उनकी छवि अंग्रेजीपरस्त नेहरू से भिन्न एक राष्ट्रवादी नेता की है। हिंदी के मसले पर झुकने से उनकी छवि को नुकसान होगा। हमारे देश की विविधता को देखते हुए त्रिभाषा सूत्र से बढ़कर कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। केवल तमिलनाडु के विरोध के कारण पूरे देश में इसे न लागू करना भी न्यायोचित नहीं होगा। यदि एक पूर्ण बहुमत की सरकार क्षेत्रीय स्वार्थी तत्वों के दबाव में निर्णय लेगी तो इससे चिंताजनक बात दूसरी नहीं हो सकती।

भारतीय संसद के दोनों सदनों ने जब राजभाषा संकल्प 1968 पारित किया था, तब यह तय किया था कि- 'संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार और उसका विकास करना होगा ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। संकल्प किया गया कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं

के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए।'

यानी उक्त त्रिभाषा सूत्र राज्यों के सहयोग से बनाया गया है और उनकी प्रादेशिक भाषाओं को यथोचित सम्मान दिया गया है। ऐसी स्थिति में केवल राजनीति के लिए विरोध करने वालों को महत्व देने का कोई औचित्य नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना बताती है कि विगत एक दशक में तमिलनाडु में हिंदी 25 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। तमिलनाडु में सक्रिय दक्षिण भारत प्रचार सभा और अन्य संस्थाओं से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि वहां की जनता हिंदी सीखने के लिए कितनी लालायित है। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति हिंदी बोलने अथवा समझने में सक्षम है। विदेशों में भी हिंदी सिखाने वालों की भारी मांग है। तमिलनाडु भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी ने विगत 70 वर्षों में तमाम विरोधों के बावजूद उपलब्धियों के बड़े शिखर पार किए हैं। आज वह संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वह 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा, 24 करोड़ लोगों की दूसरी भाषा और 42 करोड़ लोगों की तीसरी, चौथी अथवा विदेशी भाषा है। उसे 78 प्रतिशत भारतीय बोलने अथवा समझने में सक्षम हैं। वह इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाली सबसे मजबूत कड़ी है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकास का पहिया अपनी भाषा में ही दौड़ता है। विश्व के जिस किसी भी देश ने विकास किया है उसने यह उपलब्धि अपनी भाषा में अर्जित की है। यहां तक कि इजरायल जैसे छोटे से देश ने हिब्रू में उत्कृष्ट तथा मौलिक शोधकार्य करके अब तक 12 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यूरोप के हरेक देश ने अपनी भाषा में विकास किया है। इसी तरह रूस ने रूसी, जापान ने जापानी तथा चीन ने मंदारिन के द्वारा विश्वस्तरीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विश्व के जिन 30 देशों की प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता सबसे अधिक है उनमें से केवल चार देशों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। शेष राष्ट्रों की स्वयं की भाषाएं हैं।

हमें भाषा के मसले पर चीन और जापान से भी सीखने की जरूरत है जिन्होंने अपने-अपने देश में अंग्रेजी को केवल एक विदेशी भाषा के रूप में ही रखा है, न कि शिक्षा के माध्यम के रूप में। हमारी नई पीढ़ी भाषाओं के महत्व को समझ रही है, इसलिए वह स्वयं अनेक भाषाएं सीखना चाहती है। आज भारतीयों के लिए जापानी और जर्मन में रोजगार का बड़ा अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि हमारी शिक्षा का माध्यम हिंदी व भारतीय भाषाएं हों और उन्हें अंग्रेजी के विकल्प के रूप में जापानी, मंदारिन, जर्मन आदि पढ़ने की छूट हो। तभी वे विश्व व्यवस्था के परिचालन में अपनी स्वाभाविक भूमिका पा सकते हैं। ऐसा मनोविज्ञान तथा भाषाविज्ञान दोनों का मानना है कि जिसे कोई एक भाषा बहुत अच्छी तरह आती है वह दूसरी भाषाएं बड़ी सरलता से सीख सकता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी और भारतीय भाषाओं को यथोचित सम्मान मिले और हिंदी का विरोध करने वाले अंग्रेजी के शुभचिंतकों को सही संदेश मिले।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या अलग-अलग चुनाव लड़ने से सपा-बसपा को राजनीतिक रूप से फायदा होगा?

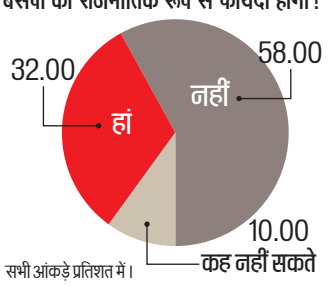

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ट्विंकल-ट्विंकल बुझ गया इक लिटिल स्टार,
हैवानों की आंख में तनिक न उमड़ा प्यार।
तनिक न उमड़ा प्यार दया भी तनिक न आई,
उस नन्हीं सी जान संग थी कौन लड़ाई?
जिसको वह मासूम समझती आई अंकल,
आखिर बनी शिकार उसी जालिम का ट्विंकल।

- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

मुफ्त यात्रा की व्यावहारिकता

अंजलि सिन्हा
स्वतंत्र टिप्पणीकार

दिल्ली मेट्रो रेल व डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का प्रावधान उनके लिए घरों से बाहर निकलकर कुछ नया हासिल करने की राह तैयार करने में मददगार साबित हो सकता है

दिल्ली सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस से दो दिन पहले घोषणा की कि वह दिल्ली मेट्रो रेल और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इसके व्यावहारिक रूप लेने को लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम के साथ तालमेल के जरिये कोई व्यावहारिक राह निकाली जा सकती है, ताकि इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा सके।

पर्यावरण दिवस का उल्लेख यहां पर इसलिए उल्लेखनीय है, क्योंकि पर्यावरण के चिंतनीय हालात, वायु प्रदूषण, सड़कों पर निजी वाहनों की भरमार तथा सड़क पर जाम की समस्या से जूझते लोग आदि मसलों पर जब भी चर्चा चलती है, इसके उपाय ढूंढने की बात चलती है तो सबसे महत्वपूर्ण यही बताया जाता है कि इसका समाधान है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, लेकिन क्या इस दिशा में कुछ किया जा रहा है?

ध्यान रहे हर दिन दिल्ली की सड़कों पर करीब 1,400 नई गाड़ियां उतरती हैं, जिनका बहुलांश निजी गाड़ियों का होता है। एक तरफ जहां मोटर वाहन कंपनियां खपत बढ़ाने के चक्कर में रहती हैं, नई नई स्कीम बनाती रहती हैं, वहीं लोग भी कभी जरूरत की वजह से तो कभी स्टेटस सिंबल के नाम पर निजी गाड़ियां रखने में संकोच नहीं करते। कहने का तात्पर्य कि मेट्रो रेल, बस, लोकल ट्रेनें आदि एक तरफ जहां पर्यावरण के लिहाज से जरूरी हैं, वहीं इसे सुविधाजनक और सस्ता बनाना भी उतना ही जरूरी है, ताकि हर तबके के लोग रोजमर्रा के जीवन को आसान बना सकें।

अब यदि हम महिलाओं के लिए प्रस्तावित मुफ्त यात्रा की बात करें तो इसके पक्ष में इस आधार पर हामी भरी जा सकती है कि इसके चलते सार्वजनिक दायरे में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ सकती है। आज भी यह मुद्दा अहम बना हुआ है कि घर के बाहर के दायरे में उनकी भागीदारी बराबरी की नहीं है। मेट्रो यात्रियों में भी उनकी उपस्थिति 25 से 30 फीसद तक ही बताई जाती है। किसी भी उपाय या बहाने से उन्हें बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहन मिले तो उसका लाभ लेकर इस अंतर को पाटना ही चाहिए। अधिकाधिक लड़कियां तथा महिलाएं पढ़ने या नौकरी, व्यवसाय आदि के लिए बाहर आएं तो जेंडरजनित बराबरी के साथ ही सार्वजनिक दायरे में पितृसत्तात्मक वर्चस्व भी टूटेगा। समझना यह है कि यह कदम प्रोत्साहन तो देगा कि आप बाहर निकलें, लेकिन यदि सार्वजनिक परिवहन कैसा होना चाहिए इसकी बात की जाए तो वह निश्चित ही सस्ता और सुलभ सभी के लिए होना चाहिए, यही मांग बनती है। पश्चिमी देशों में सार्वजनिक परिवहन को जबरदस्त सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने इस मामले में अध्ययन करके पता लगाया है कि बिना सब्सिडी दिए उसे सस्ता नहीं किया जा सकता है।

पर्यावरण की बदतर होती स्थिति को देखते हुए तथा निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए पिछले साल यह खबर भी आई थी कि सभी लोगों के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की योजना दुनिया के कई शहरों में जोर पकड़ रही है। एक शोध अध्ययन में ब्रुसेल्स यूनिवर्सिटी के एक अध्येता ने बताया कि वर्ष 2017 में पूरी दुनिया में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन के 99 नेटवर्क कायम थे, जिनमें से 57 यूरोप में, 27 उत्तरी अमेरिका में, 11 दक्षिणी अमेरिका में, तीन चीन में और एक आस्ट्रेलिया में देखने को मिला। फ्रांस के लगभग दो लाख आबादी वाले शहर डंकर्क में पिछले साल यह योजना लागू की गई, जिसने इसकी प्रेरणा इस्तोनिया की राजधानी तालिन से ली थी, जो 2013 में किसी यूरोपीय देश की ऐसी पहली राजधानी बना था जहां बसों और

ट्रामों में नगरपालिका में पंजीकृत निवासियों के लिए यातायात मुफ्त कर दिया गया था।

दिल्ली की सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को देखें तो वर्ष 2017 में दो चरणों में किराया बढ़ोतरी को लागू किया गया जो पहले से दोगुना हो गया। इससे दैनिक यात्रियों के खर्चे में दोगुनी वृद्धि हुई। ऐसे खर्चे में बढ़ोतरी की सबसे अधिक मार मध्यवर्ग पर पड़ती है। अगर किसी मध्यवर्गीय परिवार में दो बच्चे पढ़नेवाले हों तो ऐसे परिवार पर खर्चा कितना बढ़ा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। शायद सरकार यही सोचती है कि दुनिया के अनुभव के विपरीत सार्वजनिक परिवहन के खर्चे को लोगों से ही वसूला जाए। और जब भी किराये में कटौती की बात चलती है तो सरकारें यही दावा करती हैं कि आखिर सरकार इतनी रकम लाएगी कहां से। सरकारों को प्राथमिकता तय करनी होती है कि उसे सरकारी खजाने को कहां खर्च करना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मुफ्त यात्रा वाली योजना में उसे प्रतिवर्ष 1,200 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, जो वह कर सकती है। यह बड़ी राशि नहीं है फिर क्यों नहीं सरकार इस दिशा में प्रयास करे कि वह समान रूप से सस्ती यात्रा सभी के लिए उपलब्ध करा दे।

इन दिनों कल्याणकारी राज्य की वापसी की बात की जा रही है, जिसके तहत राहत का दायरा सभी किसानों तक बढ़ाने की, छोटे कारोबारियों व किसानों के लिए पेंशन योजना की बात हो रही है। राहुल गांधी ने भी चुनाव के दिनों में किसानों के लिए 'न्याय योजना' का वादा करके किसानों को 72 हजार रुपये देने की बात की थी। सस्ता राशन, सस्ता स्वास्थ्य आदि की चर्चाओं में क्या सस्ता परिवहन की बात पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

कुछ लोगों ने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा वाली योजना की कुछ तकनीकी दिक्कतें भी गिनाई हैं कि कार्ड कैसे बनेगा ताकि कोई अन्य इसका दुरुपयोग नहीं करेगा या एएफसी गेट क्या अलग होगा आदि, लेकिन काम तो विशेषज्ञों को करना है। कहा जा रहा है कि सरकार सक्षम महिलाओं से अपील करेगी कि वे सब्सिडी छोड़ दें तो उसका लाभ जरूरतमंदों को मिले। जैसे मोदी सरकार ने गैस सिलिंडर के लिए अपील की थी। सरकार को करना यह चाहिए कि वह जरूरी चीजों की सूची बना कर सभी के लिए उपलब्ध कराए। अधिक आयवालों को सब्सिडी का लाभ उठाने से वंचित करने के तरीके निकालने चाहिए न कि इसे उनकी सदाशयता पर छोड़ना चाहिए।

खरी-खरी

डेटा के आगे डेटा, पीछे भी डेटा

मृदुल कश्यप

मैं जब उनसे मिलने उनके घर गया तो बाहर से ही अहसास हो गया कि घर के अंदर डेटा के ज्वार-भाटे चल रहे हैं। मैंने घंटी बजाई और दरवाजा खुलने का इंतजार किया। कुछ देर तक हलचल नहीं हुई तो फिर बजाई। फिर भी प्रतिक्रिया नहीं आई तो मैं समझ गया कि अंदर सब डेटा के सागर में डूबे होंगे। तब मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैंने लिखा, मैं घर के बाहर खड़ा हूं। दरवाजा खोलिए। मैसेज भेजते ही प्रतिक्रिया आई और एक हाथ में मोबाइल पकड़े, कान में ईयरफोन ठूंसे वक्त से पहले जवान हुए बच्चे ने एक हाथ से गेट खोला और स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए ही बोला- गुड मॉर्निंग अंकल! प्लीज कम।

मैं अंदर घुसा और जैसा मैंने अंदाजा लगाया था, सबकुछ वैसा ही था। घर में पपी को छोड़ हर सदस्य डेटा में गोते लगा रहा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, अनलिमिटेड जीबी डेटा बिखरा था। ड्राइंग रूम, बैडरूम, किचन, यहां तक कि वॉशरूम में भी।

घर के मुखिया ने टैबलेट की स्क्रीन से नजर न हटाते हुए कहा- आइए! कह कर वे फिर डेटा की लहर का लुत्फ उठाने लगे। मैंने जब परिचय देते हुए कहा, मैं आपका पड़ोसी, तो उनका बच्चा बोल पड़ा- हां, हम आपको जानते हैं। आपका वाईफाई आकाश नाम से हमारे घर तक आता है। मैंने कहां- हां, वह मेरे बेटे का नाम है।

किचन से मोबाइल हाथ में लिए भाभी जी आईं और बोली- आइए भाई साहब। इतना कह कर वह भी डेटा में डूब गईं। कहीं मुझ पर भी समय के साथ ना चलने का ठप्पा न लग जाए यह सोचकर मैंने भी मोबाइल निकाला और उसे देखने लगा। पपी ने मेरी तरफ देखा और निराशा से अपना सिर नीचे पैरों में रख लिया। कौन-सा मोबाइल है अंकल? उनके छोटे बेटे ने अब बात की। मैंने उसे नाम बताया तो वह आतिथ्य की गरज से बोला- अच्छा है! आपको हमारे वाईफाई का पासवर्ड दूं? मैंने हां कहा तो वह बोला- अतिथि तुम क्यों आए हो? क्या यह पासवर्ड है? मैंने पूछा! जी अंकल, मस्त टफ है ना?

मैंने पासवर्ड डाला और वाईफाई चालू। मैं डेटा में डूबने को ही था कि लाइट चली गई। वाईफाई बंद, डेटा का सागर लुप्त। अब सब बेरोजगार थे। मैंने सुझाया कि मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट है। यह सुन सबकी जान में जान आई। हॉटस्पॉट चालू किया तो सबने पूछा पासवर्ड क्या है! मैंने कहा- डेटा से कब बाहर आओगे?

राष्ट्रीय संस्करण
शनिवार 8 जून 2019
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

कोटक महिंद्रा बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा

मुंबई, प्रेट्र : आरबीआइ ने कोटक महिंद्रा बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगा दिया। प्रमोटर्स हिस्सेदारी घटाने को लेकर आरबीआइ के निर्देश का पालन नहीं किए जाने के कारण बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बीएसई को दी गई सूचना में कहा कि वह आरबीआइ के निर्देश का विश्लेषण कर रहा है। आरबीआइ के नियमों के मुताबिक निजी बैंक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी संचालन के पहले तीन साल में घटाकर 40 फीसद, 10 साल के भीतर 20 फीसद और 15 साल के भीतर 15 फीसद तक लाया जाना जरूरी है।

खाद्यान्न प्रबंधन को राज्यों की राय से ही पुख्ता बनाया जा सकता है। सरकार मानसून से पहले भंडारण की पूरी व्यवस्था की कोशिशों में जुटी है।
— रामविलास पासवान
खाद्य मंत्री

सेंसेक्स	39,615.90 ▲ 86.18	निफ्टी	11,870.65 ▲ 26.90	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 33,420 ▼ ₹70	चांदी प्रति किलोग्राम	₹38,000 ▲ ₹100	$ डॉलर	₹69.46 ▲ ₹0.18	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 62.47

वजह ▶ साइलोज निर्माण में देरी की होगी जांच, तीन सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

एफसीआइ पर भड़के पासवान, जांच के आदेश

पुख्ता खाद्य प्रबंधन के लिए खाद्य सचिवों व मंत्रियों की बैठक जल्द होगी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भारतीय खाद्य निगम के कामकाज पर सख्त नाराजगी जताई है। खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए साइलोज निर्माण की धीमी गति की जांच कराने का आदेश दिया है। इसके लिए एफसीआइ के प्रबंध निदेशक को तीन सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। एक करोड़ टन भंडारण क्षमता वाले साइलोज बनाने का लक्ष्य के मुकाबले केवल 6.7 लाख टन वाले साइलोज (आधुनिक गोदाम) का निर्माण हो पाया है। पासवान ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करते हुए एफसीआइ के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने खाद्य प्रबंधन को चुस्त-दुरुस्त करने की कारगर पहल की है। इसके तहत राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए पहले खाद्य सचिवों और फिर प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें खाद्यान्न की सरकारी खरीद, भंडारण, निकासी, राशन प्रणाली और पूरे बंदोबस्त में पारदर्शिता लाने जैसे विषय पर सभी के साथ गुफ्तगू होगी।

साइलोज निर्माण में देरी के चलते मानसून से पहले पूर्ण भंडारण बड़ी चुनौती बन गया है। फाइल

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में खाद्यान्न प्रबंधन को राज्यों के साथ मिलकर ही पुख्ता बनाया जा सकता है। इसके लिए उनकी राय लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 27 जून को राजधानी दिल्ली में सभी राज्यों के खाद्य सचिवों को बुलाया जाएगा, जबकि जुलाई के दूसरे सप्ताह में खाद्य मंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा।

एफसीआइ की कार्यप्रणाली पर नाखुशी जताते हुए पासवान ने कहा कि भंडारण की आधुनिक प्रणाली से देश में एक करोड़ टन भंडारण क्षमता वाले साइलोज बनाने की योजना थी, जो बहुत धीमी गति से चल रही है। अब तक सात लाख टन क्षमता वाले साइलोज बनाये जा सके हैं। जबकि 22 लाख टन क्षमता के साइलोज की कागजी खानापूरी हो रही है। साइलोज के डिजाइन में जरूरी बदलाव के लिए भी एक एजेंसी अध्ययन करेगी। इसकी भी रिपोर्ट हर हाल में 90 दिनों के भीतर आनी है। इसके बाद संशोधित नीति लागू कर दी जाएगी। एफसीआइ को डिजिटल बनाने की दिशा में बहुत प्रगति नहीं हुई है। एफसीआइ के गोदामों और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदामों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। लेकिन राज्यों के साथ इनका संपर्क अभी तक नहीं हो सका है। इस पर भी पासवान ने तल्खी दिखाई। एफसीआइ में सूचना प्रौद्योगिकी का कारगर उपयोग न होने से यहां के कर्मचारियों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

एफसीआइ में समान श्रेणी के होंगे सभी 40 हजार श्रमिक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारतीय खाद्य निगम के चालीस हजार श्रमिकों की अब एक समान श्रेणी होगी। उन्हें वेतन और सुविधाएं भी एक जैसी मिलेंगी। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के कामकाज को तर्कसंगत बनाने के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने विशेष पहल की है। इसके तहत निगम में सुधार की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से तेज किया जाएगा। पासवान ने एफसीआइ की पूरी कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

उन्होंने कहा कि एफसीआइ में 40 हजार श्रमिक फिलहाल तीन श्रेणियों में बंटे हुए हैं। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ भरा जा रहा है। निगम में अलग-अलग श्रेणियों में विभागीय श्रमिकों के अलावा डेली पेमेंट, नो वर्क नो पेमेंट और ठेकेदारी प्रथा के मजदूर कार्यरत हैं। पासवान ने कहा कि विभागीय श्रमिकों को सबसे अधिक वेतन मिलता है। जबकि अन्य श्रेणियों को काम के अनुसार मजदूरी मिलती है।

श्रम सुधार

- अलग-अलग श्रेणी के श्रमिकों की व्यवस्था होगी समाप्त
- छह महीने में रिक्त पदों पर हो जाएगी नियुक्ति, बरती जाएगी पारदर्शिता

पासवान ने जोर देकर कहा कि अगले छह महीने के भीतर एफसीआई के सभी श्रमिकों को एक श्रेणी में कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें समान वेतन भी मिलने लगेगा। इन श्रमिकों को वेतन के अलावा और पेंशन समेत अन्य सुविधाएं देने पर सरकार विचार कर रही है। एक सवाल के जवाब में पासवान ने कहा कि निगम की 30-40 श्रमिक यूनियनों में से ज्यादातर ने श्रमिकों को एक श्रेणी में करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

केंद्र की राजग सरकार के पहले कार्यकाल 2014 से 2019 तक कुल 5832 रिक्तियां भरी गई। नियुक्तियों की यह प्रक्रिया लगभग एक दशक बाद शुरु की गई थी। सारी नियुक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के मार्फत हुईं। जबकि 4003 कर्मचारियों की नियुक्तियों की प्रक्रिया चालू है।

सस्ता निर्यात कर्ज मुहैया कराने की कवायद शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की निर्यात व बैंकिंग क्षेत्र के साथ बैठक
- कहा - रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल के विकल्प पर करे विचार

सरकार ने निर्यातकों को सस्ती दरों पर निर्यात कर्ज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कवायद शुरू कर दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक से अपने विदेशी मुद्रा भंडार से निर्यातकों को कर्ज की संभावनाएं तलाशने को कहा है। साथ ही निर्यात संगठनों के फेडरेशन फियो को 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है जिसमें निर्यात क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निदान सुझाए गए हों।

निर्यात क्षेत्र से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के क्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को निर्यातकों और बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में गोयल ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से अपने विदेशी मुद्रा भंडार से निर्यातकों के लिए 25 अरब डॉलर के कर्ज की संभावना तलाशने को कहा। वाणिज्य मंत्री ने माना कि अगले पांच वर्ष में एक लाख करोड़ डॉलर मूल्य के वस्तु और इतनी ही राशि के सेवा निर्यात का लक्ष्य पाना तभी संभव होगा जब इस क्षेत्र को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध हो। उन्होंने विदेशी मुद्रा में निर्यातकों को कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में लिबोर पर अतिरिक्त 200 बेसिस प्वाइंट के साथ कर्ज की संभावनाएं तलाशने को भी रिजर्व बैंक से कहा।

फियो से मांगे सुझाव : वाणिज्य मंत्री ने फियो से 30 जून तक सब्सिडी के स्थान पर सस्ते विदेशी मुद्रा कर्ज की संभावनाएं तलाशने को कहा है। साथ ही सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक निर्यात कर्ज को प्राथमिकता क्षेत्र में रखने की संभावना पर भी विचार करे। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों मसलन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए विदेशी मुद्रा कर्ज में गारंटी कवर के तौर पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) के विकल्प की संभावना तलाशने को कहा है। निर्यातकों खासतौर पर एमएसएमई क्षेत्र को विदेशी मुद्रा में सरकारी बैंकों से निर्यात कर्ज दिलाने में एक्जिम बैंक की भूमिका पर भी विचार हो रहा है। फियो से इस बात की संभावना भी तलाशने को कहा गया है कि क्या इसके लिए एक्जिम बैंक सरकारी बैंकों को रिफाइनेंस कर सकता है। फियो को अगले 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट वाणिज्य मंत्री को देनी है। इस संबंध में अगली बैठक मुंबई में 30 जून को होगी।

क्या है लिबोर

लंदन इंटर-बैंक ऑफर्ड रेट (लिबोर) ब्याज दर तय करने का एक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंक आपस में एक-दूसरे को इसी दर पर शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। इस दर का निर्धारण और प्रकाशन दैनिक आधार पर इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आइसीई) द्वारा किया जाता है।

जेट के बंद होने से दूसरों की किस्मत चमकी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इस वर्ष अप्रैल में निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एयरवेज के अस्थायी रूप से बंद होने के बाद भारतीय एयरलाइन उद्योग के दबावग्रस्त होने की बातें की जाने लगी थीं। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जेट के बंद होने से भारतीय विमानन कंपनियों की माली हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वे डेढ़ दशक का सर्वाधिक मुनाफा कमाने में सफल रहें।

सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन (कापा) के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय विमानन कंपनियों को संयुक्त रूप से 3,500-4,800 करोड़ रुपये तक का मुनाफा हो सकता है। दिलचस्प यह है कि इसी अवधि के दौरान घरेलू हवाई यातायात की वृद्धि दर पांच फीसद से भी कम रहने की संभावना है। कापा की जून की रिपोर्ट इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसकी फरवरी की रिपोर्ट में विमानन कंपनियों को चालू वर्ष में 40-45 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया था।

कापा के अनुसार भारतीय एयरलाइन उद्योग को इस समय तीन प्रमुख लो बजट कंपनियां इंडिगो, स्पाइसजेट और गोएयर नियंत्रित कर रही हैं। इनमें अकेले इंडिगो का मुनाफा अगले वर्ष 2,700 से 3400 करोड़ रुपये के बीच रहने वाला है, जो तीनो एयरलाइनों के पिछले वर्ष के कुल मुनाफे से भी ज्यादा है। यही नहीं, इस वर्ष इंडिगो का मुनाफा पिछले वर्ष के मुकाबले सात गुना रहने की उम्मीद है।

कापा के मुताबिक तो अभी 49.9 फीसद बाजार हिस्सेदारी के साथ इंडिगो भारत की अग्रणी एयरलाइन है। जबकि 13.9 फीसद हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया दूसरे और 13.1 फीसद हिस्सेदारी के साथ स्पाइसजेट तीसरे नंबर पर है। 10.8 फीसद हिस्सेदारी वाली गोएयर चौथे स्थान पर है। बाकी 12.3 फीसद हिस्से पर टाटा विस्तारा, एयर एशिया एवं अन्य छोटी कंपनियों का कब्जा है। लेकिन जेट एयरवेज के बंद होने से मिलने वाले अतिरिक्त यातायात के कारण स्पाइसजेट का बाजार हिस्सा सालभर के भीतर 25 फीसद पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। एयर इंडिया को भी फायदा होगा और वो 2020 में शुद्ध मुनाफे की स्थिति में पहुंच सकती है। वित्त वर्ष 2017-18 में एयर इंडिया को 5348 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था।

हालांकि भारतीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने में बाजार हिस्सेदारी के मुकाबले बढ़े किराये की भूमिका अधिक रहेगी, जो पिछले पांच महीनों में औसतन 10 फीसद बढ़ गए हैं। जेट के हटने से प्रतिस्पर्द्धा घटने के कारण जनवरी-मार्च के दौरान इंडिगो के किराये में औसतन 12 फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

जेट की उड़ाने बंद होने से विमानन कंपनियों की प्रमुख चुनौतियां लगभग खत्म हो गई हैं। इनमें क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाना, पायलटों की कमी और एयरपोर्ट स्लॉट की अड़चनें शामिल हैं। इससे उन्हें मुनाफा बढ़ाने और बैलेंस शीट सुधारने का मौका मिल गया है।

पेचीदा सड़क परियोजनाएं लेंगी गडकरी की परीक्षा

संजय सिंह, नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी ने 100 दिनों में लंबित राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा कराने का वादा तो कर दिया है। लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। कुछ पेचीदा सड़क परियोजनाएं ऐसी वजहों से अटकी हैं जिनका समाधान बेहद कठिन है। इतने कम समय में सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं को पूरा करना संभव है जिनकी समस्याओं को पहले सुलझा लिया गया हो। गडकरी ने इसीलिए सिर्फ 20-25 परियोजनाओं को लक्षित किया है। असल में लंबित सड़क परियोजनाओं की संख्या इससे ज्यादा है।

बीते दिसंबर तक देश में 3.97 लाख करोड़ रुपये लागत की कुल 719 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही थीं। इनमें से 71 सड़क परियोजनाएं समय से पीछे थीं। इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा करने वाली रेटिंग एजेंसी 'केयर' की रिपोर्ट के अनुसार इनमें भी 45 परियोजनाओं की लागत बढ़ गई थी। इनमें से अनेक परियोजनाएं वर्ष 2014 से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए शासनकाल में शुरू हुई थीं।

- 100 दिनों में लंबित परियोजनाएं पूरी करने का राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य इतना आसान नहीं
- इससे पहले ज्यादातर परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, वित्तीय और कानूनी पचड़ों से हुई देरी

बिना मंजूरी के शुरू हुई थीं परियोजनाएं : उन परियोजनाओं की लागत बहुत बढ़ गई जिन्हें जमीन अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग और वन एवं पर्यावरण मंजूरी जैसी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर हरी झंडी दिखा दी गई। इस कारण इनकी शुरुआत ही देर से हुई थी। कई परियोजनाएं बाद के चरणों में कर्ज देने में बैंकों की आनाकानी, मुकदमों और टोल विवादों के कारण पिछड़ती चली गईं। ऐसी परियोजनाओं में दिल्ली-आगरा, पानीपत-जालंधर, मेरठ-देहरादून, वाराणसी-लुंबिनी, दिल्ली-जयपुर तथा जम्मू-श्रीनगर हाईवे चौड़ीकरण की परियोजनाएं प्रमुख हैं, जिन पर अभी भी किसी न किसी स्तर पर काम चल रहा है।

सड़क निर्माण में जबरदस्त तेजी के बावजूद राजग सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ सड़क परियोजनाएं भी अटक गई हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर अवार्ड की गईं 100 से ज्यादा परियोजनाओं में से लगभग 65 फीसद पर ही काम शुरू हो सका है। जबकि भूमि अधिग्रहण की विभिन्न अड़चनों के कारण 35 फीसद परियोजनाओं को अभी तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की अनुमति नहीं मिली है। नई सरकार इन्हें आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

आइएलएंडएफएस की मार : अटकी हुई राजमार्ग परियोजनाओं में लगभग 10 का संबंध उन निर्माताओं से है, जिनका कार्यान्वयन इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आइएलएंडएफएस) द्वारा किया जा रहा था।

एनएचएआइ ने आइएलएंडएफएस से इन सभी परियोजनाओं को वापस करने को कहा है, ताकि इन्हें अन्य कंपनियों को सौंपा जा सके। इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केंद्र सरकार स्वयं पूंजी निवेश कर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोक्योरमेंट (ईपीसी) मोड से पूरा करेगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 15 हजार करोड़ रुपये है। इनमें जम्मू-कश्मीर की रणनीतिक महत्व वाली जेड-मोड़ सुरंग परियोजना शामिल है। यह परियोजना देश की सबसे लंबी मानी जाने वाली जोजिला सुरंग परियोजना के अतिरिक्त है, जिसका ठेका भी विलंब के कारण दोबारा देना पड़ा था।

माइंडट्री के अधिग्रहण के लिए ओपन ऑफर लाई एलएंडटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने शुक्रवार को आइटी कंपनी माइंडट्री के लिए 5,030 करोड़ रुपये का ओपन ऑफर पेश किया। इसके तहत वह माइंडट्री की 31 फीसद अतिरिक्त हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह अधिग्रहण प्रति शेयर 980 रुपये की दर पर होगा। एलएंडटी पहले ही माइंडट्री की 28.90 फीसद हिस्सेदारी खरीद चुकी है। यदि कंपनी ओपन ऑफर के तहत प्रस्तावित सभी शेयर खरीदने में कामयाब हो जाती है, तो आइटी कंपनी में एलएंडटी की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 60 फीसद हो जाएगी।

एलएंडटी कुल मिलाकर माइंडट्री की करीब 66 फीसद हिस्सेदार खरीदना चाहती है। इसके लिए वह 10,700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। ओपन ऑफर 17 जून को शुरू होगा और 28 जून को बंद होगा। माइंडट्री द्वारा बीएसई को भेजे गए ऑफर पत्र में कहा गया है कि एलएंडटी इसके तहत माइंडट्री के 5,13,25,371 शेयर खरीदेगी, जो उसकी 31 फीसद हिस्सेदार के बराबर है। एलएंडटी का ओपन ऑफर पहले 14 मई को शुरू होने वाला था। लेकिन कंपनी सेबी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही थी।

प्रीमियम सेग्मेंट में सुजुकी की पकड़ और मजबूत

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने दो नए मॉडल जीआइएक्सएक्सईआर-250 एसएफ और जीआइएक्सएक्सईआर-एसएफ लांच किए हैं। इनमें जीआइएक्सएक्सईआर-250 एसएफ की कीमत 1.70 लाख रुपये और एसएफ की 1.09 लाख रुपये रखी गई है। प्रेट्र

बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों ने बाजार को संभाला

मुंबई, प्रेट्र : नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) की नकदी से जुड़ी चिंता के बावजूद बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में खरीदारी से शुक्रवार शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 86.18 अंकों की तेजी के साथ 39,615.90 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 26.90 अंकों की तेजी के साथ 11,870.65 पर बंद हुआ। सप्ताहभर के कारोबार में हालांकि सेंसेक्स में 98.30 अंकों और निफ्टी में 52.15 अंकों की गिरावट रही।

सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक में सर्वाधिक 1.90 फीसद तेजी रही। बजाज फाइनेंस में 1.69 फीसद, भारतीय स्टेट बैंक में 1.36 फीसद, आइसीआइसीआइ बैंक में 1.28 फीसद, एचडीएफसी बैंक में 0.95 फीसद और एचडीएफसी में 0.95 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर यस बैंक में सर्वाधिक 2.37 फीसद गिरावट रही। सेक्टरों के लिहाज से बीएसई के टेलीकॉम सेक्टर में सर्वाधिक 0.79 फीसद तेजी रही। दूसरी ओर यूटिलिटीज सेक्टर में सर्वाधिक 1.29 फीसद गिरावट रही। बीएसई के मिडकैप इंडेक्स में 0.17 फीसद और स्मॉलकैप में 0.11 फीसद गिरावट रही।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि एनबीएफसी सेक्टर की समस्या को देखते हुए निवेशकों ने चुनिंदा ब्लूचिप बैंकिंग शेयरों पर दांव लगाया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सुस्ती के कारण दुनियाभर के केंद्रीय बैंक ब्याज दर में कटौती की तरफ बढ़ रहे हैं। यह दुनियाभर के बाजारों के लिए सकारात्मक है, लेकिन निवेशकों में ट्रेड वार की चिंता कायम है। निवेशक आगामी बजट और अमेरिका के रोजगार आंकड़ों से भविष्य के लिए संकेत लेंगे।

- सेंसेक्स 86.18 अंकों की तेजी के साथ 39,615.90 पर बंद
- निफ्टी 26.90 अंकों के उछाल के साथ 11,870.65 पर स्थिर

प्रतीकात्मक

डीएचएफएल 11.08 फीसद लुढ़का : दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (डीएचएफएल) के शेयरों में लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। कंपनी के शेयर बीएसई पर 11.08 फीसद गिरकर 83.50 रुपये पर बंद हुए। कंपनी मंगलवार को 960 करोड़ रुपये के डिबेंचर्स पर ब्याज भुगतान में विफल रही थी। इसके बाद रेटिंग एजेंसी इक्रा और क्रिसिल ने कंपनी के 850 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर की रेटिंग घटा दी थी। कंपनी ने शुक्रवार को है कि वह सात दिनों के भीतर ब्याज का भुगतान सुनिश्चित करेगी।

ईरोज इंटरनेशनल में 14 फीसद से अधिक गिरावट

नई दिल्ली : इरोज इंटरनेशनल मीडिया के शेयर बीएसई पर 14.41 फीसद गिरकर 45.45 रुपये पर बंद हुए। गुरुवार को भी कंपनी के शेयर करीब 20 फीसद लुढ़के थे। रेटिंग एजेंसी केयर ने बुधवार को कंपनी की बैंकिंग सुविधा की रेटिंग संशोधित कर 'केयर डी' कर दी थी। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजारों को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा था कि अप्रैल 2019 और मई 2019 में बैंक लोन के भुगतान में देरी होने के कारण रेटिंग बदली है। अगले सात कार्यदिवसों के भीतर लोन का भुगतान कर दिया जाएगा।

चुनौती

शॉर्ट टर्म लोन लेने और लांग टर्म लोन देने का मॉडल है समस्या की बड़ी वजह, घरेलू बाजार में कर्ज के रास्ते बंद, विदेशी कर्ज तलाश रहीं एनबीएफसी

डीएचएफएल मामले से सेक्टर को कर्ज में और मुश्किलें : फिच

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी एजेंसी फिच ने कहा है कि डीएचएफएल की नकदी की समस्या और ब्याज भुगतान में उसके डिफॉल्ट से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के सामने फंडिंग की चुनौतियां उजागर हो गई हैं। इसके चलते कर्ज की रफ्तार और धीमी हो सकती है। इसके विपरीत एनपीए की विकट समस्या और बैंकों की वित्तीय हालत कमजोर होने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में नकदी का संकट नहीं है। जबकि बैंकों की तरफ से कर्ज की रफ्तार पहले से ही धीमी है।

फिच ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि एनबीएफसी क्षेत्र से जुड़े मसलों के बारे में बाजार को पहले ही सब मालूम है, लेकिन आइएलएंडएफएस के कर्ज संकट के बाद पूरा फोकस दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) पर हो गया था। पिछले वर्ष सितंबर में आइएलएंडएफएस का मामला सामने आने के बाद से ही निवेशकों ने एनबीएफसी सेक्टर से हाथ खींच लिए थे, जो पूरे क्षेत्र में लिक्विडिटी समस्या गहराने की मूल वजह बनी। फिच का मानना है कि बाजार के लिहाज से एनबीएफसी की नकदी की समस्या को काफी संवेदनशील मसले के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल शॉर्ट टर्म के लिए थोक फंडिंग पर निर्भर रहता है। बाजार की अवधारणा में नकारात्मक बदलाव होने से इन कंपनियों की फंडिंग का स्रोत जल्द सूख जाता है। फिच के मुताबिक हाउसिंग फाइनेंस और लोन कंपनियां इसीलिए नकदी की समस्या में घिरती हैं क्योंकि ये कम अवधि के लिए कर्ज लेकर लंबी अवधि के लिए कर्ज बांटने के व्यवसाय में हैं। इन कंपनियों पर बने इस दबाव ने देश की शीर्ष गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को फंडिंग के अन्य विकल्प तलाशने को बाध्य कर दिया है। इसके लिए ये कंपनियां अमेरिकी डॉलर बांड बाजार में संभावनाएं तलाश रही हैं।

अपनी रिपोर्ट में फिच ने कहा है कि फंडिंग में कमी की वजह से एनबीएफसी की फंड लागत भी अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त इसका असर एनबीएफसी के कर्ज की वृद्धि दर पर भी पड़ा है। एजेंसी का मानना है कि आगे भी देश में कर्ज की दर में कमी बनी रह सकती है। बैंकों की तरफ से पहले ही कर्ज देने की रफ्तार थमी हुई है। लिक्विडिटी की इस किल्लत की वजह से एनबीएफसी की तरफ से भी कर्ज की रफ्तार धीमी होने की आशंका है। हालांकि अभी एनबीएफसी की कुल कर्ज में हिस्सेदारी 20 फीसदी ही है।

विदेशी बाजारों में कर्ज की तलाश प्रतीकात्मक

यूटीआइ ने डीएचएफएल को दिए कर्ज को बट्टा खाते में डाला

नई दिल्ली : यूटीआइ म्यूचुअल फंड (यूटीआइएमएफ) ने शुक्रवार को कहा कि उसने डीएचएफएल को दिए पूरे कर्ज को बट्टा खाते में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने मान लिया है कि इस कर्ज की वसूली निकट भविष्य में नहीं हो पाएगी। इसी सप्ताह मंगलवार को डीएचएफएल अपने एक कर्ज और उस पर ब्याज का भुगतान करने में विफल रही थी। उसके अगले दिन अग्रणी रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल, इकरा और केयर ने कंपनी के कई कर्जों की रेटिंग घटाकर 'डिफॉल्ट' की श्रेणी में डाल दिया। यूटीआइएमएफ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि डीएचएफएल में पिछले दिनों हुए घटनाक्रमों को देखकर लगता है कि कई कर्जदाता उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वसूली में और देरी होने की आशंका है। इसी को देखते हुए उसने डीएचएफएल को दिए समूचे कर्ज को बट्टा खाते में डाल दिया है।

डिफॉल्ट से पहले ही समाधान योजना पर काम

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

आरबीआइ का कहना है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को किसी कंपनी के डिफॉल्ट के तत्काल बाद लोन खाते की दिक्कतों को पहचानते हुए इसे स्पेशल मेंशन एकाउंट के रूप में दर्ज करना चाहिए। चूंकि किसी एक कर्जदाता के मामले में कंपनी के डिफॉल्ट करने से ही उस कंपनी के वित्तीय संकट का अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि अन्य कर्जदाता उस कंपनी के डिफॉल्ट होने से पहले ही एक समाधान योजना पर काम करना शुरू कर देंगे।

नए नियमों के मुताबिक अगर कोई कंपनी किसी एक बैंक के साथ भी डिफॉल्ट करती है तो अन्य वित्तीय संस्थानों को 30 दिन के भीतर उस खाते की समीक्षा करनी चाहिए। इस दौरान ये वित्तीय संस्थान इस कर्ज को फंसने से बचाने के उपाय तलाश सकते हैं और उसका हल लागू करने की योजना बना सकते हैं। इस अवधि के दौरान अगर कोई समाधान योजना लागू की जाती है तो बैंकों को मिलकर एक इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट यानी कर्जदाता समझौता करना चाहिए।

इसलिए नए दिशानिर्देश की जरूरत : आरबीआइ ने पिछले वर्ष 12 फरवरी को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के फंसे कर्ज (एनपीए) से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके तहत अगर कोई कंपनी किसी बैंक का लोन चुकाने से एक दिन भी चूक जाती थी तो उसे एनपीए मानकर बैंकों को 180 दिन के भीतर उसका समाधान करना होता था अन्यथा वह मामला दिवालिया कोर्ट में चला जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इन दिशानिर्देशों को गैरकानूनी करार देते हुए खत्म कर दिया था। यही वजह है कि आरबीआइ को नया फ्रेमवर्क जारी करने की जरूरत पड़ी।

नए नियमों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे अस्थायी तौर पर वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रही कंपनियों को भी फायदा होगा, कर्जदाताओं को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और बाजार में तरलता प्रवाह बढ़ेगा।

अपने बलबूते अमीर बनने वाली अमेरिकी महिलाओं में तीन भारतीय मूल की

फोर्ब्स ने अपने बलबूते अमीर बनने वाली अमेरिका की 80 महिलाओं की सूची जारी की है। इस सूची में भारतीय मूल की तीन महिलाओं को भी स्थान मिला है। इन महिलाओं ने न सिर्फ नये कारोबार खड़े किए बल्कि इनसे अपार संपत्ति भी अर्जित की। अमेरिका द रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमन 2019 नामक इस सूची में शीर्ष पर एबीसी सप्लाय की चेयरपर्सन डिएन हेंड्रिक्स हैं। इनके पास सात अरब डॉलर की संपत्ति है। वहीं भारतीय मूल की अरिस्टा नेटवर्क्स की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जयश्री उल्लाल 18वें स्थान पर प्रौद्योगिकी (आइटी) क्षेत्र में परामर्श देने वाली तथा आउटसोर्सिंग सुविधाएं देने वाली कंपनी सिंटेल की सह-संस्थापक नीरजा सेठी 23वें स्थान पर और स्ट्रीमिंग डेटा प्रौद्योगिक कंपनी कॉन्फ्लुएंट की मुख्य तकनीकी अधिकारी एवं सह-संस्थापक नेहा नरखेड़े 60वें स्थान पर हैं।

18 जश्री उल्लाल
58 वर्षीय उल्लाल के पास अरिस्टा के शेयरों की पांच फीसद हिस्सेदारी के साथ 1.40 अरब डॉलर की संपत्ति है। लंदन में पैदा हुईं तथा भारत में पली-बढ़ी। अब वह अमेरिका की सबसे धनी महिला कार्यकारियों में से एक हैं।

23 स्थान नीरजा सेठी
1980 में 64 वर्षीय नीरजा ने अपने पति भारत सेठी के साथ मिलकर मिशीगन में मौजूद अपने अपार्टमेंट में दो हजार डॉलर के मामूली निवेश के साथ सिंटेल कंपनी की स्थापना की थी। उनके पास अभी एक अरब डॉलर की संपत्ति है।

60 नेहा नरखेड़े
34 वर्षीय नेहा नरखेड़े के पास 36 करोड़ डॉलर की संपत्ति है। 2.5 अरब डॉलर बाजार मूल्य वाली उनकी कंपनी के ग्राहकों में गोल्डमैन सैक्श, नेटफ्लिक्स और उबर जैसी कंपनियां शामिल हैं।

01 डिएन हेंड्रिक्स
पेशा : कारोबारी

अपनी किस्मत गढ़ने वाली कुछ लोकप्रिय अमेरिकी महिलाएं।

स्थान

10 ओपरा विनफ्रे
पेशा : टीवी होस्ट

12 शेरिल सैंडबर्ग
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर

51 बियोंसे
पॉप सिंगर

39 मडोना
पॉप सिंगर

37 रिहाना
पॉप सिंगर

80 सेरेना विलियम्स
टेनिस खिलाड़ी

दुबई में सड़क हादसा, 12 भारतीयों समेत 17 की मौत

दुर्घटना ▶ रास्ते में लगे साइनबोर्ड से टकरा गई ओमान से आ रही बस

नौ यात्री घायल, पांच की हालत गंभीर

दुबई, प्रेट्र : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई शहर में एक बस रास्ते में लगे साइनबोर्ड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में बारह भारतीयों समेत 17 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें से ज्यादातर ओमान में रहने वाले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहां ईद की छुट्टियां मनाकर लौटे थे। बस में 31 यात्री थे। गुरुवार को हुई इस दुर्घटना में नौ लोग घायल हुए हैं जिनमें पांच की हालत गंभीर है।

भारतीय वाणिज्य दूतावास का कहना है कि हादसे में जान गंवाने वाले कुछ लोगों के परिजनों से संपर्क कर लिया गया है और अन्य के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दूतावास के अनुसार, दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीयों में रंजन गोपालन, फिरोज खान पठान, रेशमा फिरोज खान पठान, दीपक कुमार, जमालुद्दीन अर्कावेत्तिल, किरन जॉनी, उमर चोनोकवदथ, नबील उमर, विमल कुमार कार्तिकेयन, वासुदेव विशनदास, रोशनी मूलचंदानी और विक्रम जवाहर ठाकुर शामिल हैं जमालुद्दीन दुबई की मीडिया फर्म में काम करते थे। उनकी पत्नी और बेटियां केरल में रहती हैं। केरल से ही ताल्लुक रखने वाले उमर अपने बेटे नबील के साथ ओमान से लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वाले दीपक भी केरल से थे। उनकी पत्नी और चार साल की बेटी घायल हैं।

दुबई की शेख मोहम्मद जाएद रोड पर साइन बोर्ड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। हादसे की यह तस्वीर दुबई पुलिस हेडक्वार्टर से जारी की गई। एपी

यह हादसा उस वक्त हुआ जब ओमान से आई बस गलत दिशा से अल रशीदिया मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। साइनबोर्ड से टकराने के कारण बस के बाएं हिस्से की खिड़कियां टूट गईं। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पीड़ितों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक ट्वीट में दूतावास ने कहा, 'महावाणिज्यदूत व अन्य अधिकारी घायलों और उनके परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों ने अस्पताल और पुलिस प्रशासन के कर्मियों से भी मुलाकात की।'

विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया शोक : भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर शोक जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, 'दुबई में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से आहत हूं जिसमें 12 भारतीयों की जान चली गई। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'

यूएन की प्रतिबंध कमेटी में पारदर्शिता न होने पर भारत ने रोष जताया

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध कमेटी के कामकाज में पारदर्शिता न होने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा, पारदर्शिता के अभाव में ही पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में एक दशक का समय लग गया। भारत का यह रुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के एक महीने बाद सामने आया है।

सुरक्षा परिषद की सहायक कमेटियों का उल्लेख करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा, कई कमेटियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए उनका गठन हुआ है। ये किसी भी व्यक्ति या संस्था पर प्रतिबंध लगाती है या उसे प्रतिबंध से मुक्त करती हैं। अब इन कमेटियों के कामकाज के तरीके पर खुली बहस की जरूरत है। क्योंकि इन कमेटियों के कामकाज की कोई नियमावली नहीं है और ये सुरक्षा परिषद के किसी संकल्प से बंधी हुई नहीं हैं। ये कमेटियां पारदर्शिता के मानदंडों से परे काम करती हैं। इनके बहुत सारे फैसले और बातचीत की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय बिरादरी जान भी नहीं पाती है। नायडू ने कहा, सदस्य देशों के आवेदन पर निर्णय या उसे अस्वीकार करने की कमेटी की प्रक्रिया को भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, न ही औपचारिक रूप से संबंधित देश को इसकी समुचित जानकारी दी जाती है।

इसी प्रकार से वैश्विक आतंकी की सूची से नाम हटाने की जानकारी से भी संबंधित देश को वंचित रखा जाता है। भारत का यह आक्रोश सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध कमेटी के दस साल बाद अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के बाद सामने आया है।

ब्रिटिश पीएम टेरीजा मे ने छोड़ा कंजरवेटिव पार्टी का अध्यक्ष पद

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे ने सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी के अध्यक्ष पद से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी रहेंगी। टेरीजा ने बेक्जिट समझौते पर संसद में कई बार विफलता हाथ लगने के बाद पिछले माह पीएम पद छोड़ने का एलान कर दिया था। अब उनके उत्तराधिकारी पर ब्रेक्जिट मामले को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। टेरीजा के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी में नए नेता के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

टेरीजा ने गत 23 मई को इस्तीफे का एलान करते हुए अपने भावुक संबोधन में कहा था, 'यह मेरे लिए हमेशा खेद का विषय रहेगा कि मैं ब्रेक्जिट प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई। अब यह मेरे उत्तराधिकारी का जिम्मा होगा कि वह इसे आगे बढ़ाएं।' टेरीजा जून, 2016 में डेविड कैमरून के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बनी थीं।

टेरीजा के इस्तीफे की घोषणा से ब्रिटेन में ब्रेक्जिट (यूरोपीय यूनियन से अलगाव) का मसला और उलझ गया है। नए प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी कि वह अलगाव की शर्तों पर सबको साथ लेकर संसद में विधेयक पारित कराएं या बिना शर्त यूरोपीय यूनियन से अलग होने की घोषणा करें। यूरोपीय यूनियन ने ब्रिटेन को अलग होने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दे रखा है।

नेता बनने की दौड़ में 11 नाम शामिल : कंजरवेटिव पार्टी का नेता बनने की दौड़ में अब तक 11 नाम सामने आ चुके हैं। इनमें पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन सबसे आगे बताए जा रहे हैं। मौजूदा विदेश मंत्री जेरेमी हंट और पर्यावरण मंत्री माइकल गोव भी इस दौड़ में शामिल हैं।

नए नेता का एलान 22 जुलाई को संभव : कंजरवेटिव पार्टी की चुनाव समिति के प्रमुख चार्ल्स वाकर ने कहा, 'हमारा मकसद है कि 20 जून के मतदान के बाद सिर्फ दो उम्मीदवार बचें। इसके बाद पार्टी के सांसद उन दोनों में से किसी को नेता चुनेंगे। उम्मीद है कि 22 जुलाई को विजेता के नाम का एलान कर दिया जाएगा।' बता दें कि यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझीदारी होती है जो संघ के सभी राष्ट्रों पर लागू होती है।

अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक बनी रहेंगी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री

सत्तारूढ़ दल में नेता चुनने की प्रक्रिया हुई शुरू

लंदन में पीएम हाउस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पद छोड़ने की घोषणा के दौरान भावुकमुद्रा में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरीजा मे। फाइल फोटो, एपी

ऐसे होगा कंजरवेटिव नेता का चुनाव

अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के लिए आठ सांसदों का समर्थन जरूरी है

नामांकन दाखिल करने के लिए दस जून को शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है

कंजरवेटिव पार्टी के सांसद कई चरणों में यानी 13, 18, 19 और 20 जून को मतदान करेंगे

पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा

न्यूज गैलरी

वर्षगांठ : भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित समारोह के दौरान पुस्तिका का विमोचन करते यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन (मध्य में) और अन्य मेहमान। प्रेट्र

स्वीडन के अपार्टमेंट में हुए धमाके में 25 घायल

स्टॉकहोम : स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से 175 किलोमीटर दूर स्थित लिंकोपिंग शहर में एक अपार्टमेंट में हुए धमाके में 25 लोग घायल हो गए। शुक्रवार तड़के हुए जबरदस्त धमाके में अपार्टमेंट की दो इमारतें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि यह आतंकी घटना है या नहीं। (एपी)

अफगान सेना ने तालिबान के कब्जे से मुक्त कराया जिला

गजनी : अफगानिस्तान की सेना ने गजनी प्रांत के एक जिले को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया है। अफगानिस्तान के कार्यकारी रक्षा मंत्री असदुल्ला खालिद ने बताया कि तालिबान ने तीन प्रांतों पर नियंत्रण करने की असफल कोशिश की थी। तालिबान ने अभी सेना के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। (एएनआइ)

कराची में आइएसआइ छाप रही दो हजार के भारतीय नोट

नई दिल्ली, आइएएनएस : नकली भारतीय नोटों की तस्करी का धंधा चलाने में पाकिस्तानी दूतावास के अफसरों की अहम भूमिका है। दो हजार रुपये के भारतीय करेंसी के नोट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ कराची में एक उच्च सुरक्षा वाले प्रिंटिंग प्रेस में छपवा रही है। और डी कंपनी इसके वितरकों में से एक है। भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे नकली नोटों का रैकेट चलाने के सिलसिले में काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अफसरों के संपर्क में हैं। दाऊद के एक गुर्गे यूनुस अंसारी को हाल ही में इसी मामले में नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली भारतीय नोटों का रैकेट वह काठमांडू के चक्रपथ क्षेत्र स्थित एक छोटे से होटल से चला रहा था। काठमांडु का यह इलाका पाकिस्तानी दूतावास के नजदीक है।

सूत्रों के मुताबिक दाऊद के गुर्गे अंसारी के भाई यूनुस और नसीम का काठमांडु स्थित पाकिस्तानी दूतावास में नियमित रूप से आना-जाना है। बताया जाता है कि यह गुर्गे पाकिस्तान के डिफेंस अटैची के लगातार संपर्क में हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों की टिप पर ही काठमांडू पुलिस के एक विशेष दस्ते ने विगत 24 मई को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यूनुस अंसारी और तीन पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। कराची से उड़ान भरने वाले यूनुस के पासपोर्ट पर कतर के स्टैंप लगे हैं। उसके साथ चार सूटकेस भी बरामद किए गए जिसमें 7.67 करोड़ रुपये की नकली भारतीय करेंसी भरी हुई थी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, नकली नोटों की एक बड़ी खेप समुद्र के रास्ते तस्करी करके बांग्लादेश पहुंचाई गई है। पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने सीमावर्ती पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक कई छापेमारी की हैं। खुफिया एजेंसी आइबी के सूत्रों के अनुसार, हाल में जब्त किए गए नकली नोटों की क्वॉलिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर यूवी काउंटरफीट डिटेक्शन मशीन से इन नोटों की पहचान नहीं की गई तो यह बाजार में जगह बना सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यूनुस अंसारी को तो फिलहाल पुलिस ने जेल में डाल दिया है। लेकिन बिहार से लगे नेपाल के तराई क्षेत्र स्थित बीरगंज का एक स्थानीय नेता बसरुद्दीन अंसारी भी डी कंपनी के संपर्क में है। वह दाऊद के पैसे से खोला एक निजी संस्थान नेशनल मेडिकल कॉलेज भी चलाता है। इसके बदले में डी-कंपनी उसके कुछ सुरक्षित ठिकानों को इस्तेमाल करती है। यही ठिकाने भारत में तस्करी करके नकली नोट ले आने के लिए उनके 'ट्रांजिट प्वाइंट' हैं।

डी कंपनी और पाकिस्तान दूतावास मिलकर चला रहे नकली नोटों का धंधा

एनआइए ने पश्चिम बंगाल से लेकर गुरुग्राम तक में की छापेमारी

यूनुस अंसारी (मध्य में)। फाइल

पेरिस का मशहूर व्हाइट ड्रेस डिनर

पेरिस के ट्यूलरीज गार्डन में आयोजित 'डिनर एन ब्लैंक' (डिनर इन व्हाइट) में दावत का आनंद उठाते लोग। इस डिनर की खासियत है कि इसमें सभी आमंत्रित लोग व्हाइट ड्रेस शामिल होते हैं। मेजपोश, तौलिया और डिनर सेट भी व्हाइट कलर के होते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोगों और स्थल का चयन ऑनलाइन किया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में फ्रेंचमान फ्रांस्वा पसक्वियर की एक दावत से हुई थी। फ्रांस्वा ने दावत के लिए जिन दोस्तों को आमंत्रित किया था, उनसे सफेद ड्रेस पहनकर आने का अनुरोध किया गया था। तब उन्हें पता भी नहीं होगा कि आगे चलकर यह इवेंट दुनिया में इतना लोकप्रिय हो जाएगा। एएफपी

बोरिस के लिए पीएम मे की जगह लेने की रुकावट हुई दूर

लंदन, एएफपी : ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन के लिए प्रधानमंत्री टेरीजा मे की जगह लेने के रास्ते की बड़ी रुकावट दूर हो गई है। लंदन हाई कोर्ट ने निचली अदालत से उनके खिलाफ जारी समन को रद कर दिया है। जॉनसन पर ब्रेक्जिट को लेकर गलतबयानी का आरोप था।

जॉनसन के खिलाफ 29 साल के एक कारोबारी ने याचिका दायर की थी। उनके वकील एड्रियन डर्बीशायर की दलील थी कि निजी अभियोजन राजनीति से प्रेरित है और कानून में इस तरह की परंपरा नहीं रही है। हाई कोर्ट के दो जजों के पैनल ने कहा कि वो उनके मामले से सहमत है। ब्रेक्जिट पर मे ने पद से इस्तीफा दे दिया है और जॉनसन को प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है।

ब्रेक्जिट के लिए 2016 में जब ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था, तब जॉनसन विदेश मंत्री के साथ ही लंदन के मेयर भी थे। ब्रेक्जिट के पक्ष में लोगों से उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटेन अलग हो जाता है तो उसे यूरोपीय संघ को हर हफ्ते 44.5 करोड डॉलर (लगभग 3.5 हजार करोड़ रुपये) नहीं चुकाने पड़ेंगे।

'साजिश के तहत किए गए थे तेल टैंकरों पर हमले'

न्यूयॉर्क, एएनआइ : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के जलक्षेत्र में पिछले महीने चार तेल टैंकरों पर हमले साजिश के तहत किए गए थे। हमले से प्रभावित देश यूएई, नॉर्वे और सऊदी अरब ने यहां संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में यह बात कही है। गत 12 मई को यूएई के फुजैरा बंदरगाह से कुछ दूर समुद्र में खड़े चार तैल टैंकरों पर हमले किए गए थे। इसमें दो टैंकर सऊदी अरब के थे। अमेरिका ने इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ होने की आशंका जताई थी। तीनों देशों ने गुरुवार को यहां एक संयुक्त विज्ञप्ति में कहा कि इन हमलों को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था, जिससे पता चलता है कि इसके पीछे किसी देश का हाथ है। हालांकि विज्ञप्ति में हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का जिक्र नहीं किया गया है। यूएन में यूएई के दूत लाना नुसेइबे ने कहा कि हमारे देश ने हमलों के पीछे ईरान के होने का जिक्र नहीं किया है। लेकिन सऊदी अरब के दूत अब्दल्ला अल-मौलिमी ने कहा कि हमले ईरान ने करवाए थे।

खुला रास्ता

एपल आइफोन के एप-स्टोर पर इन एप्स के लिए फिर से रास्ता खुल गया है, जांच के डर से दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ने लिया फैसला

पेरेंटल कंट्रोल एप को लेकर बदली नीति

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एपल ने बीते साल आइफोन के एप-स्टोर से कई पेरेंटल कंट्रोल एप हटा दिए थे। इन एप्स की मदद से मां-बाप यह तय कर सकते थे कि उनका बच्चा कितने समय तक फोन इस्तेमाल करेगा। इन एप्स को हटाने के बाद एपल पर अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था।

इस सप्ताह प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में न्यायिक विभाग एपल और अन्य टेक कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर सकता है। इसी रिपोर्ट के मद्देनजर एपल ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए पेरेंटल कंट्रोल एप्स के लिए फिर रास्ता खोल दिया है। माना जा रहा है कि अपने ऊपर जांच के डर से एपल ने यह कदम उठाया है।

एप-स्टोर को नियंत्रित करने का लगा आरोप : कई एप्स ने एपल पर अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर एप-स्टोर को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। स्पॉटीफाई के साथ दो अन्य पेरेंटल

कंट्रोल एप ने प्रतिस्पर्धा खत्म करने को लेकर एपल के खिलाफ यूरोपीय नियामक के पास शिकायत दर्ज कराई है। नीदरलैंड्स के नियामक इस मामले में एपल की जांच कर रहे हैं।

बच्चों की निजी जानकारियां एक्सिस करने के आरोप में हटाए थे एप : कई सारे पेरेंटल कंट्रोल एप मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (एमडीएम) और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एमडीएम के जरिये अभिभावक बच्चों का फोन नियंत्रित कर सकते हैं और वीपीएन की मदद से बच्चों के फोन पर मौजूद कुछ एप को बंद किया जा सकता है। एपल का कहना है कि इन तकनीक की मदद से ये एप बच्चों की निजी जानकारियां जुटा सकते हैं। इसी कारण उसने बीते अगस्त में फ्रीडम नामक एप बंद कर दिया था। एप ने हालांकि यूजर की कोई भी जानकारी इकट्ठा करने से इन्कार किया था।

अब एमडीएम और वीपीएन के इस्तेमाल की दे दी मंजूरी : एपल ने अब अपनी नीति को अचानक बदलते हुए इन दोनों तकनीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। उसने हालांकि इसकी एक शर्त रखी है। इसके अनुसार एप डेवलपर यूजर की उन निजी जानकारियों को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचेंगे और ना ही खुद उसका इस्तेमाल करेंगे।

आइफोन के एप-स्टोर से अब पेरेंटल कंट्रोल एप फिर खोजे जा सकेंगे। इनकी मदद से अभिभावक यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि उनके बच्चे कितनी देर तक फोन का इस्तेमाल करें। इसका एक फायदा यह भी है कि ऐसा करने से अभिभावक अपने बच्चे का शैक्षिण स्तर सुधार सकते हैं और उसकी पूरी निगरानी भी कर सकते हैं।

अमेरिकी सेना में सिख अफसर को पगड़ी पहनने की इजाजत

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी वायुसेना ने सिख अफसर हरप्रीतिंदर सिंह बाजवा को ड्यूटी के दौरान पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की इजाजत दे दी है। बाजवा पहले सिख अफसर हैं, जिन्हें अमेरिकी वायुसेना ने ड्यूटी के दौरान धार्मिक पहनावे और मान्यताओं का पालन करने की इजाजत दी है।

अमेरिका में ही जन्मे बाजवा ने 2017 में वायुसेना ज्वाइन की थी। उन्हें मैककॉर्ड एयरफोर्स बेस पर क्रू चीफ के पद पर तैनाती मिली थी। लेकिन वायुसेना के ड्रेस कोड के चलते वह अपनी मान्यताओं का पालन नहीं कर पा रहे थे। बाजवा ने कहा, 'मुझे इस बात से काफी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने धर्म का पालन करने के साथ ही देश की सेवा भी कर सकता हूं। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे देश ने मेरी सिख परंपरा को सम्मानित किया है।' वायुसेना ने बाजवा को यह छूट सिख अमेरिकन वेटरंस एलांयस और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) से मिले आग्रह के बाद दी है।

ब्रिटिश विदेश विभाग के बोर्ड में पहली बार भारतवंशी को जगह

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन की सरकार ने भारतवंशी कुमार अय्यर को फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस (एफसीओ) का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। अय्यर एफसीओ के प्रबंधक बोर्ड में शामिल होने वाले पहले भारतवंशी हैं। उनका कार्यकाल जुलाई में शुरू होगा। लंदन में जन्मे अय्यर 2013 में भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे थे। उनके जीवन के शुरुआती साल भारत में बीते थे। 11 साल की उम्र में वह ब्रिटेन लौट गए थे।

मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर वह एफसीओ की इकोनॉमिक यूनिट का नेतृत्व करेंगे। उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए विदेश विभाग के स्थायी अवर-सचिव साइमन मैकडोनाल्ड ने कहा, 'कुमार एफसीओ के बोर्ड मेंबर बनने वाले पहले गैर श्वेत हैं। उनकी नियुक्ति विदेश विभाग में विविधता का प्रतीक है। उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था की गहरी समझ है जिससे एफसीओ को फायदा होगा।' कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री पूरी करने वाले अय्यर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंस और मैक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा चुके हैं। फिलहाल वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजिटिंग शिक्षाविद हैं।

कुमार अय्यर। फाइल

कुमार ने ब्रिटिश सरकार के कोषागार विभाग में भी अपनी सेवाएं दी हैं। 2007 से 2010 के बीच वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी यूनिट के उपाध्यक्ष रहे थे। एफसीओ में जगह मिलने पर उन्होंने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एफसीओ के मुख्य अर्थशास्त्री बनने का मौका मिलेगा। मैं इसको लेकर बहुत उत्साहित हूं।'

ये भी जानिए

1992 विश्व कप में भी पाकिस्तान का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ बारिश के कारण रद हुआ था। तब पाकिस्तान 74 रन पर ढेर हो गई थी।

नेविल मैदान के पास रहने वाले रिचर्ड्स • जागरण

यहीं से खिले थे भारतीय क्रिकेट के फूल

- नेविल क्रिकेट मैदान पर 1983 के विश्व कप में कपिल की जिंबाब्वे के खिलाफ 175 रनों की पारी से बदल गया था भारतीय क्रिकेट
- यह इस मैदान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय मैच था, लेकिन यहां पर नहीं लगी है पूर्व भारतीय कप्तान कपिल की फोटो

अभिषेक त्रिपाठी • लंदन

आज अगर भारत में क्रिकेट इतने ऊंचे पायदान पर है तो उसकी एकमात्र वजह कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया का लॉर्ड्स के मैदान में 1983 विश्व कप ट्रॉफी उठाना है, लेकिन भारत को यह ट्रॉफी सिर्फ इसलिए मिली, क्योंकि तत्कालीन कप्तान कपिल देव ने नेविल क्रिकेट मैदान में 18 जून 1983 को खेले गए लीग मैच में जिंबाब्वे के खिलाफ 175 रनों की पारी खेलकर हमें जीत दिलाई थी। उस मैच में भारत ने नौ रन पर चार विकेट गंवा दिए थे और इसके बाद कपिल बल्लेबाजी करने उतरे। 17 रन के कुल योग पर यशपाल शर्मा के रूप में भारत का पांचवां विकेट गिरा, लेकिन कपिल डटे रहे और उनकी 138 गेंदों की नाबाद पारी की वजह से भारत 60 ओवर में आठ विकेट पर 266 रन बनाने में सफल रहा। कपिल ने इस पारी के दौरान 16 चौके व छह छक्के लगाए और इसी के साथ नेविल क्रिकेट मैदान क्रिकेट जगत में अमर हो गया। भारत ने यह मैच 31 रन से जीता और यहीं से टीम इंडिया की क्रिकेट की महाशक्ति बनने की शुरुआत हो गई।

टीम इंडिया अगर यह मैच हार जाती तो विश्व कप के अगले दौर में पहुंचना मुश्किल हो जाता, लेकिन कपिल ने नेविल क्रिकेट मैदान में उस समय की वनडे की सबसे बड़ी पारी खेलकर खुद का और इस मैदान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। हालांकि, विश्व कप के प्रसारक बीबीसी की हड़ताल होने के कारण इस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लगभग 4000 लोगों के अलावा कपिल की पारी को कोई नहीं देख पाया।

ऐसा है नेविल क्रिकेट मैदान : उस मैच की रिकॉर्डिंग नहीं होने के कारण आप कपिल की उस पारी को चाहकर भी नहीं देख सकते हैं। विराट सेना उसी इंग्लैंड में इस समय विश्व कप खेल रही है।

नेविल क्रिकेट मैदान का पवेलियन • जागरण

जब हम साउथैंप्टन में टीम इंडिया की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद गुरुवार को लंदन पहुंचे तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात कौंध रही थी कि जिस वजह से आज हम लोग यहां हैं, उस पारी को तो नहीं देख सकते, लेकिन उस मैदान, उस जगह को देखना चाहिए और उसके बाद मैंने उस नेविल मैदान में जाने का फैसला किया। टीम इंडिया को रविवार को अगला मुकाबला ओवल मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है और शुक्रवार को उसे अभ्यास करना था, लेकिन बारिश के कारण अभ्यास रद हो गया। इसके बाद मैं नेविल मैदान के लिए निकल गया। लंदन के ओवल ट्यूब (मेट्रो) स्टेशन से ट्यूब पकड़कर चारिंग क्रॉस रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहां से ट्रेन लेकर टनब्रिज वेल्स स्टेशन उतरा। वहां से टैक्सी लेकर काउंटी टीम वेल्स के मैदान नेविल पहुंचा।

छोटे से मैदान पर पड़ा कीर्तिमान : छोटे से कस्बे में बने इस मैदान के गेट पर ना ही कोई सुरक्षाकर्मी था और ना ही दफ्तर में कोई कर्मचारी। मैदान की बाउंड्री 60 से 65 मीटर की होगी। 10 कदम चलते ही मैदान दिखाई दिया और उसे देखते ही मन को आत्मिक सुकून भी मिला। आज भी वह मैदान वैसा ही है। बारिश के कारण पिच ढकी हुई थी और नीले और बैंगनी रंग के रॉडोडेनड्रॉन फूल दूर से आकर्षित कर रहे थे। यह फूल इसी क्रिकेट मैदान में पाए जाते हैं। मैदान चारों तरफ से बड़े-बड़े पेड़ों और रॉडोडेनड्रॉन फूलों से घिरा हुआ है। यहां बैठने के लिए दो स्टैंड हैं, जिसमें एक में वही पुराने जमाने का ड्रेसिंग रूम और एक छोटा सा पब है। ब्लूमेंटल स्टैंड में 412 सीट हैं, जबकि उसके बगल में बने छोटे से पवेलियन के नीचे 124 लोगों के बैठने की जगह है। मैच के समय मैदान के आसपास अस्थायी सीटें लगाई जाती हैं जिससे यहां करीब 6000 लोग मैच देख सकते हैं।

मैंने देखा था वह मैच : स्टेडियम के पास में ही रहने वाले स्टीव निकर ने कहा कि मैंने वह मैच देखा था। करीब 4000 दर्शक उस मैच में मौजूद थे। यह इस मैदान का पहला और आखिरी वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच था। बादल होने के कारण गेंद स्विंग हो रही थी और यही कारण था कि गावस्कर समेत भारत के चार बल्लेबाज पवेलियन में जल्दी पहुंच गए। सबको लग रहा था कि यह मैच जिंबाब्वे जीत जाएगा, लेकिन कपिल ने वह कर दिखाया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दिन बहुत हवा चल रही थी और कपिल हवा के खिलाफ ऑफ साइड में चौके-छक्के लगा रहे थे। अगर उस पारी की तुलना किसी से की जाए तो सिर्फ इयान बॉथम की 1981 की पारी याद आती है, जब उन्होंने फॉलोऑन के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था।

मेरे घर की छत पर गया था कपिल का छक्का : नेविल क्रिकेट मैदान से सटी हुई सड़क है और उसके दूसरी तरफ जेफ्री रिचर्ड्स का घर है। जब मैं बारिश में भीगते हुए उस मैदान का मुजाहिरा कर रहा था तभी रिचर्ड्स अपने कुत्ते के साथ टहलते हुए मैदान में आ गए। क्रिकेट के शौकीन रिचर्ड्स ने बताया कि 1983 विश्व कप के समय मैं यहां नहीं था। मैं यहां बाद में रहने आया, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि कपिल ने एक ऐसा छक्का लगाया कि गेंद उस मकान में जाकर गिरी जिसमें मैं अब रहता हूं। वाकई में वह 100 मीटर से लंबा छक्का होगा।

बीसीसीआइ के निवेदन को आइसीसी ने सिरे से किया खारिज, विश्व कप के बाकी मैचों में भारतीय विकेटकीपर नहीं पहन सकेंगे सेना का बलिदान बैज

आइसीसी को रास नहीं आया दस्तानों पर 'धौनी का बलिदान'

विश्व कप में दैनिक जागरण

अभिषेक त्रिपाठी • लंदन

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साउथैंप्टन में विश्व कप के पहले मैच में पैरा स्पेशल फोर्स के बलिदान बैज वाले दस्ताने पहनकर उतरने देने के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के निवेदन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसे में पूर्व भारतीय कप्तान धौनी अब विश्व कप के आने वाले मुकाबलों में इस बैज को पहनकर नहीं उतर सकेंगे।

आइसीसी ने शुक्रवार को बीसीसीआइ को जवाब में कहा कि एमएस धौनी पिछले मैच में जिस बैज को पहनकर खेले थे उसको आइसीसी विश्व कप के अन्य मुकाबलों में पहनकर खेलने की इजाजत नहीं देती है। आइसीसी टूर्नामेंट के नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, जिसमें कोई व्यक्तिगत संदेश या लोगो खेलने के कपड़ों या साधनों पर लगाकर खेले। इसी के साथ यह विकेटकीपर के दस्तानों पर लागू नियम के खिलाफ भी है। नियम के मुताबिक विकेटकीपिंग के प्रत्येक दस्ताने पर बनाने वाली कंपनी के दो लोगो लगाने की इजाजत है। जिनमें से एक 38.71 सेंटीमीटर तो दूसरा 12.9 सेंटीमीटर का हो सकता है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित बीसीसीआइ की प्रशासकों की समिति (सीओए) के मुखिया विनोद राय ने कहा था कि धौनी अपने विकेटकीपिंग दस्ताने पर बलिदान बैज लगाना जारी रखेंगे, क्योंकि यह सेना का चिन्ह नहीं है। हमने इस मामले में आइसीसी से अपील करते हुए कहा कि वे धौनी को उनके दस्तानों पर बने इस बैज को लगाने की अनुमति दें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिषद ने भारतीय बोर्ड की इस अपील को ठुकरा दिया है। बता दें कि आइसीसी ने बीसीसीआइ से कहा था कि वह धौनी के दस्तानों पर से यह चिन्ह हटवाएं। बीसीसीआइ ने आइसीसी से इस बैज को लगे रहने के लिए निवेदन किया था।

आइसीसी के नियमों के मुताबिक खिलाड़ी किसी वित्तीय, धार्मिक या सेना के लोगो को नहीं लगा सकता है। ऐसे में धौनी का बैज को पहनना आइसीसी के वित्तीय या धार्मिक नियम को नहीं तोड़ता है। साथ ही यह भारतीय पैरा स्पेशल फोर्स का प्रतीक चिन्ह भी नहीं है। ऐसे में धौनी ने कहीं भी नियम को नहीं तोड़ा है। उधर, आइसीसी के मुताबिक खिलाड़ी राजनीति, धर्म या नक्सलवाद से जुड़े किसी भी गतिविधि का प्रचार नहीं कर सकता है। उधर, आइसीसी के एक अधिकारी ने कहा था कि हमारी क्रिकेट ऑपरेशन टीम इस मामले पर विश्व कप आयोजन समिति की तकनीकी समिति के प्रमुख ज्योफ एलार्डयेस से बात करेगी। हालांकि बीसीसीआइ तकनीकी समिति के सामने यह साबित नहीं कर पाया कि यह सेना का चिन्ह नहीं है। धौनी भारतीय पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स पैराशूट रेजीमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और यह चिन्ह इस रेजीमेंट का हिस्सा है।

वहीं सीओए प्रमुख ने कहा था कि पैरा रेजीमेंट के लोगो में बलिदान शब्द अंकित है, लेकिन धौनी के केस में उनके दस्तानों पर लगे बैज पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हालांकि आइसीसी बीसीसीआइ के इस तर्क से सहमत नहीं रहा और अपने नियम पर कायम रहा। सीओए को उस वक्त इस मामले में सतर्क होना पड़ा था, जब राय से यह पूछा गया कि आइसीसी ने अगर इस बैज को हटाने का आदेश दिया और धौनी पर नियम तोड़ने पर कोई प्रतिबंध लगाया तब भारत कैसे जवाब देगा। तो राय ने कहा था कि मुझे लगता है कि आइसीसी ने इस बैज को हटाने के लिए निवेदन किया है। कोई हिदायत नहीं दी है। सीओए ने अब तक धौनी से कोई बात नहीं की है। वहीं सीओए की सदस्य डायना इडुल्जी भी धौनी का समर्थन करती दिखीं थी। उन्होंने कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है। हमने टीम से कोई बात नहीं की है, लेकिन हम धौनी का बचाव करेंगे। अगर कोई और क्रिकेटर भी होता तो हम ऐसा ही करते।

इस मामले में बीसीसीआइ के सीईओ राहुल जौहरी के ऑस्ट्रेलिया से होने वाले मुकाबले से पहले वहां जाने की बात सामने आई थी। बोर्ड के एक अधिकारी ने पहले ही इस मामले में धौनी की मुश्किल की ओर इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की राह मुश्किल है क्योंकि इसमें एक और पेंच है। आइसीसी के नियम के अनुसार उसके टूर्नामेंट में विकेटकीपर के दस्ताने में उत्पादक के दो लोगो (एक छोटा और एक बड़ा) हो सकते हैं। धौनी के दस्ताने में एसजी के साथ यह बलिदान बैज का लोगो भी है। अगर बलिदान बैज पर आइसीसी को समझा भी दिया जाता है तब भी धौनी दस्तानों पर दो चिन्ह नहीं रख सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धौनी ने विकेटकीपिंग के समय यह दस्ताने पहने थे • ट्विटर

"यह मामला देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। मैं बीसीसीआइ से आग्रह करता हूं कि महेंद्र सिंह धौनी के मामले में साफ कदम उठाए। –**किरण रिजिजू**, खेल मंत्री

"जब हम मैदान पर होते हैं तो हम खुद को अपने देश के लिए समर्पित कर देते हैं और हम अपना सर्वस्व भारत का मान बढ़ाने के लिए दे देते हैं। हम सब अपने देश से प्यार करते हैं और एमएस धौनी ने भी हमारे नायकों के बलिदान को सैल्यूट कर और सम्मान कर यही किया। इसे देशभक्ति मानना चाहिए, ना कि राष्ट्रवाद।

सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेटर

एमएस धौनी को 2011 में सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी थी। उन्हें पूरा हक है कि वह बलिदान बैच को पहने। मेरा आइसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर और सीओए सदस्य रवि थोडगे से अनुरोध है कि देश की और भारतीय सेना की भावनाओं का सम्मान करें। मुझे उम्मीद है कि आप धौनी को यह बैच पहनने की इजाजत देंगे।

आदित्य वर्मा, सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार"

धौनी की जिंदगी के करीब यह बैज

धौनी के जिस बैज को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वह उनकी जिंदगी के बेहद करीब है। यह तो सभी जानते हैं कि धौनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। उनका सेना से प्रेम भी किसी से छुपा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली घरेलू सीरीज में धौनी ने रांची में पुलवामा आतंकवादी हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी टीम को सेना की कैप पहनाई थी। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जिसमें धौनी के फोन के कवर पर भी यह बलिदान बैज मौजूद है, जो धौनी के सेना से प्रेम को साफ जाहिर कर रहा है।

धौनी का फोन, जिसके कवर पर बलिदान बैज साफ देखा जा सकता है • ट्विटर

एक बार फिर निगाहें होंगी महेंद्र सिंह धौनी पर

अभिषेक त्रिपाठी • लंदन

मिशन विश्व कप

- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में सबकी निगाहें माही पर होंगी
- विवाद ने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा

भारत ने साउथैंप्टन में जब दक्षिण अफ्रीका को हराया तो सबका ध्यान इस बात पर था कि टीम लंदन के ओवल स्टेडियम की पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में क्या करेगी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धौनी को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद सबकी नजरें पूर्व भारतीय कप्तान पर टिक गई हैं। भारत को रविवार को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है और यहां पर सब यह देखना चाहेंगे कि धौनी उस बैज के साथ उतरेंगे या नहीं और वह अपने बल्ले से कैसे जवाब देंगे।

अगर धौनी के विवाद को छोड़कर अगले मैच की बात करें तो शुक्रवार को यहां बारिश हुई और शनिवार को भी हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन पिच की नमी और बादल छाए रहने के कारण एक बार फिर ओवल में शुरुआत में तेज गेंदबाजों का जलवा देखने को मिल सकता है। इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अफगानिस्तान को बुरी तरह हराने के बाद वेस्टइंडीज को भी मात देकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। माना जा रहा कि लगातार दो जीत के बाद ओवल में भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम कड़ी चुनौती पेश करेगी।

ऑस्ट्रेलिया से है नाता : पिछले साल धौनी को जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 टीम में नहीं रखा गया था तो लोगों को लगा कि इस पूर्व भारतीय कप्तान का समय अब खत्म हो गया है और कई लोगों ने उनके 2019 विश्व कप में नहीं खेलने की भविष्यवाणी भी कर दी थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन्हें इस साल 12 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन वनडे की सीरीज में वापसी कराई। उसके बाद से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। धौनी विश्व कप के अभ्यास मैच में भी शतक लगा चुके हैं और यह उनका आखिरी विश्व कप है। ऐसे में वह अपने बल्ले से कठोर जवाब देकर इस महाकुंभ से विदाई चाहेंगे। वह विश्व कप में भारत की योजना का अहम हिस्सा हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही लिया था टेस्ट से संन्यास : भारतीय टीम के पूर्व कप्तान धौनी ने ऑस्ट्रेलिया में ही 2014 में टेस्ट से संन्यास लिया था। पिछले साल इसी टीम के खिलाफ टी-20 टीम में उनको शामिल नहीं करने पर सवाल उठे थे। हालांकि चयनकर्ताओं ने कहा था कि धौनी खुद टी-20 टीम में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वह अगले टी-20 विश्व कप की योजना का हिस्सा नहीं हैं, ऐसे में वह चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया में टी-20 टीम में नए विकेटकीपर को मौका मिले। बीसीसीआइ के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह यह तय है कि ऑस्ट्रेलिया में 2020 में होने वाले टी-20 विश्व कप में धौनी नहीं खेलेंगे।

धौनी को चुनौती देने का इंतजार : कैरी

एलेक्स कैरी फाइल फोटो, एपी

लंदन : अपने पहले विश्व कप में खेल रहे ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने कहा कि वह अब भारत विशेषकर धौनी को चुनौती देने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन दोनों टीमों के बीच लंदन में रविवार को मुकाबला होगा। कैरी के 55 गेंदों पर 45 रन और नाथन कूल्टर नाइल की 92 रन की पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को वेस्टइंडीज को 15 रन से हराया। इस पारी से उन पर पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलने को लेकर बना दबाव भी कम हो गया है। कैरी ने कहा, 'भारत और ऑस्ट्रेलिया में उनके (धौनी) खिलाफ खेलते हुए मैंने पाया कि वह बेहद शांतचित हैं। वह हमेशा मैच के सकारात्मक अंत का खुद को मौका देते हैं। वह क्रीज पर पर्याप्त समय बिताते हैं। वह शांत स्वभाव रखते हैं और खुद को पारी के अंत तक टिके रहने का अवसर देते हैं।'

धौनी में बहुत कमजोरियां नहीं : हसी

लंदन : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी को लगता है कि महेंद्र सिंह धौनी की बहुत ज्यादा कमजोरियां नहीं हैं और अगर हैं भी तो चेन्नई सुपरकिंग्स के बल्लेबाजी कोच होने के नाते वह उसे साझा नहीं करेंगे।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हसी धौनी की कप्तानी वाली आइपीएल टीम सीएसके से जुड़े हैं। जब हसी से पूछा गया कि क्या वह ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ धौनी को लेकर कुछ साझा करेंगे। इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'कोई संभावना नहीं है, वैसे भी धौनी की ज्यादा कमजोरी नहीं है।' उन्होंने कहा, 'आज के दौर में सभी टीमें सभी खिलाड़ियों पर बहुत बारीकी से विश्लेषण करती हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि उनके पास धौनी और सभी भारतीय खिलाड़ियों के लिए योजना होगी। धौनी महान खिलाड़ी हैं और दबाव की स्थिति में किसी दूसरे खिलाड़ी से बेहतर रहते हैं। वह काफी चतुर खिलाड़ी हैं और जोखिम का आकलन करते रहते हैं। उन्हें अपनी ताकत के बारे में पता है और वह उसी तरीके से खेलते हैं। धौनी ना सिर्फ खेल की स्थिति के अनुसार खेलते हैं, बल्कि पारी की

माइकल हसी, फाइल फोटो, ट्विटर

शुरुआत में खुद को कुछ समय देना पसंद करते हैं। उनको पारी की आखिरी हिस्से में ज्यादा जिम्मेदारी लेना पसंद है।' हसी को लगता है कि धौनी की मौजूदगी और खेल को आखिरी तक ले जाने की क्षमता से विरोधी टीम चैन की सांस नहीं ले पाती है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि धौनी को पैट कमिंस, कैगिसो रबादा और जोफ्रा आर्चर (आइपीएल में) जैसे बेहतर तेज गेंदबाजों के खिलाफ शॉट खेलने में दिक्कत हुई है। हसी ने कहा, 'धौनी को पता रहता है कि किस गेंदबाज से खतरा होगा और टीम को किसके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए। आपने जिन गेंदबाजों का जिक्र किया है वे केवल एक छोर से गेंदबाजी कर सकते हैं।'

भारतीय टीम में नाजुकपन : एलेन बॉर्डर

लंदन, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलेन बॉर्डर ने कहा है कि भारतीय टीम में कुछ नाजुकपन है, बावजूद इसके यह टीम आरोन फिंच की कप्तानी वाली टीम के सामने बड़ी चुनौती साबित होगी। भारत ने आइसीसी विश्व कप की बेहतरीन शुरुआत की थी और दक्षिण अफ्रीका को हराया था। बॉर्डर ने कहा कि मुझे लगता है कि वह उस दिन जेल से बाहर आए थे। द. अफ्रीका ने शानदार खेल खेला लेकिन वह ज्यादा रन नहीं बना सकी और इसके बाद रोहित शर्मा ने भारत के लिए अपना काम किया। बॉर्डर ने कहा कि भारत में कुछ नाजुकपन है लेकिन उनके पास रोहित, विराट जैसे खिलाड़ी हैं।

बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच मुकाबला आज

कार्डिफ, एएफपी : इंग्लैंड की टीम शनिवार को जब यहां बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप का अगला मैच खेलेगी तो वह चार साल पुरानी कड़वी यादों को ध्यान में रखकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने से बचना चाहेगी।

बांग्लादेश ने विश्व कप 2015 में एडिलेड में इंग्लैंड को 15 रन से हराकर उसे टूर्नामेंट के पहले दौर से बाहर कर दिया था। इंग्लैंड उस हार को भूला नहीं होगा, हालांकि तब उसकी टीम आज की तुलना में कमजोर थी। इसके बाद इंग्लैंड के टीम प्रबंधन में बदलाव हुए और उसने लगातार सुधार किया और आज वह दुनिया की नंबर एक टीम है। लेकिन, अपनी सरजमीं पर खेले जा रहे विश्व कप में इंग्लैंड का अभियान अभी तक उतार-चढ़ाव वाला रहा है। उसने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 104 रन से हराया, लेकिन अगले मैच में पाकिस्तान से 14 रन से हार गया। बांग्लादेश की सोफिया गार्डेंस से कुछ अच्छी यादें जुड़ी हैं। उसने इसी मैदान पर 2005 में ऑस्ट्रेलिया को हराया था जिसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े उलटफेर में से एक माना जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में बांग्लादेश ने जिस तरह से 245 रन का स्कोर बचाने के लिए अपनी जी-जान लगा दी थी उससे भी मुर्तजा और साथियों के हौसले बुलंद हैं। न्यूजीलैंड ने आखिर में यह मैच दो विकेट से जीता था।

विराट के कभी हार नहीं मानने के जज्बे की परीक्षा

के श्रीकांत

कलम से

विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली के कभी हार नहीं मानने के जज्बे की कड़ी परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वैसी लय हासिल कर ली है, जिसके लिए यह टीम जानी जाती है। यानी कि नाउम्मीदी भरे हालात से वापसी कर मैच जीतने की कला।

ऑस्ट्रेलिया की किसी टीम में ऐसा जज्बा पहली बार मैंने 1987 के विश्व कप में देखा था। तब खेल को लेकर उनका नजरिया 1983 के विश्व कप से बिलकुल अलग था। भारत के खिलाफ उनका पहला और इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला इसका जीता जागता उदाहरण है। उस विश्व कप के इन दो मुकाबलों में कोई भी दूसरी टीम होती तो हार मान लेती। मगर एलन बॉर्डर की टीम ने ऐसा नहीं किया। यह टीम किसी भी हालात में हार नहीं मानती और यही वजह है कि इसने पिछले आठ में से पांच विश्व कप जीते हैं। आक्रामक क्रिकेट खेलना और बड़े अंतर से जीत हासिल करना, किसी भी टॉप टीम के खेल का हिस्सा होता है। अब बात रविवार को होने वाले भारत-ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की करते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में हमने देखा कि फिंच एंड कंपनी को हराया जा सकता है। टीम को भाग्य का भी साथ मिला और नाथन कूल्टर नाइल ने फिल्मी अंदाज में उन्हें मुकाबले में ला खड़ा किया। कई मामलों में इस मुकाबले से यह भी तय हो जाएगा कि किस टीम की सेमीफाइनल की राह आसान होने वाली है। यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका में दो अंक जोड़ने भर का नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई टीम हमेशा से विपक्षी टीम के कप्तान को निशाना बनाती है और ऐसे में काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कोहली हालात का सामना कैसे करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी विभाग फिलहाल मिचेल स्टार्क पर निर्भर नजर आ रहा है। (टीसीएम)

अफगानिस्तान के सामने कीवी चुनौती

टांटन, एएफपी : पिछले मैच में बांग्लादेश के स्पिनरों के सामने कुछ विषम पलों से गुजरने वाले न्यूजीलैंड को शनिवार को यहां विश्व कप के अपने अगले मैच में अफगानिस्तान की इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

न्यूजीलैंड ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं और वह विजय अभियान जारी रखना चाहेगा, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अपेक्षाकृत छोटे लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। रॉस टेलर के 82 रन की मदद से कीवी टीम ने यह मैच दो विकेट से जीता था। इससे पहले उसने श्रीलंका को आसानी से 10 विकेट से हराया था। टेलर ने भी माना कि एशियाई टीमों के खिलाफ स्पिन का अच्छी तरह से सामना करना जीत के लिए अहम है।

न्यूजीलैंड गेंदबाजी में अपने तेज गेंदबाजों पर निर्भर है। मैट हेनरी अब तक दो मैच में सात विकेट ले चुके हैं तथा ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन ने उनका अच्छा साथ दिया है। बल्लेबाजी में टीम कप्तान केन विलियमसन और टेलर पर काफी निर्भर है।

अफगानिस्तान ने अब तक अपने दोनों मैच गंवाए हैं, लेकिन दोनों में उसने कड़ी चुनौती पेश की। राशिद खान को मुहम्मद नबी के साथ मिलकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। नबी ने श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में 30 रन देकर चार विकेट लिए थे।

पाक खिलाड़ियों की अनोखी मांग, पीसीबी का इन्कार

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : आइसीसी विश्व कप 2019 में पाकिस्तानी खिलाड़ी 16 जून को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में विकेट मिलने के बाद अलग तरह का जश्न मानना चाहते थे। उनकी इस ख्वाहिश को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नकार दिया है।

पाकिस्तान की वेबसाइट पाक पैशन के संपादक साज सादिक ने ट्वीट किया कि पीसीबी ने सरफराज अहमद और उनकी टीम की उस अपील को नामंजूर कर दिया है जिसमें वह भारत के खिलाफ होने वाले मैच में विकेट मिलने के बाद अलग तरह का जश्न मानाने की मांग कर रहे थे। टीम की यह मांग भारतीय टीम द्वारा मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में सेना की कैप पहनने के प्रतिकार के रूप में की गई थी। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी। उन्हीं को नमन करने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में सेना जैसी कैप पहनी थी। सादिक ने ट्वीट किया कि रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों से कहा कि वह क्रिकेट पर ध्यान दें। उन्होंने साथ ही पीसीबी चेयरमैन अहसान मनी का जबाव भी लिखा है जिसमें अहसान ने कहा कि हम वो नहीं कर सकते जो अन्य टीमें करती हैं। कई तरह से जश्न मनाया जा सकता है जैसा कि मिस्बाह उल हक ने लॉर्ड्स में मनाया था, वो भी सेना को नमन था, लेकिन विकेट गिरने पर कुछ अलग नहीं।

सोशल मीडिया पर आइसीसी की आलोचना

नई दिल्ली : महेंद्र सिंह धौनी के दस्ताने को लेकर उपजे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर आइसीसी के फैसले की कड़ी आलोचना हो रही है। भारतीय लोग आइसीसी पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आइसीसी नियम के मुताबिक खिलाड़ी मैदान पर कोई धार्मिक संदेश या गतिविधि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह देखिए, इस तस्वीर में पूरी पाक टीम मैदान पर नमाज पढ़ रही है, क्या यह आइसीसी का दोहरा रवैया नहीं है? एक यूजर ने लिखा कि आइसीसी उस वक्त कहां गया था जब पूरी पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड में अपनी सेना को सम्मान देने के लिए पुशअप लगाए थे।

पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश में धुला

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारी बारिश के कारण ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को खेला जाने वाला आइसीसी विश्व कप का मैच बिना एक भी गेंद फेंके रद कर दिया गया। मैच रद होने के कारण दोनों टीमों के खाते में एक-एक अंक आया है। श्रीलंका के अब तीन मैचों में तीन अंक हो गए हैं जबकि पाकिस्तान के भी तीन मैचों में तीन ही अंक हैं। 10 टीमों की अंकतालिका में श्रीलंका बेहतर रनरेट के कारण तीसरे और पाकिस्तान चौथे स्थान पर है। मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश आ गई थी जिसके कारण टॉस में देरी हुई। काफी देर बाद बारिश रुकी और अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया और मैदान के खेलने लायक स्थिति ना बनता देख मैच रद करने का फैसला किया।

विश्व कप अंक तालिका

नं	देश	मैच	जीते	हारे	रद	अंक	नेट रनरेट
1	न्यूजीलैंड	2	2	0	0	4	2.279
2	ऑस्ट्रेलिया	2	2	0	0	4	1.059
3	श्रीलंका	3	1	1	1	3	-1.517
4	पाकिस्तान	3	1	1	1	3	-2.412
5	वेस्टइंडीज	2	1	1	0	2	2.054
6	इंग्लैंड	2	1	1	0	2	0.900
7	भारत	1	1	0	0	2	0.302
8	बांग्लादेश	2	1	1	0	2	0.008
9	दक्षिण अफ्रीका	3	0	3	0	0	-0.952
10	अफगानिस्तान	2	0	2	0	0	-1.264

घुटने में चोट के कारण विश्व कप से बाहर हुए शाहजाद

लंदन, प्रेट्र : अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर मुहम्मद शाहजाद घुटने में चोट के कारण विश्व कप से बाहर हो गए हैं।उनके स्थान पर इकराम अली खिल को बुलाया गया। इकराम के नाम को टूर्नामेंट की तकनीकी समिति ने मंजूरी दे दी है। शाहजाद पाकिस्तान के खिलाफ अभ्यास मैच में इसी चोट के कारण रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने हालांकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ मैच खेले थे।

मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने रन बना पाऊंगा, लेकिन मैं इससे खुश हूं। मैंने सोचा कि यहां कुछ और देर खड़ा रहने की कोशिश करता हूं। किस्मत मेरे साथ गई । **नाथन कूल्टर नाइल, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज**

फ्रेंच ओपन ▶ सेमीफाइनल में स्पेन के राफेल ने रोजर को सीधे सेटों में दी शिकस्त

फेडरर पर भारी पड़े क्ले कोर्ट के मास्टर नडाल

नडाल 12वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे

पेरिस, एएफपी : क्ले कोर्ट के मास्टर कहे जाने वाले स्पेन के सुपरस्टार टेनिस खिलाड़ी गत विजेता राफेल नडाल ने एक बार फिर क्ले कोर्ट पर पुरुषों में सबसे ज्यादा ग्रैंडस्लैम जीतने वाले स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर को पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में हरा दिया।

विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी और गत विजेता नडाल ने विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेडरर को सीधे सेटों में 6-3, 6-4, 6-2 से मात दी। यह मैच दो घंटे 25 मिनट तक चला। इसी के साथ नडाल ने अपना 12वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के लिए फाइनल में कदम रखा है जहां उनका सामना विश्व नंबर एक सर्बिया के नोवाक जोकोविक और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा।

नडाल की फेडरर पर यह 24वीं जीत है। फेडरर, नडाल पर सिर्फ 15 जीत ही दर्ज कर पाए हैं और इनमें से अधिकतर हार्ड या ग्रास कोर्ट पर आई हैं। क्ले कोर्ट पर फेडरर सिर्फ दो बार ही नडाल से जीत पाए हैं, जबकि 14 बार नडाल ने बाजी मारी है। यह दूसरी बार था जब नडाल और फेडरर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ रहे थे। इससे पहले 2005 में दोनों फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में भिड़े थे। फ्रेंच ओपन में यह दोनों अधिकतर फाइनल में ही भिड़े हैं। 2006, 2007, 2008, 2011 में यह दोनों फ्रेंच ओपन के फाइनल में एक-दूसरे के सामने हो चुके हैं और हमेशा नडाल ने बाजी मारी है। फेडरर के खाते में सिर्फ एक फ्रेंच ओपन का खिताब है जो उन्होंने 2009 में जीता था।

> रोजर के साथ यहां खेलना शानदार था। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि 37 वर्ष की उम्र में भी वह सेमीफाइनल तक पहुंचे। यह अविश्वसनीय है। मैं यहां के प्रशंसकों का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि उनके समर्थन से मैं फिर से फाइनल में पहुंच गया। रोजर के साथ खेलना सम्मान की बात है और उनके साथ मैच हमेशा मुश्किल होता है।
> **-राफेल नडाल, खिलाड़ी, स्पेन**

नडाल ने इसी के साथ अपने 18वें ग्रैंडस्लैम खिताब की ओर कदम बढ़ा लिए हैं, जबकि फेडरर का इस टूर्नामेंट में सफर यहीं समाप्त हो गया है। नडाल 26वीं बार ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं।

पहले सेट में को जीतने में नडाल को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन दूसरे सेट में फेडरर अपने अनुभव के आधार पर शुरुआती गेमों में नडाल को टक्कर दे पाए। फेडरर क्ले कोर्ट के मास्टर नडाल को कोर्ट के दोनों तरफ रैलियों में फंसाते रहे और शुरुआती दो गेम अपने नाम कर लिए। तीसरे गेम में दोनों के बीच कड़ी टक्कर रही और यह गेम लगभग आठ मिनट तक चला और नडाल ने इस गेम को जीतकर इस सेट में वापसी की। अगले गेम को भी नडाल ने जीतकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। पांचवें गेम में फेडरर 3-2 से आगे हो गए तो नडाल ने फिर वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया। फेडरर फिर से 4-3 से आगे हो गए। फिर नडाल ने स्कोर 4-4 कर दिया। इसके बाद नडाल ने अगले दो गेम जीतकर यह सेट 6-4 से अपने नाम किया। तीसरे सेट में जब फेडरर 1-2 से पीछे हो गए तो उन्होंने गुस्से में गेंद को रैकेट से मारकर दर्शकों के बीच फेंक दी। इसके बाद चेयर अंपायर ने उन्हें चेतावनी दी। नडाल ने इस सेट को आसानी से 6-2 से अपने नाम कर लिया।

खिताब के लिए भिड़ेंगी एश्ले बार्टी और मार्केता वोंड्रोयूसोवा

पेरिस, रायटर : आठवीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने शुक्रवार को फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में अमांडा एनिसिमोवा पर जीत दर्ज कर पहले ग्रैंडस्लैम फाइनल में प्रवेश किया, जहां उनकी भिड़ंत चेक गणराज्य की मार्केता वोंड्रोयूसोवा से होगी।

23 वर्षीय एश्ले ने पहले सेट में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए 17 वर्षीय अमांडा एनिसिमोवा को 6-7, 6-3, 6-3 से शिकस्त दी। वह सामंता स्टोसुर के बाद फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई हैं जो 2010 में उप विजेता रही थीं। एश्ले इस प्रदर्शन के बूते अगले सप्ताह विश्व रैंकिंग में शीर्ष-तीन में पहुंच जाएंगी। उन्होंने कहा, 'यह मैच शानदार था, अच्छा और बुरा दोनों। यह हालांकि काफी मुश्किल था। मुझे खुद पर गर्व है कि मैंने इस तरह वापसी की और वो भी इतनी ठंडी व हवा भरी स्थिति में। अब मुझसे फाइनल के लिए इंतजार नहीं हो रहा। यह शानदार रहा।'

फाइनल में अब एश्ले का सामना चेक गणराज्य की 19 वर्षीय मार्केता वोंड्रोयूसोवा से होगा जिसमें उनकी कोशिश 1973 के बाद पेरिस में पहली ऑस्ट्रेलियाई चैंपियन बनने की होगी। 1973 में मार्गेट कोर्ट पेरिस में चैंपियन बनने वाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थीं।

रोजर फेडरर के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद राफेल नडाल। एपी

भारतीय हॉकी टीम की लगातार दूसरी जीत

शानदार

- एफआइएच सीरीज फाइनल्स में पोलैंड को 3-1 से हराया
- मनप्रीत ने दो और हरमनप्रीत ने एक गोल दागा

गोल करने के बाद जश्न मनाते मनप्रीत (बायें)। एपी

भुवनेश्वर, प्रेट्र : कप्तान मनप्रीत सिंह की अगुआई में भारतीय हॉकी टीम ने शुक्रवार को यहां एफआइएच सीरीज फाइनल्स टूर्नामेंट में पोलैंड को कड़े मुकाबले में 3-1 से शिकस्त दी।

पहला क्वार्टर गोलरहित रहने के बाद मनप्रीत ने 21वें और 26वें मिनट में गोल दागे, जबकि ड्रेग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह ने 36वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित की। पोलैंड की ओर से एकमात्र गोल 25वें मिनट में मातेउस्ज हुलबोज ने किया।

विश्व की पांचवें नंबर की टीम भारत ने लगातार दूसरी जीत दर्ज जरूर की, लेकिन विश्व की 21वें नंबर की टीम पोलैंड को हराने में उसे संघर्ष करना पड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि भारत ने तीन महीने से भी कम समय पहले अजलन शाह कप में पोलैंड को 10-0 से रौंदा था। भारतीय खिलाड़ियों ने आदत के अनुसार धीमी शुरुआत की। पहले ही मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के रूप में पोलैंड को मैच का पहला गोल करने का मौका मिला, लेकिन यह मौका बेकार चला गया। भारतीय खिलाड़ी धीरे-धीरे लय में नजर आए, लेकिन पोलैंड ने डिफेंडरों ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया।

भारत के पास गोल करने का पहला मौका छठे मिनट में आया, जब मनदीप सिंह ने आकाशदीप सिंह के साथ मिलकर एक मौका बनाया, लेकिन पोलैंड के गोलकीपर मैकिज पैकानोव्सकी ने इसे लाइन से बाहर कर दिया। भारत को पहला पेनाल्टी कॉर्नर हासिल करने में 20 मिनट लगे, लेकिन हरमनप्रीत के प्रयास को पोलैंड के गोलकीपर ने बचा लिया। एक मिनट बाद भारत को एक और पेनाल्टी कॉर्नर हासिल हुआ और अमित रोहिदास के फ्लिक को पोलैंड के गोलकीपर ने रोक दिया, लेकिन रिबाउंड पर मनप्रीत ने गोल दाग दिया। हुलबोज ने 25वें मिनट में गोल कर पोलैंड को एक-एक की बराबरी दिला दी, लेकिन मनप्रीत ने 26वें मिनट में गोल से भारत को 2-1 से आगे कर दिया। हरमनप्रीत ने 36वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 3-1 की बढ़त दिलाई और अंत में भारत ने जीत दर्ज की।

अगले वर्ष न्यूजीलैंड जाएगा भारत

वेलिंगटन, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट टीम अगले साल न्यूजीलैंड के दौरे पर पांच टी-20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी।

इस दौरे की शुरुआत 24 जनवरी से टी-20 मुकाबले से शुरू होगी। इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज का आयोजन होगा। दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन (21 से 25 फरवरी) और दूसरा मैच क्राइस्टचर्च (29 फरवरी से चार मार्च) में खेला जाएगा।

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य अधिकारी डेविड वाइट ने कहा कि सीरीज का दूसरा टी-20 मैच 26 जनवरी को ईडन पार्क में खेला जाना प्रस्तावित है, लेकिन अभी इस पर ऑकलैंड परिषद की ओर से फैसला आने का इंतजार है।

नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराया, फाइनल में पुर्तगाल से सामना

नेशंस लीग

- सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड को 3-1 से हराकर उसे चौंकाया
- 1990, 2018 विश्व कप और यूरो 1996 के सेमीफाइनल में भी हारी थी इंग्लैंड

गुइमारेस (पुर्तगाल), रायटर : युवा टीम नीदरलैंड्स ने नेशंस लीग के एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व की चौथे नंबर की टीम इंग्लैंड को 3-1 से मात दी। निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर था, लेकिन नीदरलैंड्स ने अतिरिक्त समय में बाजी मारी। फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अब मेजबान पुर्तगाल से होगा, जिसने करिश्माई फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की हैट्रिक के दम पर स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

पहला हाफ इंग्लैंड ने अपने नाम किया, जबकि नीदरलैंड्स ने दूसरे हाफ में गोल करके मैच को अतिरिक्त समय में धकेल दिया। 15 मिनट के अतिरिक्त समय में इंग्लैंड अपनी गलती के कारण मैच में पीछे हुआ तो वहीं, नीदरलैंड्स ने अपने जोश को कायम रखते हुए जीत हासिल की। इससे पहले भी इंग्लैंड की टीम तीन बार बड़े टूर्नामेंटों के सेमीफाइनल में हारी है। 1990 व 2018 विश्व कप और यूरो 1996 के सेमीफाइनल में टीम को शिकस्त मिली थी। इंग्लैंड की टीम 1996 के बाद यह ट्रॉफी नहीं जीत पाई है और इस बार भी उसने यह मौका गंवा दिया। इंग्लिश टीम के कोच गेरेथ साउथगेट ने शुरुआती एकादश में टॉटनहम के कप्तान हैरी केन को शामिल नहीं किया। केन स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर खेलने उतरे। 2016 यूरो कप और 2018 फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाने वाली नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। पहले हाफ में इंग्लैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 32वें मिनट में मैथियास डि लिट की गलती के कारण उसे पेनाल्टी मिली। मार्कस रशफोर्ड ने कोई गलती नहीं की और पेनाल्टी पर गोल करते हुए इंग्लैंड का मैच में खाता खोल दिया। नीदरलैंड्स ने दूसरे हाफ में बेहतरीन प्रदर्शन किया। 73वें मिनट में डि लिट ने अपनी गलती को सुधारा और 18 गज के बॉक्स के अंदर से हेडर के जरिये गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। निर्धारित समय की समाप्ति से पहले इंग्लैंड के जेसी लिंगार्ड ने गेंद को गोल पोस्ट में डाला, लेकिन वार की मदद लेने के बाद रेफरी ने उसे ऑफ साइड करार दिया। नीदरलैंड्स ने अतिरिक्त समय में आक्रामक खेल खेला। इंग्लैंड के काइल वाल्कर 97वें मिनट में ओन गोल (आत्मघाती गोल) कर बैठे और नीदरलैंड्स को मैच में 2-1 से आगे कर दिया। इंग्लैंड ने वापसी करने का प्रयास किया, लेकिन क्विंसी प्रोम्स ने 114वें मिनट में गोल दागकर नीदरलैंड्स की जीत 3-1 से पक्की कर दी।

> हमने जर्मनी, फ्रांस को हराया और अब विश्व की चौथे नंबर की टीम इंग्लैंड को शिकस्त दी। हमने सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेला था, लेकिन इस बार हमारे लिए यह नया है। हम फाइनल में भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
> **- रोनाल्ड कोमैन, कोच, नीदरलैंड्स**

> 'हमने मैच के दौरान कई गलतियां की। यह हार हम सभी के लिए दर्दनाक है। हमने इस हार से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन, आखिरी में हम फिर से सेमीफाइनल में हार गए।'
> **- गेरेथ साउथगेट, कोच, इंग्लैंड**

पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि का इंतजार

अनिल भारद्वाज, गुरुग्राम : वर्ष 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का इंतजार है। जकार्ता में भारत ने 15 स्वर्ण पदक समेत 69 पदक जीते हैं, जिसमें अकेले हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने एकल स्पर्धा व टीम स्पर्धा में 18 पदक (6 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य पदक) जीतकर देश का नाम रोशन किया।

इस संबंध में खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण का कहना है कि अगले दस दिन में इस बारे में निर्णय हो जाएगा कि जकार्ता पदक विजेताओं को कब इनाम राशि वितरित की जा रही है। इसके लिए तैयारी चल रही है। खिलाड़ियों के कागजात की जांच चल रही है।

विविध

रूस में इकोनॉमिक फोरम में बोलेंगी बरखेड़ी अब्दुल्ला की युवा सरपंच

जागरण सरोकार

सौरभ खंडेलवाल, भोपाल

गांव में सरकारी योजनाओं का अमल कैसे किया जाता है, मध्य प्रदेश की बरखेड़ी अब्दुल्ला ग्राम पंचायत की युवा सरपंच भक्ति शर्मा यह बात दुनिया को बताएंगी। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम से उन्हें बुलावा आया। रूस के इस शहर में यह सम्मेलन चल रहा है। अमेरिका में नौकरी छोड़ गांव की सरपंच बनीं भक्ति आज देश की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हैं।

गांव में सरकारी योजनाओं का अमल कैसे होता है, इसकी शानदार नजीर भक्ति ने पेश की है। भोपाल के पास बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत आज मिसाल बन चुकी है। भक्ति की पंचायत में करीब-करीब हर पात्र व्यक्ति तक उससे संबंधित योजना पहुंची है। ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के इस क्रियान्वयन से प्रभावित होकर ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें आमंत्रित किया। रूस रवाना होने से पहले भक्ति ने बताया कि वे फोरम में बताएंगी कि किस तरह सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर ग्रामीण विकास को अपेक्षित गति दी जा सकती है और सतत विकास लक्ष्य-2030 (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स-2030) की दिशा में लक्षित सफलता पाई जा सकती है। 6-8 जून के बीच होने जा रहे इस सम्मेलन में भक्ति 120 देशों के प्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखेंगी और अपनी पंचायत की विकास यात्रा से सभी को परिचित कराएंगी।

नारी सशक्तीकरण

गौरतलब है कि 2015-16 में भक्ति शर्मा अमेरिका से नौकरी छोड़कर भारत लौटी थीं और पिता के कहने पर अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव जीता था। कुछ समय पहले उन्हें भारत की 100 सबसे प्रभावशाली व लोकप्रिय महिलाओं की सूची में भी शामिल किया गया। भक्ति ने गांव में नारी सशक्तीकरण की नई धारा बहा दी। जात-पात पर भी प्रहार किया और भ्रष्ट सरकारी तंत्र का भी डटकर सामना किया।

भक्ति ने नईदुनिया से कहा, मेरी पंचायत के हर घर में शौचालय है और पंचायत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी है। हर पात्र परिवार के पास राशनकार्ड है और उसे बिना किसी बाधा राशन मिल रहा है। पंचायत में कुपोषण का नामोनिशान नहीं है। आवास योजना के तहत 200 पात्र परिवारों के पक्के मकान बन चुके हैं। सभी के पास बिजली कनेक्शन है। गांवों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है। पानी की टंकी और पेयजल सप्लाई है। इसके साथ ही पंचायत में आयुष ग्राम योजना को भी लागू करने की कोशिश कर रही हूं...।

सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1997 से यह सम्मेलन हर साल होता है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में गए थे।

मध्य प्रदेश में भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला ग्राम पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा। नई दुनिया

- अमेरिका से लौटकर बनीं सरपंच, 100 प्रभावशाली महिलाओं में शुमार
- बेहतर कामों को लेकर चर्चा में रही हैं मध्य प्रदेश की बरखेड़ी अब्दुल्ला ग्राम पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा
- सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में रखेंगी अपनी बात

बेटी होने पर देती हैं दो माह की तनख्वाह

भक्ति शर्मा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से इतर अपनी पंचायत के लिए अपने स्तर पर भी एक योजना चला रही हैं। बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में यदि किसी घर में बेटी होती है तो बेटी की मां को भक्ति शर्मा सरपंच के रूप में मिलने वाली अपनी दो महीने की तनख्वाह उपहार में देती हैं। इसके साथ ही बेटी के जन्म पर पंचायत क्षेत्र में दस पेड़ लगाए जाते हैं।

बेबाक बोल, बिंदास अंदाज

भोपाल के नूतन कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए करने वाली भक्ति शर्मा सरकारी योजनाओं के तहत पंचायत में काम करने के लिए विभाग के सचिव से लेकर राज्य और केंद्रीय मंत्रियों तक से बेहिचक मिलती हैं। कहती हैं, मैं हर योजना का बारीकी से अध्ययन करती हूं। लिहाजा, कोई भी गैर जरूरी अड़चन आए तो इसे दूर करना भी मुझे आता है।

जोरशोर से गूंजेगा मां क्षीर भवानी का जयकारा

आतंक और अलगाववादियों पर सख्ती से कश्मीरी पंडितों में जगी नई उम्मीद

जागरण विशेष

गुलदेव राज, जम्मू

- 10 जून को कश्मीर के तुलमुला में लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में जुटेंगे विस्थापित कश्मीरी पंडित, अब तक छह हजार पंजीकरण
- कश्मीर वापसी की उम्मीदें लेकर हर साल दर्शन को आते हैं, लेकिन इस बार अलग है उत्साह

कश्मीर में आतंक और अलगाववादियों पर बरती जा रही सख्ती ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों में नई उम्मीद जगा दी है। कश्मीर वापसी की आस लेकर वे हर साल मां क्षीर भवानी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। उम्मीद की जा रही है कि 10 जून को कश्मीर में लगने वाले क्षीर भवानी मेले में बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी पंडित जुटेंगे। अब तक छह हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

अपनी मिट्टी को आज भी कश्मीरी पंडित भूल नहीं पाए हैं। नौवें दशक में आतंकवाद के कारण पलायन कर चुके ये परिवार मां क्षीर भवानी के दर्शन को आते हैं तो कश्मीर वापसी के लिए प्रार्थना भी करते हैं। मां क्षीर भवानी, जिन्हें मां राघेन्या भी कहा जाता है, कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी हैं और अनेक परिवारों की कुल देवी भी हैं। युवा पीढ़ी मेले के बहाने कश्मीर को करीब से देखने को आतुर रहती है। इस बार युवाओं में उम्मीद और उत्साह चरम पर है। कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में 10 जून को लगने वाले मेले में देश-विदेश में बसे कश्मीरी पंडित पहुंचेंगे। जम्मू में इनका जुटना पहले ही शुरू हो गया है। यहां से 9 जून को मंदिर के लिए रवाना होंगे। राज्य प्रशासन श्रद्धालुओं का पंजीकरण रहा है। अब तक करीब छह हजार लोग पंजीकृत हो चुके हैं और उम्मीद है कि यह आंकड़ा दस हजार को पार कर जाएगा। सुरक्षा कारणों से यात्रा के लिए विशेष बसों की व्यवस्था प्रशासन करता है। कुछ बसें दिल्ली से भी चलती हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ अष्टमी को माता का अवतरण हुआ था। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के वरिष्ठ सदस्य अजय सफाया का कहना है कि 1990 में घाटी से बड़ी संख्या में पलायन कर जम्मू सहित दिल्ली और अन्य राज्यों में बसे पंडित परिवार बेताब रहते हैं कि वे इस मौके पर कश्मीर जरूर पहुंचें। दिल्ली में बसे शुभम हांडू के बेटे मोहित ने कहा कि आतंकवाद के कारण वह कभी कश्मीर नहीं गए, लेकिन इस बार क्षीर भवानी मेले में जरूर जाएंगे। इंजीनियरिंग कर चुके एक अन्य युवा राजेश कौल ने कहा कि उस समय (1990) जो हुआ था वह गलत था। पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाना चाहिए।

पंडितों ने तुलमुला स्थित मंदिर की तरह ही जम्मू में भी हूबहू मंदिर का निर्माण करवाया है। जो पंडित घाटी में नहीं पहुंच पाते हैं, वे यहां पर माता की पूजा-अर्चना करते हैं। पनुन कश्मीर के प्रधान विनोद का कहना है कि हर साल श्रद्धा का यह सैलाब बढ़ता ही जा रहा है, वहीं अब उम्मीदें भी बढ़ रही हैं।

कश्मीर वापसी की उम्मीद लिए हर साल दर्शन को आते हैं विस्थापित कश्मीर पंडित। जागरण

कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला में स्थित मां क्षीर भवानी का मंदिर। जागरण

10 जून को लगेगा मेला, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जागरण

कार्बेट में बाघों व हाथियों के बीच बढ़ा संघर्ष

केदार दत्त, देहरादून

उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव संघर्ष ही चिंताजनक स्थिति में नहीं पहुंचा है, बल्कि जंगलों में वन्यजीवों के बीच बढ़ा संघर्ष भी हैरत में डाल रहा है। विश्व प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व की पिछले पांच वर्षों की तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है। बाघ, हाथी व गुलदार की आपसी संघर्ष में हुई मौत के सिलसिले में पहली बार कराए गए अध्ययन में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। खासकर, बाघों व हाथियों के मध्य द्वंद्व बढ़ा है। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पांच साल में 21 हाथियों की जान गई। इनमें से 13 को बाघों ने शिकार बनाया। अध्ययन रिपोर्ट में उजागर हुआ कि हिरनों के पीछे भागने में अधिक ऊर्जा जाया होने और फिर भी शिकार की गारंटी न होने के मद्देनजर बाघ वहां शिशु हाथियों को आसान शिकार समझने लगे हैं।

कार्बेट टाइगर रिजर्व में बीती 27 मई को आपसी संघर्ष में एक बाघिन की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद रिजर्व के निदेशक के निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने बीते पांच सालों में रिजर्व में बाघ, हाथी व गुलदारों की आपसी संघर्ष में हुई मौत के मामलों का अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया। निदेशक चतुर्वेदी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार एक अप्रैल 2014 से 30 मई 2019 तक रिजर्व में तीनों प्रजातियों के 36 वन्यजीवों (बाघ, हाथी व गुलदार) की आपसी संघर्ष में मौत हुई।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा संभव है। दिन के तापमान में वृद्धि के कारण दिन काफी गर्म रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क तथा काफी गर्म रहेगा। कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है।

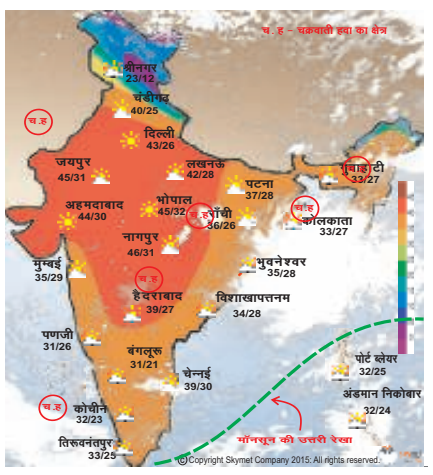

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	35/29/ध	अहमदाबाद	43/26/ध
कोलकाता	35/27/ध	बड़ौदा	40/26/आंबा
चेन्नई	40/30/आंबा	नागपुर	46/31/ध
हैदराबाद	39/27/स	इन्दौर	44/27/ध
बंगलूरु	30/20/आंबा	रांची	36/28/ध
त्रिवेन्द्रम	31/24/ध	पटना	41/31/ध
गुवाहाटी	34/27/आंबा	जमशेदपुर	33/29/आंबा
गंगटोक	18/09/ध	पुणे	32/23/ध

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
शनिवार 8 जून 2019
14
www.jagran.com

ऑल इंडिया रेडियो को अपना नाम मिला

1936 में आज ही भारत की सरकारी रेडियो सेवा यानी ऑल इंडिया रेडियो (एआइआर) को अपना नाम मिला था। इस सेवा को पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। बाद में 1956 से इसे आकाशवाणी के नाम से जाना गया।

एयर इंडिया ने पहली बार विदेश के लिए उड़ान भरी

1948 में आज ही मालाबार प्रिंसेस नाम के विमान ने मुंबई से मिस्र की राजधानी काइरो और स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा से होते हुए लंदन के लिए उड़ान भरी थी। चालीस सीटों वाले इस विमान में जेआरडी टाटा और जामनगर के नवाब आमिर अली जैसे लोग सवार थे।

मशहूर अदाकारा डिंपल कपाड़िया को जन्मदिन मुबारक

हिंदी सिनेमा में बेहतरीन अभिनय का मुजाहिरा पेश करने वाली डिंपल कपाड़िया का जन्म 1957 में आज ही मुंबई में हुआ था। 1973 में उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी की। 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकीं डिंपल की पहली फिल्म बॉबी रही। 1993 में आई फिल्म रुदाली में शानदार अभिनय के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। वहीं दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजी गईं। । राम लखन, बीस साल बाद, नरसिम्हा, क्रांतिवीर, सागर, दबंग, लेकिन, रणभूमि उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में रहीं।

इधर-उधर की

पर्यावरण बचाइए छुट्टी बढ़ाइए

बर्लिन, एजेंसी : पर्यावरण को बचाने की दिशा में बर्लिन की एक कंपनी ने एक बढ़िया तरकीब निकाली है। वाइबरविर्टशाफ्ट नाम की इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ऐसी नीति निकाली है कि यदि वे एक साल तक एक भी हवाई यात्रा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी। जर्मनी में आम तौर पर साल में तीस छुट्टियां मिलती हैं। इस लिहाज से कंपनी छुट्टी की संख्या में दस फीसद का इजाफा कर रही है। कंपनी की सीईओ कात्या फॉन डेय का इस संबंध में कहना है कि हर कोई जानता है कि हवाई जहाज के कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस नीति को एक प्रतीक के रूप में लेना चाहिए। शायद यह एक सीख बन जाए ।

स्टेम सेल को बचाएगी नई हाइड्रोजेल

तकनीक ▶ मोहाली इंस्टीट्यूट के शोधकताओं ने विकसित किया इंजेक्टेबल जेल

मेसेनकेमल स्टेम सेल (एमएससी) को दवा में मिलाकर किया तैयार

शोधकर्ताओं के साथ अध्ययन की मुख्य अन्वेषक डॉ. दीपा घोष (मध्य में)। फोटो सौजन्य : आइएसडब्ल्यू

बेंगलुरु : आइएसडब्ल्यू : चिकित्सा क्षेत्र में स्टेम कोशिकाओं का प्रत्यारोपण एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि इसमें प्रत्यारोपित कोशिकाओं के जीवित रहने से जुड़ी कई समस्याएं सामने आती हैं। स्टेम सेल, जब किसी घाव में प्रत्यारोपित किया जाता है, तो पैराक्रीन फैक्टर नामक रसायन छोड़ता है, जो ऊतक के पुनर्निर्माण के लिए आसपास की अन्य कोशिकाओं को प्रेरित करता है। भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित की है जो प्रत्यारोपित कोशिकाओं (स्टेम सेल) को लंबे समय तक जीवित रहने में मदद कर सकता है।

मोहाली के इंस्टीट्यूट ऑफ नैनोसाइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकताओं ने हाइड्रोजेल में मेसेनकेमल स्टेम सेल (एमएससी) को एनकैप्सुलेट कर इसे तैयार किया है। प्रारंभिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि हाइड्रोजेल सेल स्टेम कोशिकाओं को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। यह हाइड्रोजेल प्राकृतिक मैटीरियल, जैसे- सेलूलोज, किटोजन से बनाया गया है और लगाने के एक महीने बाद स्वयं ही नष्ट हो जाता है। साथ ही इसमें अमीनो और एल्डिहाइड समूह के तत्व भी मौजूद हैं।

इस अध्ययन की मुख्य अन्वेषक डॉ. दीपा घोष ने बताया कि हाइड्रोजेल स्टेम कोशिकाओं को लंबे समय तक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और शरीर के ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। उन्होंने बताया कि अध्ययन के दौरान हमने देखा कि इसके प्रयोग से न सिर्फ स्टेम सेल जीवित रहते हैं, बल्कि एक महीने के भीतर ही ऊतकों का पुनर्निर्माण कर यह स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

उन्होंने कहा कि हाइड्रोजेल कोशिकाओं को सामान्य रूप से काम करने में भी मदद करता है। प्रत्यारोपण के बाद, हाइड्रोजेल में मौजूद पेराक्रीन कोशिकाओं के विकास और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में सहायता करता है। इस अध्ययन के लेखक जिजयो थॉमस ने कहा कि इस हाइड्रोजेल में ऊतक कोशिकाओं के समान 95 फीसद पानी के तत्व हैं, जो कोशिकाओं में ऊतकों को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, यह जेल घाव के अनुरूप ही आकार भी ले सकती है, जिसका फायदा यह है कि इसे लगाने से घाव पूरा ढक जाएगा और किसी भी तरफ का इंफेक्शन होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। इसमें मौजूद पेराक्रीन घाव को फैलने से भी बचाती है।

डॉ. दीपा घोष ने कहा कि पशुओं पर परीक्षण के दौरान हाइड्रोजेल हर परिस्थिति में खरा उतरा है। उम्मीद है कि भविष्य में यह तकनीक लोगों के घावों के उपचार में बेहद कारगर होगी और मरीजों जल्द स्वस्थ हो पाएंगे।

आमतौर पर जख्म ज्यादा गहरे होने पर जल्दी नहीं भर पाते, लेकिन शोधकर्ताओं का दावा है कि हाइड्रोजेल के जरिये घाव जल्दी ठीक हो सकता है। शोधकर्ताओं में दीपा घोष और के साथ जीजयो थॉमस के अलावा, अंजना शर्मा, विनीता पंवार और वियानी चोपड़ा शामिल थीं। इस अध्ययन के परिणाम एसीएस एप्लाइड बायोमेट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित हुए हैं ।

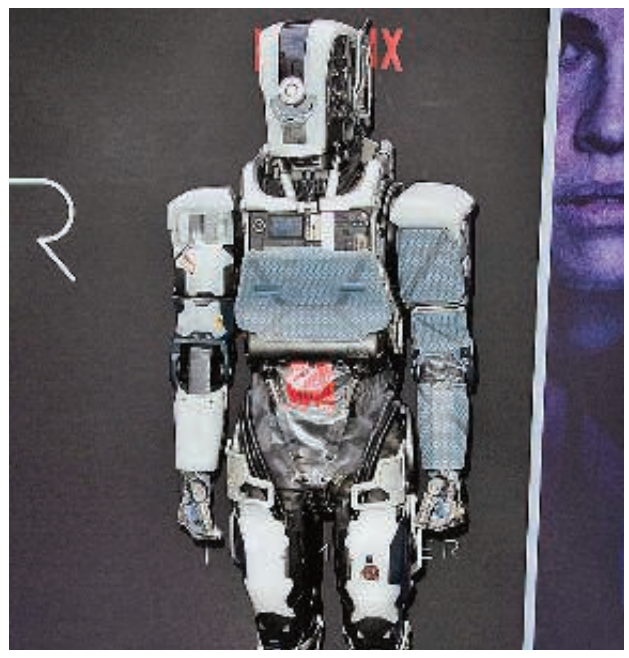

आई एम मदर...

अमेरिका में एक समारोह के दौरान पोज देती 'मदर रोबोट'। इस रोबोट ने ऑस्ट्रेलियन-अमेरिकन थ्रिलर-साइंस फिक्शन फिल्म 'आई एम मदर' में मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन ग्रांट स्पुतोर ने किया है। माइकल लॉयड ने इसकी पटकथा लिखी है। कहा जा रहा है कि यह फिल्म टोनी डिटरलाइजी की पुस्तक 'द सर्च फॉर वोंडाला' से प्रेरित है। एपी

शोध अनुसंधान

टीबी से लड़ने वाली मास्टर सेल की पहचान

शोधकर्ताओं ने एक मास्टर सेल (कोशिका) की पहचान की है। यह टीबी संक्रमण के प्रारंभिक दिनों में शरीर के इम्यून (प्रतिरक्षा) सिस्टम की प्रतिक्रिया में समन्वय का काम करती है। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं ने पाया कि इस तरह की कोशिकाओं की गतिविधि को मजबूत करने से टीबी संक्रमण के नए मामलों को रोकने में मदद मिल सकती है। अध्ययन में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और अफ्रीका हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने टीबी बैक्टीरिया से शरीर की रक्षा करने वाली इम्यून सेल्स की पहचान करने के लिए इंसानों और पशुओं पर शोध किया। उन्होंने पाया कि ग्रुप 3 इनेट लिम्फोइड सेल्स (आइएलसी3) नामक कोशिकाएं टीबी संक्रमण के पहले दो सप्ताह में अहम भूमिका निभाती हैं। -आइएएनएस

श्वास नली में कफ जमाने में मदद करता है निकोटीन

एक अध्ययन में दावा किया गया है कि ई-सिगरेट में मौजूद निकोटीन की श्वास नली से बलगम (कफ) को बाहर निकलने में बाधक बनता है, जिससे संक्रमण खतरा बढ़ सकता है। रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि श्वास नली की कोशिकाओं को निकोटीन युक्त ई-सिगरेट के संपर्क में लाने से उसकी सतह पर जमा हुए बलगम बाहर नहीं निकल पाता। इस घटना को 'म्यूकोसिलिक डिसफंक्शन' कहा जाता है। अमेरिका के कंसास और मियामी यूनिवर्सिटी और माउंट सिनाई मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने एक भेड़ पर निकोटीन का परीक्षण कर यह दावा किया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने भेड़ की श्वास नली पर तंबाकू के धुंए के प्रभावों की जांच की गई तो पाया गया कि उसका बलगम एक ही जगह पर जम गया। -प्रेट्र

दावा : सौरमंडल के बाहर स्थित चंद्रमाओं में हो सकता है जीवन

- वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से किया अध्ययन
- ग्रह के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण इन चंद्रमाओं की सतह पर आ जाता है पानी

प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : एलियन होने और न होने की बारे में अभी तक वैज्ञानिक नहीं बता पाए हैं। हालांकि, इस पर बहस होती रहती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह जरूर दावा किया है कि हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रहों (एक्सोप्लैनेट) के चंद्रमा (एक्सोमून) में एलियन हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में बताया कि इन एक्सोमून में मौजूद तरल पानी वहां जीवन की संभावनाएं जताता है।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन के शोधार्थियों के मुताबिक अभी तक चार हजार एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। इनमें से बहुत कम ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। हालांकि, इनके चंद्रमाओं में पानी होने की आशा लगाई जा रही है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिल जे सटन ने बताया कि एक्सोप्लैनेट का चक्कर लगाने वाले एक्सोमून उस ग्रह के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण अंदर से गर्म हो जाते हैं और इससे उनकी सतह के भीतर का पानी खिंचाव से ऊपरी सतह पर आ जाता है, जिससे जीवन की संभावना पनपती है। उन्होंने कहा कि हम लगातार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

रॉयल स्ट्रोलनॉमिकल सोसायटी की मासिक पत्रिका में प्रकाशित शोध में बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लेनेट जे1407 बी की परिक्रमा कर रहे चंद्रमा के मौसम का विश्लेषण कर यह संभावना जताई है।

एक्सोमून का पता लगाना है बहुत मुश्किल : अपने आकार और पृथ्वी से दूरी के कारण इन एक्सोमून का पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है। सौरमंडल के बाहर के ग्रह अधिकतर गैसों के होते हैं। जिनके आसपास शनि ग्रह के जैसे ही वलय होते हैं। वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लेनेट जे1407 बी का कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से अध्ययन किया तो पाया कि इसका वलय शनि के वलय से 200 गुना बड़ा है।

वैज्ञानिकों को हवा की गुणवत्ता के आंकड़े साझा करेगा गूगल

सैनफ्रांसिस्को, आइएएनएस : प्रदूषण पर नजर रखने के लिए एक बड़े प्रयास के तहत, गूगल वैज्ञानिकों के लिए वायु गुणवत्ता के आंकड़े जारी कर रहा है, जिसे उसने प्रोजेक्ट 'एयर व्यू' के तहत अपनी स्ट्रीट व्यू कारों के साथ कैलिफोर्निया के बे एरिया और सेंट्रल वैली से एकत्र किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन वर्षों में गूगन ने ये डेटा जुटाए हैं। कारों में इंटरनेट से जुड़े वायु गुणवत्ता सेंसर से ग्रीनहाउस गैस मीथेन, पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड समेत अन्य गैसों की माप लेकर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

कंपनी के पास पहले से ही ह्यूस्टन, साल्ट लेक सिटी, कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम और लंदन में इसी तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। 2019 के अंत तक, सर्च इंजन दिग्गज ने एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित अन्य महाद्वीपों के लिए प्रोजेक्ट एयर व्यू का विस्तार करने की योजना बनाई है। हालांकि यह पूरा डेटा सेट जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों को गूगल ये आंकड़े देगा, ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

डाटा साइंस के जरिये डिकोड किया बीथोवेन का म्यूजिक

जेनेवा, प्रेट्र : शोधकर्ताओं ने जर्मन संगीतकार और पियानो वादक लुडविंग वान बीथोवेन की संगीत को पहली बार सांख्यिकीय तकनीक के जरिए डिकोड किया है।

लुडविंग वान बीथोवेन पश्चिमी कला संगीत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली संगीतकारों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में उनकी 9 सिम्फनिया, 5 पियानो कोन्सर्टो, एक वायलिन कंसर्टो, 32 पियानो सोनटा, 16 स्ट्रिंग क्वॉर्टेट्स शामिल हैं।

स्विटजरलैंड में इकोले पॉलिटेक्निक फेडरेल डी लॉजेन (ईपीएफएल) के शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके संगीत में बहुत कम कॉर्ड ऐसे हैं जो संगीत को नियंत्रित करते हैं। पीएलओएस वन नामक पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन 'बीथोवन स्ट्रिंग क्वॉर्टेट्स' नामक कंपोजिशन पर आधारित है।

ईपीएफएल के मार्टिन रोहरमीयर ने कहा कि सांख्यिकी और डाटा विज्ञान में नई अत्याधुनिक पद्धतियां हमारे लिए पारंपरिक संगीत विज्ञान की पहुंच से बाहर के तरीकों का संगीत विश्लेषण करना संभव बनाती हैं। 'बीथोवन स्ट्रिंग क्वॉर्टेट्स' में 16 खंड हैं जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल में रचा था। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कंपोजिशन पूरा कर लिया था और 1826 में मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने आखिरी कंपोजिशन भी पूरी की थी।
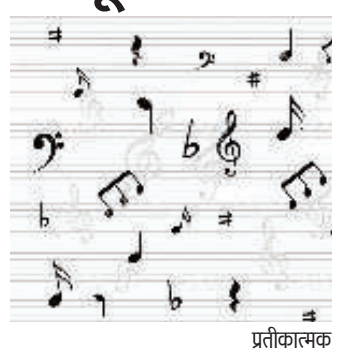
प्रतीकात्मक

एक स्ट्रिंग क्वॉर्टेट्स में चार वाद्ययंत्र बजाने वाले चार संगीतकार एक साथ दो वायलिन, वायोला और सेलो बजाते हैं। अध्ययन के लेखक, फैबियन सी मॉस ने कहा, हमने मूल रूप से बीथोवेन के संगीत के जरिए एक बड़ा डिजिटल रिसोर्स तैयार किया। इसमें लगभग 30,000 कॉर्ड एनोटेशन शामिल हैं।

ड्रैगन बोट महोत्सव पर मनाया जश्न

हांगकांग में ऐतिहासिक चाइनीज ड्रैगन बोट महोत्सव पर एक-दूसरे पर पानी फेंककर जश्न मनाते लोग। यह महोत्सव चीन के प्रमुख विद्वान और राजनेता चू युआन की याद में मनाया जाता है। सरकारी भ्रष्ट्राचार को लेकर चू युआन की सबसे मुखर नेताओं में गिनती की जाती थी। उनकी मौत 277 ईपू एक नाव दुर्घटना में हुई थी। ड्रैगन बोट प्रतियोगिता इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण मानी जाती है। इसके अलावा ओपेरा शो, कार्निवल और इंटरेक्टिव सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। एपी

वर्षा के लिए प्रार्थना

कंबोडिया में धान की रोपाई से पहले वर्षा की कामना को लेकर अनूठा समारोह आयोजित किया जाता है। इसमें शामिल महिला-पुरुष चेहरों को रंग-पोत कर तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं। कुछ भूतों जैसा रूप धारण करते हैं। समारोह के दौरान राजधानी नामपेन्ह के गांव प्रिंग का-इक में जश्न के दौरान बांसों से बनी पालकी लेकर जाते ग्रामीण। यहां इसी प्रकार प्रतिवर्ष सामूहिक से रूप से वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। धान, कंबोडिया की प्रमुख फसलों में से एक है। एपी

स्क्रीन शॉट

शो के कॉन्सेप्ट से खुद को रिलेट करते हैं सैफ

'ससुराल सिमर का' फेम दीपिका कक्कड़ और अभिनेता करण वी ग्रोवर की जोड़ी संदीप सिकंदर के रोमांटिक शो 'कहां हम कहां तुम' में एक साथ नजर आएगी। यह शो दो अलग-अलग दुनिया से वास्ता रखने वाले दो पात्रों की कहानी है, जो अपने व्यस्त शेड्यूल के साथ दो अलग-अलग पेशे से ताल्लुक रखते हैं। शो के पहले ट्रेलर में सैफ अली खान द्वारा ऑन-स्क्रीन जोड़े का परिचय दिया गया, जिसने दर्शकों के जेहन में सवाल खड़ा कर दिया कि हालांकि उनके दिल एक हैं, लेकिन क्या वे एक-दूसरे को समझने में कामयाब होंगे? दरअसल, दोनों डिमांडिंग करियर में हैं। सैफ अली खान शो के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह से खुद को रिलेट करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि बतौर कलाकार अपने परिवार के लिए समय मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। सैफ ने कहा, 'हम सभी अपने कामों

में व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता के चलते हमें अपने करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है। अपने करियर को कई बार ज्यादा समय देने से आपके संबंधों को भी भुगतना पड़ता है। मैं खुद शो से रिलेट करता हूं। मैं भी एक्टर हूं और शूटिंग के बाद देर से घर पहुंचने पर जब मैं अपने बेटे तैमूर को सोते हुए पाता हूं तो मुझे बहुत खराब महसूस होता है। शो में रोहित और सोनाक्षी के किरदार मेरे जीवन से संबंधित हैं। मेरे पिता क्रिकेटर थे, जबकि मां अभिनेत्री। दोनों अलग प्रोफेशन से रहे, लेकिन एक-दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। मेरा मानना है कि हमेशा अपने काम और जिंदगी में उलझे रहना अच्छी बात नहीं है। आपको दूसरे लोगों से भी बात करनी चाहिए, तब आपकी जिंदगी और खूबसूरत हो सकती है।' शो में यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि टेलीविजन शो में काम करना कितना मुश्किल है। सैफ ने कहा, 'एक्टर की जिंदगी बहुत ग्लैमरस दिखती है, हालांकि उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। मुझे लगता है कि यह शो कलाकारों की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को दिखाएगा।' शो का प्रसारण 17 जून से स्टार प्लस पर होगा।

रिहर्सल के लिए पंकज के घर जाती थीं जाह्नवी

फिल्म 'धड़क' से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी दूसरी फिल्म गुंजन सक्सेना की बायोपिक की शूटिंग कर रही हैं। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी, उस वक्त घायल सैनिकों को बचाने का जिम्मा गुंजन सक्सेना और उनके साथी ने लिया था। गुंजन को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। फिल्म में जाह्नवी गुंजन की भूमिका निभा रही हैं। उनके पिता अनुज सक्सेना की भूमिका में पंकज त्रिपाठी हैं। फिल्म का निर्माण करण जौहर कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान पंकज और जाह्नवी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ऑन स्क्रीन पिता-पुत्री की भूमिका निभाने से पहले दोनों ने किरदारों की तैयारी एक साथ की थी। जाह्नवी अक्सर पंकज के साथ अपने सीन की तैयारी के लिए उनके घर जाती थीं और देर रात तक तैयारी करती थीं। इस दौरान उनके खाने-पीने का ध्यान पंकज की पत्नी मृदुला रखती थीं। पंकज ने बताया, 'जाह्नवी बहुत टैलेंटेड हैं। अपने किरदार की तैयारी को लेकर कड़ी मेहनत करती हैं। गुंजन की बायोपिक के दौरान मुझे काम के प्रति उनका समर्पण देखने को मिला। फिल्म में वह मेरी बेटी की भूमिका निभा रही हैं। वह किरदार की तैयारी के लिए मेरे घर आती थीं। हम घर का बना खाना भी खाते थे। हम तब तक अपनी लाइनों का रिहर्सल करते थे, जब तक जाह्नवी संतुष्ट न हो जाएं। मुझे यकीन है कि जाह्नवी फिल्मी दुनिया में लंबा सफर तय करेंगी।'

नॉन-स्टॉप काम करके भी थकान महसूस नहीं करतीं श्रद्धा

अभिनत्री श्रद्धा कपूर कहती हैं कि उन्हें लगातार काम करने से थकान नहीं होती, बल्कि वे काम के हर पल का आनंद लेती हैं। श्रद्धा इन दिनों एक साथ कई फिल्मों में नॉन-स्टॉप काम कर रही हैं। पिछले 20 दिनों से वह एक साथ कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग के लिए भाग-दौड़ कर रही हैं। हैदराबाद में 'साहो' की शूटिंग के बाद वह 'स्ट्रीट डांसर 3डी' के लिए दुबई गईं। दुबई से इस्तांबूल और फिर वापस लौटीं। लेकिन इसके बाद भी रुकी नहीं। कुछ घंटों बाद ही उन्होंने 'साहो' के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया। अपने इस शूटिंग शेड्यूल को लेकर वह कहती हैं, 'यह बहुत ही क्रेजी समय है। मुझे लगता है, जब तक मैं अपनी पूरी नींद ले लेती हूं और मेडीटेट कर लेती हूं, तब तक मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकती हूं। मैं हर पल का मजा लेती हूं, क्योंकि यह मुझे थकाने से ज्यादा आनंद देता है। हां, कभी-कभी थोड़ी थकावट होती है।'

अगले साल ईद पर टकराएंगे सलमान और अक्षय कुमार

ईद पर सलमान खान अभिनीत 'भारत' रिलीज हो चुकी है। अगली ईद की भी उन्होंने बुकिंग कर ली है। संजय लीला भंसाली निर्देशित 'इंशाअल्लाह' अगले साल ईद पर रिलीज होगी। उसमें सलमान खान के साथ आलिया भट्ट होंगी। दोनों पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे। जबकि अक्षय कुमार और कट्रीना कैफ अभिनीत 'सूर्यवंशी' को अगले साल ईद पर रिलीज करने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। गत मार्च में रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म का एक लुक साझा किया था। फिल्म में अक्षय एटीएस अधिकारी की भूमिका में हैं। 'सिंघम' और 'सिंबा' की सफलता के बाद रोहित अपनी पुलिस की दुनिया का विस्तार 'सूर्यवंशी' में कर रहे हैं। वहीं सलमान खान करीब बीस साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम करेंगे। दोनों ने वर्ष 1999 में 'हम दिल दे चुके सनम' में आखिरी बार फिल्म में एक साथ काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी।

सावधान

वैज्ञानिकों ने चेताया कि इंटरनेट में हद से ज्यादा समय बिताने से एकाग्रता होती है भंग, किसी कार्य पर फोकस करने में भी आती हैं दिक्कतें

दिमाग पर असर डालता है इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल

- वर्ल्ड साइकियाट्री जर्नल में प्रकाशित हुआ अध्ययन
- इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग हमारी याददाश्त और व्यवहार को प्रभावित करता है

प्रतीकात्मक

मेलबर्न, प्रेट्र : हमेशा से कहा जाता रहा है कि किसी चीज का उपयोग सीमा में हो तो फायदेमंद, लेकिन अगर सीमा से ज्यादा हुआ तो नुकसानदेह हो सकता है। इंटरनेट के बारे में भी यही नियम लागू होता है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को सुलभ जरूर बना दिया हो लेकिन उस पर ज्यादा समय बिताना खतरनाक हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में किए गए एक अध्ययन में यह बताया गया है कि इंटरनेट का हद से ज्यादा उपयोग हमारे मस्तिष्क में बदलाव लाता है जो हमारे ध्यान, याददाश्त, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है।

वर्ल्ड साइकियाट्री जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन में दावा किया गया कि इंटरनेट हमारी चेतना के एक विशिष्ट दायरे में लगातार और तेज परिवर्तन करता है जोकि मस्तिष्क में बदलाव का कारण बनता है। अब शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि हमारी चेतना की प्रक्रिया को बदलने में इंटरनेट किस तरह से भूमिका निभाता है।

ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के जोसेफ फर्थ ने बताया कि इस अध्ययन से जो मुख्य बात सामने आती है वह यह है कि इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल से मस्तिष्क के कई हिस्से प्रभावित होते हैं। ऑनलाइन दुनिया तथ्यों और सूचनाओं का बहुत बड़ा भंडार है। जिसको पाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इंटरनेट की तमाम सूचनाएं और संकेत हमारे ध्यान को लगातार विभाजित रखते हैं जो हमें एक कार्य पर एकाग्रता बनाए रखने के लिए हमारी क्षमता को कम कर सकती है।

ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि इंटरनेट के प्रभावों पर अधिकतर शोध अभी केवल वयस्कों पर ही किए गए हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर भी इस तरह के शोध की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेट मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली दोनों को बदलने की क्षमता रखता है।

डब्ल्यूएचओ ने भी चेताया : विश्व स्वास्थ्य संगठन 2018 के दिशा-निर्देश के अनुसार छोटे बच्चों (2-5 वर्ष की आयु) को दिन में केवल एक घंटे या उससे भी कम स्क्रीन के संपर्क में रहना चाहिए। परिजनों को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे बहुत अधिक समय डिजिटल प्लेफार्म पर न बिताएं, जिससे की उनकी फिजिकल एक्टिविटी, सामाजिक संपर्क न बाधित हो। अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बच्चे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम खेलें बाहरी शारीरिक गतिविधियां ज्यादा करें, जितना संभव हो सके खुद भी बच्चों के साथ खेलें। इससे उनका संपूर्ण विकास होगा।